R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 20 । अंक : 01
01 से 15 अक्टूबर 2021
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

उपचुनाव से तय होगा मध्य प्रदेश का राजनीतिक भविष्य!

शिवराज सिंह या कमलनाथ
किसकी बढ़ेगी ताकत ?

भाजपा और कांग्रेस दोंनो जुटे
मिशन 2023 की तैयारी में...

अल्ट्राटेक
सीमेंट
इंजीनियर की पसंद
देश का नं.1 सीमेंट
घर है आपकी पहचान
बनाइये इसे देश के नं.1 सीमेंट से
घर है आपकी पहचान। इसलिए जब इरादा हो खुद का घर बनाने का, तो चुनिए सिर्फ़ देश का नं.1 सीमेंट, अल्ट्राटेक।
इसके अल्ट्राटेक बाइंडिंग पार्टिकल्स ईंटों से सरियों तक जोड़कर आपके घर को दे बेजोड़ मज़बूती।
www.ultratechcement.com
facebook.com/ultratechcementlimited
twitter.com/ultratechcement
1800 210 3311
'अल्ट्राटेक, देश का नं.1 सीमेंट' – क्लेम के विवरण के लिए ultratechcement.com पर विज़िट करें।

इस अंक में

प्रशासनिक

9 | जगी प्रमोशन की आस...

मप्र के करीब 1.50 लाख सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन मिलने की आस एक बार फिर से जगी है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने जहां मंत्री समूह का गठन किया है, वहीं प्रमोशन में आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट 10 अक्टूबर...

राजपथ

10–11 | मिशन-2023 के मोर्चे पर संघ

भाजपा ने 6 माह में 3 राज्यों में 4 मुख्यमंत्री बदल डाले हैं। इससे कई राज्यों में असंतोष की खबरें हैं। इन खबरों के बाद संघ ने स्वयंसेवकों को जनता के बीच जाकर भाजपा सरकार और संगठन के प्रति लोगों की मंशा...

मुद्दा

14 | अफसरों पर शिवराज कठोर क्यों?

इन दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ कड़क नजर आ रहे हैं। खासकर उनके निशाने पर नौकरशाह हैं। जाना जा रहा है कि मंत्रियों, विधायकों और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार शिकायत पहुंच रही है कि मैदान में पदस्थ अफसर ठीक...

कैंपस

15 | 18 माह में पढ़ाई चौपट

मप्र में 18 महीने बाद स्कूल खुल गए हैं। लेकिन पढ़ाई पूरी तरह चौपट हो गई है। दूसरी कक्षा के बच्चे को कुछ याद ही नहीं है। वहीं पांचवीं के बच्चे हिंदी की किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं। दरअसल, स्कूल बंद होने के कारण यह स्थिति निर्मित हुई है। भारत दुनिया में सबसे लंबे...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

मप्र में 2 साल बाद विधानसभा चुनाव होना है। भाजपा और कांग्रेस अभी से मिशन 2023 की तैयारी में जुट गई है। लेकिन इससे पहले एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। वैसे तो इन उपचुनावों का सत्ता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इनके परिणाम मप्र का राजनीतिक भविष्य जरूर तय करेंगे। इन चारों सीटों के परिणाम जिनके पक्ष में जाएंगे, वह पार्टी 2023 के मोर्चे पर और उत्साह दिखाएगी। इसलिए इन उपचुनावों का महत्व बढ़ गया है।

राजनीति

30–31 | रीजनल स्टार दमदार

भारत अब दो तरह के मुख्यमंत्रियों का देश बन गया है। एक वे हैं जो क्षेत्रीय दलों के उभरते सितारे हैं और हर चुनाव के साथ राजनीति पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। दूसरी तरह के मुख्यमंत्री वे हैं जो दो बड़े राष्ट्रीय दलों के अस्थायी प्रादेशिक चेहरे हैं और जिनकी हुकूमत अपने...

महाराष्ट्र

35 | गुल खिलाने वाली दोस्ती

दोस्ती में मजाक भी खूब चलता है और उद्धव ठाकरे ने भी भाजपा नेता राव साहब दानवे को लेकर अपने बयान को मजाक बता दिया है, लेकिन उनका मजाक बताना भी डिस्क्लेमर जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उद्धव ठाकरे बचाव के लिए किसी व्यावहारिक रास्ते के तकनीकी लूप-होल...

बिहार

38 | लालू भरोसे पीएम मटेरियल

नीतीश कुमार की छटपटाहट स्वाभाविक है। जेडीयू नेताओं के बीच पीएम मटेरियल समझे जाने के बावजूद नीतीश कुमार अपनी हदों की हकीकत भी समझते हैं- और हालात को बदलने की कोशिश में कोई कसर भी बाकी नहीं रखते, लेकिन राजनीतिक...

6-7 अंदर की बात
40 पड़ोस
41 विदेश
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

कागज पर 100 फीसदी टीकाकरण!

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता की पंक्तियां हैं...

क्या खोया, क्या पाया जग में, मिलते और बिछुड़ते मग में,
मुझे किसी से नहीं शिकायत यद्यपि छला गया पग-पग में.

ये पंक्तियां अनायास नहीं लिखी गई होंगी, बल्कि इसके पीछे कोई न कोई स्थिति और परिस्थिति रही होगी। जैसी इस समय कोरोना टीकाकरण को लेकर बनी है। वैक्सीनेशन को लेकर देश-प्रदेश में तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में मप्र में दावा किया गया कि यहां फर्स्ट डोज का 100 फीसदी टीकाकरण हो गया है। लेकिन ये सब जानते हैं कि ये आंकड़े हैं आंकड़ों का क्या? आज भी प्रदेश में ऐसे पात्र हजारों लोग हैं, जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है। या तो वे लोग वैक्सीनेशन लगाने में रूचि नहीं ले रहे हैं या फिर प्रशासन उन तक पहुंच नहीं पाया है। ऐसे लोगों में घुमक्कड़ जातियों के लोग बहुतायत में हैं। फिर भी अफसरों ने 100 फीसदी टीकाकरण का दावा कर दिया है। ये दावे भले ही कुछ समय के लिए हमें खुश कर दें, लेकिन ये खतरनाक हो सकते हैं। गौरतलब है कि अभी कोरोना पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। रोज आ रहे आंकड़े कभी डराते हैं तो कभी रुलाते हैं। पिछले करीब डेढ़ साल से दुनिया महामारी की चुनौती से जूझ रही है। इसका सामना करते हुए न सिर्फ लोगों को इससे बचाने के ठोस उपायों पर लगातार काम चल रहा है, बल्कि बचाव के जरूरी इंतजाम के साथ जनजीवन को सामान्य बनाने की भी कोशिश चल रही है। बहुत सारे देशों ने कोरोना विषाणु के संक्रमण को काबू करने के उपायों के साथ-साथ आर्थिक और दूसरी सार्वजनिक गतिविधियों को धीरे-धीरे सहज बनाने की ओर कदम उठाए हैं। खासतौर पर जबसे कोरोना विषाणु से बचाव का टीकाकरण चल रहा है, तब से एहतियात की हिदायतों के साथ कई स्तर पर राहतें भी दी गई हैं, ताकि लोग अब भविष्य की ओर बढ़ सकें। ऐसे में टीकाकरण के कागजी आंकड़ें खतरनाक साबित हो सकते हैं। पहली मुश्किल यह है कि दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों, दुर्गम इलाकों और बड़े शहरों की मलिन बस्तियों में टीकाकरण करने वालों की संख्या नाकाफी है। हम तकरीबन 20 फीसदी जगहों पर इस कमी का सामना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 90 फीसदी से अधिक स्थानों पर डाटा को लेकर भी तमाम तरह की समस्याएं हैं। जैसे, धीमी इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण कंप्यूटर सिस्टम में टीकाकरण के लिए प्रत्येक व्यक्ति की जानकारियों को दर्ज करना एक मुश्किल काम है। टीका लेने आए लोगों के दस्तावेजों की जांच करना, उनका पंजीकरण करना और फिर तमाम सूचनाओं को कंप्यूटर में लिखना, वह भी धीमी इंटरनेट के साथ, एक ऐसी प्रक्रिया हो जाती है, जिसमें टीकाकरण के बजाय आंकड़ों को जांचना व संभालना ही मूल काम बन जाता है। इन आंकड़ों को दर्ज करने वाले दक्ष हाथों का भी अभाव है, इसलिए टीका लगाने वालों को ही यह काम भी करना पड़ता है, जिससे टीकाकरण करने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है। असल में, टीकाकरण अभियान में अंतर्निहित सोच यह है कि लोग अपनी मर्जी से आएंगे और टीका लगवाएंगे। लोगों तक व्यवस्थित रूप से पहुंचने के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना होगा। हालांकि, पहले के कुछ महीनों में ही यह जाहिर हो गया था कि यह एक दोषपूर्ण व्यवस्था है। लोगों तक टीके पहुंचाने के लिए व्यवस्थित, लगातार और बड़े पैमाने पर प्रयास करने होंगे। इसीलिए निवास स्थान और आबादी की सही जानकारी न होने से अराजकता पैदा हो रही है। इसकी गवाही यह आंकड़ा भी दे रहा है कि दूसरी खुराक जितने लोगों को मिल जानी चाहिए थी, उनमें करीब 25 फीसदी अब भी इससे दूर हैं।

- राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 20, अंक 1, पृष्ठ-48, 1 से 15 अक्टूबर, 2021

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
मुंबई :- ऋतेन्द्र माथुर, **कोलकाता:**- इंद्रकुमार,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, टी.पी. सिंह, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (विदिशा) ज्योत्सना अनूप यादव

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी-फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : 39 श्रुत्रि सिलटर निपानिया, इंदौर मोबाइल - 7000123977

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

बाघों की चिंता

मप्र में को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है, लेकिन बाघों की मौत भी चिंताजनक है। ज्यादातर बाघों की मौत का कारण क्षेत्र को लेकर लड़ाई है। प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ी है तो क्षेत्र को लेकर लड़ाई लाजमी है। प्रदेश सरकार को बाघों की मौत को रोकने के लिए प्रयास करना होगा।

● **पृथ्वी सिंह,** राजगढ़ (म.प्र.)

मप्र निवेशकों की पसंद

मप्र हमेशा से निवेशकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। लेकिन कोरोना संक्रमणकाल में देशभर में सबसे अधिक निवेशकों ने मप्र का रुख किया। सरकार भी पूरे प्रयास कर रही है कि बड़े से बड़े निवेशक मप्र की ओर रुख करें। जिससे मप्र की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके।

● **सुरेंद्र कशेरिया,** इंदौर (म.प्र.)

गड्ढों में सड़क

भाजपा शासनकाल में संभवत पहली बार बारिश से जिस तरह सड़कों की हालत खस्ता हुई है ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं रही। प्रदेश में दूरदराज के अंचलों को छोड़िए राजधानी और बड़े शहरों की सड़कें ही चलने लायक नहीं हैं। पता ही नहीं लगता है, सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क।

● **दीपेंद्र ठाकुर,** भोपाल (म.प्र.)

धमाकेदार होगा 2024 का चुनाव

2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष ही नहीं सत्तारूढ़ भाजपा भी चिंतित है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद ममता बनर्जी विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा बनकर उभरीं। इसी को देखते हुए भाजपा आने वाले चुनाव को लेकर चिंतित दिख रही है। ममता बनर्जी लगातार अन्य विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। संभावना जताई जा रही है कि टीएमसी और कांग्रेस के एक होने के बाद भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक चुनौती खड़ी की जा सकती है। हालांकि, इस खिचड़ी विपक्ष बनाने की राह में अभी भी राष्ट्रीय स्तर से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक कई रोड़े हैं। दूसरी तरफ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी उठापटक कर रही हैं।

● **कार्तिक शर्मा,** ग्वालियर (म.प्र.)

वोटरों को लुभाने में जुटीं पार्टियां

कांग्रेस को मजबूत होने के लिए अब आदिवासी वर्ग का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं भाजपा भी ओबीसी और आदिवासी वोटरों को साधने में लगी है। मप्र में पिछले तीन दशक के आंकड़े बताते हैं कि आदिवासी वर्ग ने जिधर करवट ली है, उधर का पलड़ा भारी रहा है। बीते दिनों विधानसभा सत्र के दौरान आदिवासी मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधने से लेकर कमलनाथ की आदिवासी अधिकार यात्रा तक इसी कवायद का हिस्सा है। आने वाले दिनों में कांग्रेस मप्र में आदिवासी मुद्दों को लेकर सरकार पर आक्रामक हो सकती है।

● **जाकिर हुसैन,** नई दिल्ली (म.प्र.)

अमेरिका पीछे क्यों हटा?

अफगानिस्तान में पिछले 40 सालों से आतंकवाद जारी है। पहले रूस ने वहां तख्ता पलट कर शासन हथियाया। रूस को वहां से खदेड़ने में अमेरिका ने आतंकवादी संगठनों की भरपूर मदद की। बाद में फौजी ताकत का इस्तेमाल और भारी धन निवेश करके अफगानिस्तान में एक तरह से कब्जा कर लिया। बीस साल तक फौज और अकूत धन के सहारे वहां टिका रहा। इस सब के बाद भी जब दाल नहीं गली तो वहां से निकलने में ही अपनी खैर समझी।

● **रोहित कुमार,** सीहोर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

रावत का कद बढ़ा, देवेंद्र की होगी विदाई

पंजाब कांग्रेस का एपिसोड समाप्त होने के साथ ही अब खबर है कि उत्तराखंड कांग्रेस में चल रहे बड़े नेताओं के घमासान पर पार्टी आलाकमान सख्त रुख अपनाने जा रहा है। चर्चा गर्म है कि 'मिशन पंजाब' को सफलतापूर्वक अंजाम देने में कामयाब रहे पार्टी महासचिव हरीश रावत का कद पार्टी के भीतर खासा बढ़ गया है। सूत्रों की मानें तो अब रावत पंजाब के प्रभार से मुक्त हो उत्तराखंड में कुछ माह बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ऊर्जा लगाने जा रहे हैं। खबर जोरों पर है कि रावत ने उत्तराखंड की बाबत पार्टी नेतृत्व संग लंबी वार्ता कर उन्हें राज्य की जमीनी हकीकत और प्रदेश कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी से हो रहे नुकसान को तुरंत रोकने के लिए एक फॉर्मूला सुझाया है। इस फॉर्मूले पर जल्द ही पार्टी आलाकमान का फैसला सामने आ सकता है। जानकारों का दावा है कि पार्टी नेतृत्व राज्य के वर्तमान प्रभारी देवेंद्र यादव के स्थान पर किसी नए चेहरे को लाने का मन बना चुका है। बहुत संभव है कि पूर्व में प्रदेश की प्रभारी रह चुकी अंबिका सोनी को यह दायित्व सौंपा जाए। खबर यह भी है कि रावत ने आलाकमान को भाजपा के दो विधायकों की बाबत भी सूचित किया है जो पाला बदल कांग्रेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं। इनमें से एक विधायक रावत के मुख्यमंत्री काल में हुई बगावत के दौरान भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं में से एक हैं।

स्टालिन की बढ़ती लोकप्रियता

तमिलनाडु की राजनीति में पिछले कई दशकों से अन्नाद्रमुक और द्रमुक का कब्जा रहा है। दोनों ही दलों के मध्य सत्ता को लेकर चलने वाले संघर्ष ने कई बार राज्य की कानून व्यवस्था को खतरे में डालने का काम किया है। हालात इतने तनावपूर्ण इन दलों के मध्य रहते आए हैं कि जो भी दल सत्ता में आता वह दूसरे के खिलाफ नाना प्रकार की जांचें शुरू कर बदले की कार्यवाही करने लगता। लेकिन अब यहां हालात बदलते नजर आ रहे हैं। राज्य की कमान द्रमुक नेता स्टालिन के हाथों में आते ही प्रतिशोध की राजनीति थमती नजर आने लगी है। स्टालिन ने कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम शुरू किया। इसके लिए उन्होंने अन्नाद्रमुक के नेताओं को भी अपनी टीम में शामिल कर सबको चौंका दिया था। अब स्टालिन ने अपनी पूर्ववर्ती डीएमके सरकार द्वारा राज्यभर के स्कूली बच्चों में मुफ्त वितरित किए जाने वाले 60 लाख स्कूली बस्तों की बाबत एक निर्णय ले सभी का दिल जीत लिया है। इन स्कूली बस्तों में अन्नाद्रमुक की संस्थापक स्वर्गीय जयललिता एवं पूर्व मुख्यमंत्री पलानीस्वामी की तस्वीरें छपी हैं। राज्य के नौकरशाहों का मानना था कि सरकार बदलने के बाद इन बस्तों को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा क्योंकि इनमें अन्नाद्रमुक नेताओं की फोटो छपी है।

ममता का बढ़ता जलवा

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाजपा को एक के बाद एक झटका देने में जुटी हुई हैं। गत सप्ताह पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को तृणमूल में शामिल करा दीदी ने भाजपा नेताओं को सकते में डाल दिया। इससे पहले पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहते मुकुल राय भी यकायक ही तृणमूल में शामिल हो भाजपा को तगड़ा झटका दे चुके हैं। कोलकाता के राजनीति गलियारों में बड़ी चर्चा है कि 77 सदस्यीय भाजपा विधान दल में दीदी जल्द ही बड़ी तोड़-फोड़ मचाने जा रही हैं। गौरतलब है कि चुनावी जीत के तुरंत बाद से ही भाजपा छोड़ तृणमूल में शामिल होने के लिए भाजपा विधायकों की लाइन लगनी शुरू हो गई है। सबसे पहले विधायक विश्वजीत दास ने पार्टी छोड़ी, उनके बाद एक अन्य विधायक सौमन रॉय ने भी पार्टी छोड़ तृणमूल ज्वाइन कर डाली। अब तक सात विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। खबर है कि दीदी के संपर्क में इस समय 10 से 15 भाजपा विधायक हैं जो कभी भी पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। खबर यह भी जोरों पर हैं कि त्रिपुरा भाजपा में भी तृणमूल बड़ी सेंधमारी करने जा रही है। बताया जा रहा है कि ममता के इन आक्रामक तेवरों के चलते भाजपा के भीतर भारी खलबली मची हुई है।

गुजरात में भाजपा बैकफुट पर

भले ही गुजरात में भाजपा आलाकमान ने पूरी की पूरी सरकार बदल डाली हो, विजय रूपाणी सरकार के प्रति उपजा जनता का आक्रोश यथावत बताया जा रहा है। खबर जोरों पर है कि भूपेंद्र पटेल जैसे नौसिखिए राजनेता को मुख्यमंत्री बना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य भाजपा के कई दिग्गजों को खासा खफा कर डाला है। जानकारों का मानना है कि राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदी बेन पटेल का इस उलटे-फेर में बड़ा हाथ रहा है। गुजरात की राजनीति समझने वालों की मानें तो आनंदी बेन पटेल और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के रिश्ते मोदी के मुख्यमंत्रित्वकाल से ही तनावपूर्ण रहते आए हैं। आनंदीबेन के स्थान पर अपनी पसंद के विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री बनाने वाले अमित शाह का इस बार हुए आमूल-चूल परिवर्तन में खास रोल नहीं बताया जा रहा है। पूरा खेल प्रधानमंत्री मोदी के स्तर पर खेला गया। भूपेंद्र पटेल आनंदी बेन के खास हैं। उनके कैबिनेट में शामिल अधिकांश मंत्री भी आनंदी बेन के करीबी बताए जा रहे हैं।

कमजोर पड़ रहे दुष्यंत चौटाला

हरियाणा की राजनीति में जल्द ही बड़ा भूचाल आने की चर्चा जोर पकड़ रही है। राज्य में भाजपा और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन सरकार है। खबर है कि जजपा भीतर पार्टी सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला की कार्यशैली को लेकर पार्टी नेताओं में असंतोष तेजी से बढ़ रहा है। जानकारों का दावा है कि दुष्यंत चौटाला का पूरी तरह भाजपा परस्त होना पार्टी विधायकों के लिए बड़ी चिंता का कारण बन चुका है। विधायकों को सबसे बड़ी मुसीबत किसान आंदोलन के चलते आ रही है। हरियाणा सरकार किसान आंदोलन को दबाने के लिए जिस प्रकार पुलिस दमन का सहारा ले रही है उससे पार्टी के खिलाफ राज्यभर में जबरदस्त असंतोष का माहौल है। रही सही कसर इंडियन नेशनल लोकदल के नेता ओम प्रकाश चौटाला के जेल से बाहर आ राजनीति में सक्रिय होने से पूरी कर दी है। इनेलो प्रमुख पूरे राज्य का दौरा कर अपनी पार्टी को मजबूती देने में जुटे हैं। उनकी सक्रियता के चलते जजपा बैकफुट पर है।

एक तो करेला... ऊपर से नीम चढ़ा

यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि एक तो करेला... ऊपर से नीम चढ़ा। ऐसा ही कुछ इन दिनों प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में हो रहा है। दरअसल, एक विभाग में कुछ ऐसी महिला आईएएस पदस्थ हो गई हैं, जो अपनी करतूतों के लिए ख्यात रही हैं। तथाकथित तेज तर्रार इन महिला अफसरों को विभाग में इसलिए पदस्थ किया गया था कि इससे विभाग के कार्यों में गति आएगी। लेकिन इन महिलाओं ने विभाग में पदस्थापना के साथ ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। इन महिला अधिकारियों के रंग से विभाग के प्रमुख सचिव बदरंग हो रहे हैं। दरअसल, विभाग प्रमुख इन महिला अधिकारियों से आजीज आ चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि विभाग की गतिविधियों के लिए प्रमुख सचिव महोदय जब भी मीटिंग बुलाते हैं विभाग में पदस्थ सभी महिला अधिकारी समय पर नहीं पहुंचती हैं। इस कारण साहब को उनका इंतजार करना पड़ता है। कभी-कभी तो स्थिति यह निर्मित हो जाती है कि वे मीटिंग में पहुंचती भी नहीं हैं। साहब उन महिला अधिकारियों का भूतकाल अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए वे उनके साथ सख्ती भी नहीं बरतते हैं। गौरतलब है कि इन महिला अधिकारियों में से एक ने एक नेताजी को थप्पड़ जड़ दिया था। वहीं अन्य महिला अधिकारियों का भी हाल कुछ ऐसा ही रहा है। इसलिए साहब इन महिलाओं की मनमानी मन मारकर बर्दाश्त कर रहे हैं।

मुफ्त का चंदन... घिस मेरे नंदन

उपरोक्त कहावत की तरह खेलकूद अकादमी में बजट का उपयोग किया जा रहा है। दरअसल, सूत्रों का कहना है कि विभाग में किसी अफसर की नहीं चल रही है। विभाग की मंत्री जो चाहती हैं वही होता है। अभी हाल ही में उन्होंने अपनी पसंद का डायरेक्टर रख लिया है अब मनमाने तरीके से कोच और डायटीशियन पर बजट स्वाहा किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि कई कोच तो ऐसे हैं, जिनको 20-25 लाख रुपए मासिक का वेतन दिया जा रहा है। ये कोच अकादमी में आते हैं कि नहीं ये किसी को नहीं पता, लेकिन उनका वेतन निरंतर उनके पास पहुंच रहा है। इसी तरह अकादमी में इन दिनों न्यूट्रीशियन और डायटीशियन को भी बड़े वेतन पर रखा गया है। 2-2.5 लाख रुपए के वेतन पर रखी गई डायटीशियन कब आती हैं, कब नहीं यह उनकी मर्जी पर निर्भर है। विभाग के अधिकारी परेशान हैं कि आखिरकार खेलकूद को बढ़ावा देने वाले इस विभाग में इस तरह की फिजूल खर्ची किसलिए की जा रही है। लेकिन किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वे विभागीय मंत्री से इस मामले में सवाल-जवाब कर सके। अब देखना यह है कि मुफ्त का चंदन कब तक घिसा जाएगा।

साहब का अजब-गजब शौक

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों एक राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी का शौक चर्चा में बना हुआ है। साहब वर्तमान में पुलिस अधीक्षक के पद पर हैं। इसलिए उनका रसूख भी बड़ा है। उनके रसूख के कारण उनके आसपास तितलियां मंडराती रहती हैं। सूत्रों का कहना है कि साहब इन दिनों पुलिस विभाग की ही एक तितली यानी एक महिला पुलिस अधिकारी पर मेहरबान हो गए हैं। आलम यह है कि उक्त साहब अक्सर महिला अधिकारी के साथ देख जाते हैं। यहां तक तो सबकुछ ठीक था, लेकिन विगत दिनों कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि साहब के इस अजब-गजब शौक ने प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में भूचाल ला दिया। दरअसल, साहब जिस महिला अधिकारी पर मेहरबान थे, उस महिला अधिकारी पर एक आरक्षक भी फिदा हो गया। सूत्र बताते हैं कि उक्त आरक्षक साहब की तितली को पकड़ने की कोशिश करने लगा। मामला यहां तक बिगड़ गया कि आरक्षक की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए साहब के बंगले पर क्राइम ब्रांच के जवानों ने आरक्षक की धुनाई कर दी। आरक्षक भी कहां मानने वाला था। उसने भी मोर्चा खोल लिया और मामला थाने से होते हुए मीडिया के पास पहुंच गया। उधर, पूरे घटनाक्रम पर विराम लगाने के लिए उक्त आरक्षक को अनैतिक तरीके से वीडियो बनाने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। आरोप है कि आरक्षक 5 लाख रुपए मांग रहा था। उधर, लोगों का कहना है कि साहब अभी भी अपने शौक पर विराम लगाते नहीं दिख रहे हैं।

मंत्रीजी को लौटानी पड़ी रकम

प्रदेश में सरकार जीरो टॉलरेंस का नारा बुलंद किए हुए है। सरकार की मंशा को भांपते हुए लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू निरंतर भ्रष्टों के खिलाफ छापामार कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन विडंबना यह दिखी कि सरकार की नाक के नीचे ही लेनदेन का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। दरअसल, प्रदेश सरकार में कांग्रेस से आए कुछ विधायक जो मंत्री बने हैं उनके नाते-रिश्तेदार और खुद मंत्रीजी कमाई में जुटे हुए हैं। ऐसे ही एक मंत्रीजी इन दिनों खूब चर्चा में हैं। मंत्रिमंडल के सबसे बुजुर्गवार ये मंत्रीजी कमाई का कोई भी मौका नहीं चूक रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि पिछले दिनों उन्होंने एक ठेकेदार से 13 लाख रुपए ले लिए थे, लेकिन ठेकेदार का काम नहीं हो पाया। बताया जाता है कि यह बात प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया तक पहुंच गई। फिर क्या था, प्रशासनिक मुखिया ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और मंत्रीजी से ठेकेदार को 13 लाख रुपए वापस दिलवाए। उधर, चर्चा यह भी है कि आखिरकार ये बात प्रशासनिक मुखिया तक कैसे पहुंची और उन्होंने इस मामले में इतनी रूचि क्यों ली।

यह कैसा सवाल... ?

इन दिनों प्रदेश सरकार के मुखिया को पर्यावरण की चिंता सबसे अधिक सता रही है। आश्चर्यजनक बात है कि प्रदेश के पर्यावरण को सुधारने के लिए उन्होंने पूरा भार अपने ऊपर ले लिया है और रोजाना पौधारोपण कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि उनके रोजाना के पौधारोपण कार्यक्रम में प्रोटोकाल के कारण अमला तो पूरा जुटता है लेकिन पौधा एक ही लगाया जाता है। इस दौरान कई बार एक ऐसा वाक्या सामने आया है जब सरकार के मुखिया कलेक्टर से लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पूछते हैं। जबकि उस दौरान वहां डीआईजी भी मौजूद रहते हैं। लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार लॉ एंड ऑर्डर की जानकारी डीआईजी से न लेकर कलेक्टर से क्यों ली जा रही है। यहां बता दें कि कलेक्टर और डीआईजी सरकार के दूसरे नंबर के मंत्री जी के खासमखास हैं। एक तो रिश्तेदार हैं और दूसरे को वे ही यहां लाए हैं। फिर ऐसी क्या वजह है कि शासन के मुखिया कलेक्टर से वह जानकारी मांगते हैं जो डीआईजी के अधिकार क्षेत्र की होती है।

कांग्रेस आज इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसे टुकड़े-टुकड़े गैंग को जोड़ने की जरूरत पड़ रही है। जिन लोगों ने देश के खिलाफ आवाज उठाई है, कांग्रेस उन लोगों को पार्टी से जोड़ रही है। दरअसल, अब कोई भी अच्छा व्यक्ति कांग्रेस में नहीं जाना चाहता।

● **मुख्तार अब्बास नकवी**

वाकई पैसे में दम होता है। वरना कोई भी टीम भारत का दौरा निरस्त करके तो दिखाए। आतंकवाद के नाम पर न्यूजीलैंड ने मैच शुरू होने से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान का दौरा निरस्त कर पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश की है। इससे पाकिस्तान की साख गिरी है। लेकिन विषम परिस्थितियों में भी कोई देश भारत का दौरा निरस्त करने की हिम्मत नहीं जुटा सकता।

● **रमीज राजा**

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में केंद्र कोताही कर रहा है। अगर 2024 में महागठबंधन बिहार में 40 में से 39 सीटें जीतता है तो जो भी देश के प्रधानमंत्री होंगे, वह खुद पटना आकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा करेंगे। फिलहाल मौजूदा संसद में बिहार में 40 में से 39 सांसद एनडीए के हैं। फिर भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है।

● **तेजस्वी यादव**

रिश्वत का भी अपना गणित होता है। आटे में नमक बराबर रिश्वत चल सकती है। अगर कोई एक हजार रिश्वत लेता है तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सवा लाख के घर में 5-10 हजार की रिश्वत लेना गलत है।

● **रामबाई**

स्टेज पर रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बोलना आसान है, अपनी मेंशन से बाहर निकलिए, पोर्न की दुनिया से बाहर निकलिए तब आपको हकीकत पता चलेगी। आप टीवी पर शाष्टांग दंडवत प्रणाम करती हैं, उन कलाकारों को जिनकी कला से आप प्रभावित होती हैं। कृपया रील लाइफ से बाहर निकलकर रीयल दुनिया में जाकर पीड़ित महिलाओं को थोड़ी-बहुत सहानुभूति दिखाइए। यकीन मानिए, सारी दुनिया आपको शाष्टांग दंडवत करेगी।

● **शर्लिन चोपड़ा**

वाक्युद्ध

केंद्र सरकार ने किसानों के लिए वह सबकुछ किया है, जो 70 सालों के दौरान नहीं हुआ है। कृषि कानूनों को लाकर सरकार किसानों को खुशहाल बनाना चाहती है, लेकिन कुछ लोग अपना हित साधने के लिए आंदोलन पर उतर गए हैं। आंदोलन की वजह से लाखों लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। इसकी चिंता किसी को नहीं है।

● **संबित पात्रा**

भारत बंद को मिले देशव्यापी समर्थन से यह साबित हो रहा है कि केंद्र के तीनों कृषि कानून किसी को पसंद नहीं हैं। किसान कृषि कानूनों का विरोध केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश की जनता के लिए कर रहे हैं। क्योंकि किसानों पर पड़ने वाले भार का असर खाद्यान्न पर पड़ेगा। लेकिन सत्तारूढ़ दल को इसमें भी खोट नजर आती है।

● **राकेश टिकैत**

जगी प्रमोशन की आस...

मप्र के करीब 1.50 लाख सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन मिलने की आस एक बार फिर से जगी है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने जहां मंत्री समूह का गठन किया है, वहीं प्रमोशन में आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट 10 अक्टूबर को फैसला सुना सकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में गत दिनों सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मप्र सहित सभी राज्यों का पक्ष सुनने के बाद कहा कि इस मामले में अब आगे सुनवाई नहीं होगी। सभी राज्य 2 सप्ताह में अपना पक्ष लिखित में पेश करें। शीर्ष अदालत ने कहा कि 5 अक्टूबर से लगातार केंद्र और राज्य सरकार को आधा-आधा घंटा अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया जाएगा।

गौरतलब है कि प्रमोशन में आरक्षण का विवाद होने के कारण अभी तक करीब 80 हजार कर्मचारी बिना प्रमोशन रिटायर हो गए हैं। लेकिन राज्य कर्मचारियों को चार साल बाद भी प्रमोशन का रास्ता नहीं निकल पाया है। अब सरकार ने एक बार फिर प्रयास शुरू किए हैं। इसके लिए मंत्री समूह का गठन किया गया है। इस मंत्री समूह से कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ी हैं। वहीं नाराजगी यह है कि राज्य कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है जबकि राज्य प्रशासनिक सेवा और अखिल भारतीय सेवा के अफसरों के प्रमोशन में कोई रोक नहीं है। उन्हें समय पर प्रमोशन का लाभ दिया जा रहा है। मप्र में प्रमोशन का विवाद सुलझाने के लिए पहले भी प्रयास हुए थे। कमलनाथ सरकार के समय भी प्रमोशन के लिए मंत्री समूह गठित किया गया था। तत्कालीन सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री डॉ. गोविंद सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने कर्मचारी संगठनों को भी सुना था। उसी दौरान प्रमोशन के अभाव में उच्च पदनाम का फॉर्मूला तय हुआ था। विभागों को निर्देश दिए गए थे कि वे अपने-अपने स्तर पर कार्यवाही कर कर्मचारियों को उच्च पदनाम दें। विभाग इस पर अमल कर पाते इसके पहले ही सत्ता परिवर्तन हो गया और कमलनाथ सरकार का निर्णय फाइलों में दफन हो गया। हालांकि अब पुलिस महकमे में उच्च पदनाम देने का क्रम शुरू हुआ है। अन्य विभागों के कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं।

प्रमोशन में आरक्षण का नियम रद्द होने के बाद कर्मचारियों की नाराजगी को दूर करने के लिए चार साल पहले तत्कालीन शिवराज सरकार ने बीच का रास्ता निकालने के लिए प्रयास किए थे। इसके लिए सरकार ने नए नियम भी तैयार कर लिए थे, लेकिन सरकार के यह प्रयास सफल नहीं हो सके। कानूनी राय भी ली गई लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के कारण मामला अटक गया। कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए वर्ष 2018 में रिटायरमेंट एज 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। इससे कर्मचारियों का रिटायरमेंट तो रुक गया लेकिन इन दो सालों में भी प्रमोशन का कोई रास्ता नहीं निकाला जा सका।

मप्र में सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों की संख्या 5,54,991 है। इतने बड़े अमले की सबसे बड़ी नाराजगी प्रमोशन न होना है। इस कारण प्रमोशन के अभाव में लगभग 80 हजार कर्मचारी रिटायर हो गए हैं। वहीं लगभग 1.50 लाख कर्मचारी प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने प्रमोशन के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रमोशन नियम निरस्त किए जाने संबंधी हाईकोर्ट के निर्णय को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। कर्मचारियों को सशर्त प्रमोशन की पहल हुई। प्रस्ताव था कि यदि कोर्ट का निर्णय प्रमोशन के खिलाफ आया तो संबंधित कर्मचारी का डिमोशन कर दिया जाएगा। जिला अदालत कर्मचारियों के मामले में ऐसा ही हुआ। कमलनाथ सरकार के समय कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिलने का मामला सदन में भी गूंजा। तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने सरकार से कहा जब तक कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता नहीं निकलता तब तक अफसरों के भी प्रमोशन न हों। तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष प्रजापति ने प्रमोशन के लिए हाईपॉवर कमेटी का गठन किया। इसमें स्पीकर, मुख्यमंत्री सहित सत्ता और विपक्षी दल के विधायक शामिल रहे। लेकिन इस हाईपॉवर की कमेटी बैठक नहीं हो पाई। यानी समस्या आज भी जस की तस है।

प्रदेश में पदोन्नति नियम 2002 के तहत अधिकारियों-कर्मचारियों की पदोन्नति होती थी, लेकिन 2016 में उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी। दरअसल, अनारक्षित वर्ग की ओर से अनुसूचित जाति-जनजाति को दिए जा रहे आरक्षण की वजह से उनके अधिकार प्रभावित होने को लेकर हाईकोर्ट में 2011 में 24 याचिकाएं दायर की गई थीं। इनमें सरकार द्वारा बनाए मप्र पब्लिक सर्विसेज (प्रमोशन) रूल्स 2002 में एससी-एसटी को दिए गए आरक्षण को कठघरे में रखा गया था। मप्र हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को राज्य में एससी-एसटी वर्ग को प्रमोशन में आरक्षण देने के नियम को असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया था। तत्कालीन चीफ जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस संजय यादव की बेंच ने कहा है कि यह नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 व 335 के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र को दिए गए दिशा-निर्देश के खिलाफ है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के निर्देश दिए। ऐसे में अब पदोन्नति तभी हो सकती है, जब कोर्ट इसकी अनुमति दे। सरकार ने इसको लेकर कोर्ट से अनुरोध भी किया था पर अनुमति नहीं मिली। इससे सबसे ज्यादा नुकसान उन कर्मचारियों व अधिकारियों को हुआ, जो पिछले 5 साल में रिटायर हो गए।

● **सुनील सिंह**

2 साल बढ़ाई थी सेवानिवृत्ति की आयु

पदोन्नति में आरक्षण का मामला लंबित होने की वजह से अधिकारी-कर्मचारी पदोन्नत हुए बिना ही सेवानिवृत्त होते जा रहे थे। इसको लेकर सरकार के खिलाफ कर्मचारियों में नाराजगी भी थी। इसे देखते हुए शिवराज सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा कदम उठाते हुए सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 साल कर दी थी, जो अभी भी जारी है। सरकार नए पदोन्नति नियम का ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की समिति बनाई गई थी। समिति ने सभी पहलुओं पर विचार करने और विधि विशेषज्ञों से अभिमत लेने के बाद नए नियमों का मसौदा तैयार कर लिया है। अब इसे कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है, जिसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव भी भेज दिया है।

देश में विपक्ष की एकजुटता और कुछ राज्यों में भाजपा के नेताओं के बीच पनपे असंतोष के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत दो दिन के दौरे पर मप्र की व्यावसायिक राजधानी इंदौर आए थे और उन्होंने जनता से सत्ता और संगठन का फीडबैक लिया। संघ सूत्रों का कहना है कि संघ प्रमुख को सामाजिक, धार्मिक संगठनों, उद्यमियों के साथ ही युवाओं ने फीडबैक दिया कि प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार से पूरी तरह खुश है। बताते हैं कि मप्र से मिले फीडबैक को सुशासन का आधार बनाकर संघ अन्य राज्यों में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करेगा।

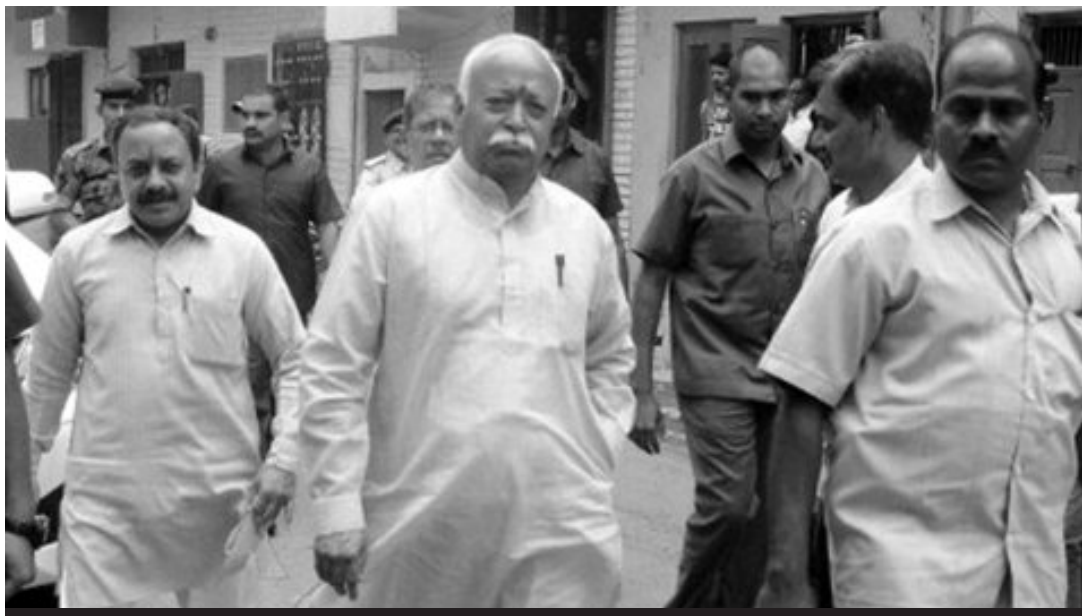

मिशन-2023 के मोर्चे पर संघ

भाजपा ने 6 माह में 3 राज्यों में 4 मुख्यमंत्री बदल डाले हैं। इससे कई राज्यों में असंतोष की खबरें हैं। इन खबरों के बाद संघ ने स्वयंसेवकों को जनता के बीच जाकर भाजपा सरकार और संगठन के प्रति लोगों की मंशा जानने के लिए सर्वे करने को कहा था। इसी संदर्भ में संघ के सर संघचालक डॉ. मोहन भागवत 21 और 22 सितंबर को दो दिवसीय प्रवास पर इंदौर आए थे। इस दौरान उन्होंने समाज के प्रबुद्धजनों से मुलाकात कर समाज पर सरकार के कामों का असर और उसकी छवि के बारे में फीडबैक लिया। वहीं संघ के अनुषांगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी अपनी रिपोर्ट सौंपी।

संघ सूत्रों का कहना है कि देश के साथ ही मप्र में भी महंगाई और बेरोजगारी मुख्य समस्या है, लेकिन सरकार की सक्रियता से ये समस्याएं विलोपित होती जा रही हैं। दरअसल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महंगाई से प्रभावित वर्ग के लिए सरकार का खजाना खोल रखा है। प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति दी गई है। वहीं हर जिले में रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। इससे बेरोजगारी की समस्या कमतर हो रही है। बताया जाता है कि संघ प्रमुख से मुलाकात के क्रम में प्रदेश के युवाओं ने फीडबैक दिया कि मप्र में सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए कई फोरम पर कार्य कर रही है। इस कारण मप्र की बेरोजगारी दर भी कम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के कम होते ही मप्र में रोजगार और अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार आने लगा है। यही कारण है कि अब प्रदेश में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय दर की तुलना में करीब आधी रह गई है। सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआई) की ताजा रिपोर्ट में मप्र में बेरोजगारी की दर 3.5 फीसदी है, जबकि राष्ट्रीय बेरोजगारी की दर 7.6 फीसदी है। प्रदेश में वर्ष 2021 के दौरान बेरोजगारी दर की अगर बात की जाए तो इस साल जनवरी में 6.2, फरवरी में 2.0, मार्च में 1.5, अप्रैल में 1.4, मई में 5.2, जून में 2.3, जुलाई में 2.3, अगस्त में 3.5 और सितंबर माह में भी 3.5 फीसदी रही है। यानी इस साल के 9 माह में अभी तक औसत बेरोजगारी की दर 3.1 फीसदी तक हुई है।

जानकारों का मानना है कि मप्र में अगस्त-सितंबर में बेरोजगारी की दर 3.5 फीसदी स्तर पर दूसरे राज्यों की तुलना में काफी कम है। जो प्रदेश सरकार के अर्थव्यवस्था के प्रबंधन की कुशलता को दर्शाती है और आर्थिक आशावाद का आधार है। कोरोना की प्रथम लहर में मई 2020 में प्रदेश की बेरोजगारी दर 22 फीसदी, राष्ट्रीय दर 21.7 फीसदी से अधिक रही थी। दूसरी लहर के जनवरी-सितंबर तीन तिमाही में यह औसतन 3.1 फीसदी रही। अगस्त-2021 एवं सितंबर-

संसदीय क्षेत्रों में संघ संभालेगा मोर्चा

मप्र में सत्ता और संगठन की सक्रियता के बावजूद संघ संसदीय क्षेत्रों में अभी से मोर्चा संभालेगा। इसकी वजह यह है कि संघ पूरी कोशिश में लगा है कि विपक्ष की एकजुटता के बावजूद लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए 400 से अधिक सीटें जीते। संघ के एक पदाधिकारी कहते हैं कि भाजपा के लिए अगला लोकसभा चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, यह तो गुजरात के मुख्यमंत्री को बदलने से ही स्पष्ट हो चुका है। दरअसल पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार ने भाजपा के आत्मविश्वास को ध्वस्त कर दिया है। इस कारण संघ की चिंता बढ़ी है। सूत्रों के अनुसार सत्ता और संगठन की सक्रियता के बाद भी भाजपा का जनाधार मजबूत करने के लिए संघ संसदीय क्षेत्रों में मोर्चा संभालेगा। संघ के सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनाव में स्वयंसेवकों ने जनता के बीच हजारों बैठकें की थीं।

2021 में यह 3.5 फीसदी रही है। ये अच्छे संकेत का द्योतक है। इससे आर्थिक कारोबार के लिए अच्छा वातावरण बनता है, जो विकास के लिए काफी आवश्यक है। कुल मिलाकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में रिकवरी हमें आगे ले जाएगी।

संघ प्रमुख को स्वयंसेवकों से मिले फीडबैक में यह भी कहा गया है कि प्रदेश में चौथी पारी संभालने के बाद से ही सत्ता और संगठन पूरी तरह चुनावी मोड में हैं। दरअसल, सरकार के साथ भाजपा संगठन भी कोराना संक्रमण के दौरान सक्रिय रहा। इससे जनता को आत्मबल मिला है। अब एक लोकसभा और 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के कारण सरकार और संगठन की सक्रियता और बढ़ गई है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। वहीं विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय कर दिया है। साथ ही सरकार अब जनता और विधायकों दोनों की सुविधा के लिए नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। हर विधायक के विधानसभा क्षेत्र के लिए एक डैश बोर्ड बनाया जा रहा है, जिसमें वहां की समस्याओं की शिकायत, मुद्दों की जानकारी और समाधान का ब्यौरा होगा। यह डैशबोर्ड सीधे मुख्यमंत्री के डैशबोर्ड से कनेक्ट होंगे। यानि विधायकों के विधानसभा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों की मॉनीटरिंग सीधे अब मुख्यमंत्री करेंगे। इसके जरिए मुख्यमंत्री की नजर विधायकों के कामकाज पर भी होगी। ये सब कुछ मुख्यमंत्री शिवराज के निर्देश पर हो रहा है। सीएम हेल्पलाइन सेवा में बड़ा बदलाव करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन को नए कलेवर में ढालने का ऐलान किया है। कई नई सुविधाओं को सीएम हेल्पलाइन से जोड़ा जाएगा। व्हाट्सएप **चैट बोर्ड** की सुविधा को भी तेजी के साथ अमल में लाने की तैयारी है। लोग व्हाट्सएप के जरिए शिकायतों का समाधान पा सकेंगे। साथ ही फोन कॉल के जरिए मिलने वाली सेवाओं को भी बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अब तक 44 विभागों की 560 सेवाओं को जोड़ा गया है। लेकिन सरकार अब इसे ऐसा बनाना चाहती है ताकि लोगों को इसका आसानी से फायदा मिले। सीएम हेल्पलाइन पर मिलने वाली शिकायतों के समाधान और जुड़े दस्तावेजों को अब सीधे घर तक पहुंचाने की भी तैयारी में सरकार है। इसके लिए 4 जिलों भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर को चुना गया है। लोगों को शिकायतों के समाधान और दस्तावेजों की जानकारी स्पीड पोस्ट के जरिए मिल सकेगी। स्पीड पोस्ट पर आने वाला खर्च संबंधित व्यक्ति को देना होगा। प्रदेश के लोक प्रबंधन मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया का कहना है कि सरकार सीएम हेल्पलाइन में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है ताकि लोगों को आसानी से इसका लाभ मिल सके। सीएम हेल्पलाइन में हर दिन हजारों की संख्या में शिकायतें मिलती हैं जिनका समाधान किया जाता है। लेकिन अब इन सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है और इसे प्रभावी बनाने की तैयारी है। ताकि कोई शिकायत पेंडिंग नहीं रहे। सीएम हेल्पलाइन की हर स्तर पर मॉनीटरिंग होगी और खुद मुख्यमंत्री शिवराज इसकी मॉनीटरिंग करेंगे। विभागों की जिम्मेदारी तय की जा रही है कि उनके विभाग से जुड़ी शिकायतों को पेंडिंग ना रखा जाए। जहां लापरवाही होगी वहां कार्रवाई की जाएगी। आने वाले दिनों में सीएम हेल्पलाइन में कई बड़े बदलाव किए जाएंगे। जैसे विधायकों के डैश बोर्ड बनाने की तैयारी है। इससे विधायकों के विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी शिकायतें और उनके समाधान की जानकारी भी उपलब्ध होगी। विधानसभा क्षेत्र में विधायक डैश बोर्ड तैयार होने पर स्थानीय लोग उस पर आवेदन अपलोड करने और अपने दस्तावेज हासिल करने के लिए आवेदन दे सकेंगे। हर एक विधानसभा क्षेत्र में बेहतर सेवा देने के लिए नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी है।

संघ प्रमुख को स्वयंसेवकों ने दी रिपोर्ट में कहा है कि इस बार भाजपा सरकार और संगठन से किसान भी खुश हैं और आदिवासी भी खुश हैं। वहीं ओबीसी वर्ग का भी झुकाव भाजपा की तरफ है। दरअसल, कोरोना संक्रमणकाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए सरकारी खजाना पूरी तरह खोल दिया था। वहीं आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य और मुफ्त में राशन व्यवस्था को दुरुस्त रखा था। इसका प्रभाव पड़ा है, जिससे किसान और आदिवासी खुलकर भाजपा के पाले में नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में किसान, आदिवासी और दलित वर्ग भाजपा से नाराज था।

● **कुमार राजेन्द्र**

विपक्ष के पास मुद्दा नहीं

स्वयंसेवकों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वर्तमान समय में मप्र में विपक्ष के पास भाजपा को चुनौती देने के लिए कोई वैकल्पिक मॉडल नहीं है। इसकी वजह यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर कमजोर पक्ष को मजबूत कर दिया है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद किए गए आंकलन में जो भी कमजोर पक्ष मिला है, उस पर इस बार जोरदार काम किया गया है। इसलिए विपक्ष के पास फिलहाल कोई मौका नजर नहीं आ रहा है। दरअसल, इस बार भाजपा सरकार ने संगठन के साथ समन्वय बनाकर अपनी कमजोरियां दूर करने का प्रयास किया है। इससे 2018 वाली स्थिति से पार्टी काफी आगे निकल गई है। इस बार भाजपा के पास जहां नया नेतृत्व है वहीं पूरी सरकार एकजुटता के साथ काम कर रही है। संघ प्रमुख को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बार प्रदेश सरकार के मंत्री, विधायक, भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एक सुनिश्चित एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इससे जनता के बीच सरकार और पार्टी की पैठ बढ़ी है। भाजपा के सूत्रों का कहना है कि पार्टी आलाकमान ने शिवराज सरकार, प्रदेश भाजपा संगठन और संघ को उपचुनाव की चारों सीटों को जीतने के साथ ही 2023 में विधानसभा की 230 में से 200 और लोकसभा की सभी 29 सीटें जीतने का लक्ष्य दिया है। इस लक्ष्य को पाने के लिए भाजपा रणनीति बनाकर मैदानी मोर्चा संभालने जा रही है। यही कारण है कि पिछले दिनों प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जिलों के साथ ही मोर्चा प्रकोष्ठों का गठन कर जल्द से जल्द मैदानी मोर्चा संभालने का निर्देश दिया है। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में कांग्रेस कभी-कभार नजर आ रही है।

अधर में 10 नर्मदा परियोजनाएं

नर्मदा नदी मप्र की जीवन रेखा है। नर्मदा का पानी सिंचाई, बिजली उत्पादन और पेयजल के रूप में इस्तेमाल होता है। लेकिन गुजरात के साथ नर्मदा नदी से पानी के बंटवारे में प्रदेश की दावेदारी कमजोर पड़ती जा रही है। राज्य सरकार अपने हिस्से के 18.25 एमएएफ (मिलियन एकड़ फिट) पानी का उपयोग अब तक नहीं कर पाई है। इसकी वजह है नर्मदा नदी पर बनने वाली परियोजनाओं के निर्माण में लेतलाली। कुछ परियोजनाएं आधी-अधूरी हैं तो बजट के अभाव में 10 परियोजनाएं शुरू ही नहीं हो पाई हैं।

आधी-अधूरी परियोजनाओं के कारण मप्र नर्मदा नदी से वर्ष 2024 तक अपने हिस्से का 18.25 एमएएफ पानी नहीं ले पाएगा। दरअसल, दो एमएएफ पानी लेने के प्रोजेक्ट के टेंडर ही नहीं हो पाए हैं। करीब एक दर्जन प्रोजेक्ट का काम लगभग 70 फीसदी अधूरा है। भुगतान के अभाव में ठेकेदारों ने प्रोजेक्ट की गति धीमी कर दी है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने पैसों के अभाव में 8 बड़े प्रोजेक्ट के लिए टेंडर रोक रखा है। इन प्रोजेक्ट की लागत करीब 27 हजार करोड़ के आसपास आएगी। टेंडर जारी होने पर 150 करोड़ रुपए तत्काल लगेंगे। इन प्राजेक्ट को पूरा होने में 4 से 5 साल लग सकते हैं, क्योंकि वन पर्यावरण सहित तमाम तरह की अनुमतियां लेनी होंगी। इन प्रोजेक्ट के पूरे होने पर प्रदेश में करीब 5 लाख हैक्टेयर में सिंचाई होगी। नहीं होने से ठेकेदारों ने काम की गति धीमी कर दी है। ठेकेदारों को हर माह 300 करोड़ का भुगतान हो रहा है, जबकि 800 करोड़ का भुगतान चाहिए। नर्मदा घाटी विकास विभाग होने का बजट ही 3500 करोड़ है।

दरअसल, इसके लिए प्रस्तावित 21 सिंचाई परियोजनाओं में से एक भी पूरी नहीं हुई है। इनमें से 10 परियोजनाओं को पिछले साल (वर्ष 2020) में मंजूरी दी गई थी, पर अब तक इनके टेंडर तक जारी नहीं हुए हैं। जबकि पहले से निर्माणाधीन 11 परियोजनाओं का निर्माण कार्य सरकार की माली हालत खराब होने के कारण अटका हुआ है। इन परियोजनाओं के ठेकेदारों को समय से भुगतान नहीं हो पा रहा है। ज्ञात हो कि पानी बंटवारे की तय समयसीमा के मुताबिक नर्मदा जल बंटवारा न्यायाधिकरण (नर्मदा वॉटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल) वर्ष 2024 में अपने 41 साल पुराने फैसले पर पुनर्विचार करेगा। तब तक अपने हिस्से का 18.25 एमएएफ पानी का उपयोग मप्र नहीं कर पाया, तो करीब 3.7 एमएएफ पानी गुजरात के खाते में चला जाएगा। नर्मदा जल बंटवारा न्यायाधिकरण ने वर्ष 1979 में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मप्र के बीच नर्मदा के पानी का बंटवारा किया था। 10 साल के अध्ययन और दोनों राज्यों की सुनवाई के बाद न्यायाधिकरण ने मप्र को 18.25 एमएएफ पानी का उपयोग करने की अनुमति दी थी, पर 41 सालों में राज्य बंटवारे का पानी खर्च नहीं कर पाया। अब वर्ष 2024 में न्यायाधिकरण अपने फैसले पर पुनर्विचार करने वाला है। इसे देखते हुए राज्य सरकार अपने हिस्से के पानी का उपयोग करना चाहती है। इसके लिए पिछले पांच साल में 21 परियोजनाओं की घोषणा की गई। जिनमें से एक भी चालू नहीं हो पाई है। सूत्र बताते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर हो चुकी सरकार इन परियोजनाओं के लिए बजट नहीं दे पा रही है।

नर्मदा नदी पर प्रस्तावित परियोजनाएं या तो आधी-अधूरी हैं या शुरू ही नहीं हो पाई हैं। जिन परियोजनाओं का काम चल रहा है उनकी गति काफी धीमी है। बरगी व्यपवर्तन परियोजना का काम चल रहा है। इससे जबलपुर, कटनी, रीवा, सतना जिले में 2.45 लाख हैक्टेयर में सिंचाई होगी। आईएसपी काली सिंध परियोजना के चरण एक का काम चल रहा है। इससे देवास, सीहोर शाजापुर जिले में एक लाख हैक्टेयर में सिंचाई होगी। इसके चरण दो से राजगढ़ और शाजापुर जिले में एक लाख हैक्टेयर में सिंचाई का लक्ष्य है। नर्मदा पार्वती चरण एक-दो में शाजापुर, सीहोर जिले में एक लाख हैक्टेयर में सिंचाई होगी। वहीं चरण तीन और चार में सीहोर, शाजापुर में एक लाख हैक्टेयर में सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है। छीपानेर माइक्रो परियोजना से सीहोर, देवास जिले की 53 हजार हैक्टेयर भूमि सिंचित होना है। नागरवाड़ी एमआईपी से बड़वानी और खरगोन जिले में 47 हजार हैक्टेयर में सिंचाई होना है। नर्मदा-क्षिप्रा बहुउद्देश्यीय परियोजना से उज्जैन जिले में 30 हजार हैक्टेयर में सिंचाई होगी। नर्मदा-झाबुआ-पेटलावाद से थांदला-सरदारपुर माइक्रो परियोजना से धार और झाबुआ जिले में 58 हजार हैक्टेयर में सिंचाई होना है। छैगांवमाखन माइक्रो परियोजना से खंडवा जिले में 35 हजार हैक्टेयर में सिंचाई होना है। मोरंड गंजाल परियोजना से खंडवा, होशंगाबाद, हरदा, जिले में 50 हजार हैक्टेयर सिंचित होना है। बरगी का पानी सतना लाने 12 किमी लंबी स्लीमनाबाद टनल का निर्माण 11 साल से चल रहा है, लेकिन 6.6 किमी सुरंग बन पाई है। मार्च में मुख्यमंत्री ने 2023 तक निर्माण पूरा करने हर माह 275 मीटर सुरंग बनाने का लक्ष्य दिया था। अभी भी प्रतिमाह 200 मीटर की औसत से निर्माण हो रहा है।

● **लोकेंद्र शर्मा**

लक्ष्य बड़ा...अभी तक कई परियोजनाएं शुरू नहीं

सभी परियोजनाओं से नर्मदा नदी से लगभग 25 लाख हैक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होना है। इसमें 13 लाख हैक्टेयर सिंचाई के लिए जल संसाधन विभाग के जरिए विभिन्न प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। जल संसाधन विभाग के भी कई निर्माण कार्य काफी पीछे चल रहे हैं। वहीं कई परियोजनाएं शुरू नहीं हो पाई हैं। इनमें चिकी वोरास बैराज नरसिंहपुर, शंकर पेंच जिक नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, दूधी परियोजना नरसिंहपुर, अपर नर्मदा परियोजना डिंडौरी, हाडिया बैराज हरदा, राघवपुर बहुउद्देश्यीय डिंडौरी, बसानिया मंडला, होशंगाबाद बैराज होशंगाबाद, कुक्षी परियोजना धार और सांवेर उद्वाहन इंदौर आदि शामिल हैं। मप्र 2024 तक 18.25 एमएएफ पानी नहीं ले पाता है तो बाकी पानी गुजरात के कोटे में चला जाएगा। इसके बाद मप्र नर्मदा से कोई भी परियोजना लॉन्च कर पानी नहीं ले सकेगा। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण ने पानी का बंटवारा कर मप्र के अलावा गुजरात को 9 एमएएफ, महाराष्ट्र को 0.50 एमएएफ और राजस्थान को 0.25 एमएएफ पानी देने का निर्णय किया है।

विकास पर विराम माननीय परेशान

मप्र में मिशन 2023 का घमासान जोर पकड़ रहा है। भाजपा और कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ मिशन मोड में आ गई हैं। सरकार ने अपने सभी विधायकों को विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय होने का निर्देश दे दिया है। लेकिन विधायक पसोपेश में पड़े हुए हैं, क्योंकि विकास कार्य रुके हुए हैं। ऐसे में माननीयों की परेशानी बढ़ गई है कि वे अपने क्षेत्र में जनता को क्या जवाब देंगे।

गौरतलब है कि प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के लिए डेढ़ साल बचे हैं। चुनाव का घमासान अभी से शुरू हो गया है। ऐसे में माननीयों को विकास की चिंता सताने लगी है। इस कारण वे अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य पूरा कराना चाह रहे हैं लेकिन सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने से जहां बड़े प्रोजेक्ट मंजूर नहीं हो रहे हैं वहीं जनभागीदारी वाले सैकड़ों काम अटक गए हैं। अकेले इस साल मंजूर हुए 500 प्रोजेक्ट्स में से अधिकांश में काम शुरू नहीं होने से माननीयों की धड़कनें बढ़ गई हैं।

गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। इस कारण माननीयों के जनभागीदारी के कार्यों के लिए पर्याप्त फंड नहीं मिल रहा है। इस कारण जनभागीदारी के कार्य रुके पड़े हैं। खरगोन विधानसभा क्षेत्र में जनभागीदारी के जरिए खेत सड़क योजना, सीसी रोड, तालाबों का गहरीकरण, खड्जा और सड़कों का निर्माण कराए जाने के प्रस्ताव बुलाए गए थे, लेकिन एक भी काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है और न ही नए कार्य स्वीकृत किए जा रहे हैं। लांजी विधानसभा क्षेत्र में भी अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने का प्रस्ताव अटका है। ये स्थिति अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों की है। प्रदेश में जनभागीदारी से जुड़े कार्य नहीं होने से जनप्रतिनिधियों में खासी निराशा है। इस समय गांवों में केंद्र सरकार के फंड से केवल जल जीवन मिशन के तहत समूह पेयजल योजना पर ही काम चल रहा है। जनभागीदारी के कामों पर वर्ष 2019 से रोक लगी हुई है। शिवराज सरकार ने पिछले साल 410 काम स्वीकृत किए थे और इस साल 500 से ज्यादा काम मंजूर हुए हैं, लेकिन आर्थिक संकट के चलते ये काम अधिकांश जिलों में ठप हैं।

जनभागीदारी के तहत खेत सड़क योजना, सीसी रोड, तालाबों का गहरीकरण, अस्पतालों में जन सहयोग से सुधार और उपकरणों की खरीदी, सांसद, विधायक के सहयोग से आंगनबाड़ी भवनों, स्कूल भवनों में पेयजल और टॉयलेट का निर्माण तथा बाउंड्रीवाल निर्माण शामिल हैं। खासकर अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों में जनभागीदारी से जुड़े कार्यों में सरकार 75 प्रतिशत राशि खर्च करती हैं और सामान्य क्षेत्रों में 50 प्रतिशत। बकाया 25 और 50 प्रतिशत राशि की व्यवस्था जनसहयोग, स्थानीय निकाय, पंचायतों आदि के माध्यम से की जाती है। लेकिन इस बार सरकार की आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसलिए विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

दरअसल मप्र का राजकोष खाली है। कमाई से ज्यादा खर्च है, राज्य का इस साल का जितना बजट है, उससे ज्यादा कर्ज है और कर्ज पर ब्याज का बोझ भी है। कर्ज पर निर्भर मप्र ऐसे में कैसे आत्मनिर्भर मप्र बन पाएगा। सरकार वेतन बांटने और प्रशासनिक व्यय के लिए प्रतिमाह दो हजार करोड़ का कर्ज ले रही है प्रदेश के अधिकांश निगम, मंडल घाटे में चल रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी ने भी मप्र सरकार पर कर्ज को लेकर ट्वीट करते हुए निशाना साधा हैं। उन्होंने लिखा की मप्र सरकार पर 2.53 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज हो चुका है। सरकार प्रति घंटे 2.5 करोड़ का ब्याज भर रही है। बावजूद इसके शिवराज 100 करोड़ रुपए का टर्बो जेट प्लेन खरीद रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसते हुए लिखा- महामारी, महंगाई से बदहाल जनता की गाढ़ी कमाई, सरकार के ऐशो-आराम पर क्यों उड़ाई जा रही है? उन्होंने मप्र की स्थिति के बारे में लिखा- ये कैसा कंगाल, बदहाल प्रदेश बना दिया? मप्र सरकार पर मार्च 2021 तक 2.53 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज हो चुका है। पिछले 1.5 वर्ष में ही 32 बार में 49,800 करोड़ से अधिक कर्ज लिया गया। इस हिसाब से मप्र के हर नागरिक पर 30 हजार से अधिक का कर्ज हो गया है। फिलहाल इन आकड़ों के हिसाब से मप्र की स्थिति काफी चिंताजनक हो गई हैं।

● **नवीन रघुवंशी**

माननीयों की अपने-अपने तर्क

विकास कार्य नहीं होने से विधायकों की अपनी-अपनी व्यथा है। मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया कहते हैं कि मैंने विधायक निधि से ग्राम दंदौड़ा में जनभागीदारी से कार्य कराने के लिए 5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। इसमें राज्य सरकार 2 लाख रुपए खर्च करेगी। मेरे क्षेत्र में जनभागीदारी के कार्य लगातार कराए जा रहे हैं। वहीं खरगौन विधायक रवि रमेशचंद्र जोशी कहते हैं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जनभागीदारी का कोई काम नहीं चल रहा है। केंद्रीय फंड से केवल जलजीवन मिशन के तहत समूह पेयजल योजनाओं में काम चल रहा है। क्षेत्र में फंड की कमी की वजह से अधिकांश विकास कार्य ठप हैं। उदयपुरा विधायक देवेंद्र पटेल कहते हैं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी जनभागीदारी का काम नहीं चल रहा है, जिसके कारण सीसी रोड और खड्जा सड़कों का निर्माण पूरी तरह ठप है। उधर, पीडब्ल्यूडी के पास भी पैसा नहीं है। जनभागीदारी से क्षेत्र में छोटे-मोटे कार्य हो जाते हैं। वहीं लांजी विधायक हिना कांवरे कहते हैं कि जनभागीदारी को लेकर लांजी में प्रस्ताव तो बुलाए गए थे, लेकिन अभी तक कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है। अधिकारियों से कई बार संपर्क करने पर भी गंभीरता नहीं बरती जा रही। मुख्यमंत्री घोषणा तो कर देते हैं, लेकिन क्षेत्र में काम नहीं होते।

अफसरों पर शिवराज कठोर क्यों?

इन दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ कड़क नजर आ रहे हैं। खासकर उनके निशाने पर नौकरशाह हैं। जाना जा रहा है कि मंत्रियों, विधायकों और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार शिकायत पहुंच रही है कि मैदान में पदस्थ अफसर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इससे सरकार की छवि खराब हो रही है। इस कारण मुख्यमंत्री को कठोरता दिखानी पड़ रही है। सिविल सेवा के अधिकारियों की आलोचना करना, पुलिस अधिकारियों को खुलेआम चेतावनी देना, लोगों को सार्वजनिक रैली में भ्रष्ट अधिकारियों का नाम लेने के लिए कहना और फिर उन्हें तत्काल वहीं-के-वहीं निलंबित करना-ये शायद कुछ ऐसी बातें लगती हैं जिसकी आप एक मृदुभाषी, नरमदिल और उदारवादी मुख्यमंत्री के रूप में ख्यात व्यक्ति से अपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन इन दिनों मप्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यही रूप देखने को मिल रहा है।

वाजपेयी-आडवाणी युग वाली भाजपा के एकमात्र मुख्यमंत्री चौहान, जो अभी भी सत्ता में हैं, अभी भी काफी लोकप्रिय हैं और अपने दम पर सीटें जितवाने में सक्षम हैं। लेकिन हाल ही में उत्तराखंड से कर्नाटक तक और अब गुजरात में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा किए गए नेतृत्व परिवर्तनों ने चौहान को अपनी कार्यशैली बदलने और सत्ता विरोधी लहर को मात देने के लिए एक नए प्रकार के दिखावे को अपनाने के लिए प्रेरित किया है।

उनके सामने मौजूद ताजातरीन इम्तिहान मप्र में तीन विधानसभा सीटों और खंडवा लोकसभा क्षेत्र, जिसके लिए तारीखों की घोषणा हाल ही में की गई है, के लिए होने वाले उपचुनावों की एक श्रृंखला है। लेकिन ऐसा लगता है कि इन चुनावों और भविष्य की अन्य चुनौतियों को भांपते हुए चौहान अपनी छवि को एक इफ्तार पार्टी में भाग लेने वाले उदारवादी नेता से बदलकर एक सख्त और अधिक कट्टर नेता के रूप में पेश करने को तैयार हैं। इसी आशय से उन्होंने विकास कार्यों पर जनता की प्रतिक्रिया (फीडबैक) प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से उन निर्वाचन क्षेत्रों में जहां उपचुनाव होने हैं, 12 सितंबर से जनदर्शन यात्रा शुरू कर दी है।

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि चौहान के इस 'स्वरूप परिवर्तन' के पीछे कई कारण हैं, पार्टी के शीर्ष पर बैठे नेतृत्व की प्रकृति से लेकर उनकी अपनी असुरक्षा तक, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा जैसे मजबूत नेताओं के नेतृत्व में मप्र भाजपा के भीतर भी कई गुट हो गए हैं। भोपाल में 'आजादी का अमृत महोत्सव' नाम के एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए उन्होंने सरकारी अधिकारियों पर विकास की झूठी तस्वीर पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 'यदि आप मंत्रालय के अंदर बैठे रहते हैं, तो आपको केवल एक झूठी तस्वीर मिलती है। आपको चारों तरफ आनंद ही आनंद नजर आता है। लेकिन जब आप वास्तव में मैदान में उतरते हैं, तभी आपको एहसास होता है कि यह खुशहाली कितनी दूर तक पहुंच पाई है।' प्रमुख सचिव (उद्योग) संजय शुक्ला की ओर मुड़ते हुए, चौहान ने कहा कि वह उनका जिक्र नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा, 'काम केवल वही हो पाता, जहां मुख्यमंत्री ध्यान केंद्रित करते हैं'।

इससे कुछ दिन पहले, जिला कलेक्टरों और आयुक्तों के साथ हो रही एक समीक्षा बैठक में, मुख्यमंत्री ने कहा था कि, 'जिस किसी अधिकारी ने भी पीएम आवास योजना के तहत पैसा खाया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।' उन्होंने भ्रष्टाचार की जांच के लिए औचक दौरे करने और विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने पर नजर रखने की भी प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा, 'अगर कोई भी शिकायत हुई तो मैं उन्हें निलंबित कर दूंगा।' उन्होंने दमोह के पुलिस अधीक्षक डीआर तेनिवार को पुलिसिंग के मामले में जिले की निम्न रैंकिंग के लिए और नीमच के एसपी सूरज कुमार वर्मा को 'गैंगस्टर और माफिया के खिलाफ कुछ नहीं करने' के लिए भी चेतावनी दी थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली घटना तो एक हफ्ते पहले निवाड़ी में हुई थी जब मुख्यमंत्री चौहान ने अपना भाषण सुन रही जनता से पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों का नाम पूछा था। उसी दिन मंच से उन्होंने कहा, 'मुझे बताया गया है कि पीएम आवास योजना में काफी अनियमितताएं हुई हैं। एक सीएमओ (मुख्य नगरपालिका अधिकारी) थे उनके खिलाफ भी शिकायतें हैं। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।'

ठीक उसी दिन, पृथ्वीपुर, जहां अभी उपचुनाव होना है, में आयोजित एक अन्य रैली में उन्होंने एक तहसीलदार को निलंबित कर दिया। उन्होंने पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा जांच की भी घोषणा की। टीकमगढ़ में भी, उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में एक अधिकारी को यह कहते हुए निलंबित कर दिया, 'अब मैं डंडा लेकर निकला हूं। गड़बड़ करने वालों को छोड़ूंगा नहीं।' इसके अलावा, रायगांव, एक अन्य उपचुनाव वाले क्षेत्र, में उन्होंने राज्य की नल जल योजना के तहत पानी उपलब्ध नहीं कराने के लिए एक अधिकारी की खिंचाई कर दी।

● अरविंद नारद

मजबूती दिखाने की कोशिश

मार्च 2020 में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के गिरने के बाद चौथी बार मप्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद से रैगांव, पृथ्वीपुर, जोबट विधानसभा क्षेत्रों और खंडवा संसदीय क्षेत्र में होने वाले आगामी उपचुनाव शिवराज सिंह चौहान की दूसरी कठिन कसौटी होगी। नवंबर 2020 में चौहान के पहले कड़े इम्तिहान में भाजपा ने 28 में से 19 सीटें जीतीं और इसके लिए कांग्रेस के पूर्व नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद को भी थोड़ा श्रेय जाता है, जो अपने समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल हो गए थे और जिससे इस उपचुनाव की आवश्यकता पड़ी थी। इस बार, चौहान खुद को एक मजबूत और होशियार नेता के रूप में पेश करके कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं।

18 माह में पढ़ाई चौपट

मप्र में 18 महीने बाद स्कूल खुल गए हैं। लेकिन पढ़ाई पूरी तरह चौपट हो गई है। दूसरी कक्षा के बच्चे को कुछ याद ही नहीं है। वहीं पांचवीं के बच्चे हिंदी की किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं। दरअसल, स्कूल बंद होने के कारण यह स्थिति निर्मित हुई है। भारत दुनिया में सबसे लंबे समय तक स्कूल बंद रखने वाले देशों में से एक है। देश में लगभग 44 करोड़ छात्र-छात्राएं 18 महीने से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सितंबर से कुछ राज्यों में स्कूल खुले हैं। तो कई राज्यों में स्कूल खुलने की संभावना अभी नहीं है।

सितंबर के पहले हफ्ते में आई एक रिपोर्ट में 'स्कूल चिल्ड्रेन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग (स्कूल) सर्वे' में कहा गया था कि कोविड की महामारी ने बच्चों की पढ़ाई पर प्रतिकूल असर डाला है। 500 से ज्यादा दिन से बंद रहे स्कूलों के चलते ग्रामीण बच्चे कैसे शिक्षा से दूर हो गए हैं। सर्वे के नतीजों के मुताबिक शहरों में 24 फीसदी तो गांवों में महज 8 फीसदी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे। गांवों में 37 फीसदी पढ़ाई नहीं कर रहे थे। गांवों में शामिल 48 फीसदी बच्चे ऐसे थे जो कुछ शब्दों से ज्यादा नहीं पढ़ सकते थे।

यह सर्वे अगस्त 2021 में 15 राज्यों किया गया, जिसमें मप्र भी शामिल था। सर्वे में शामिल 1362 परिवारों में से प्रत्येक प्राइमरी और अपर प्राइमरी में पढ़ने वाले एक-एक बच्चे से बात की गई थी। ग्रामीण इलाकों में महज 8 फीसदी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे इसकी वजह ये है कि ग्रामीण भारत में आधे परिवारों (सैंपल में शामिल) के पास स्मार्टफोन नहीं है। इससे पहले फरवरी 2021 में छोटी कक्षाओं के बच्चों के पढ़ाई के स्तर पर अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की रिपोर्ट 'लॉस ऑफ लर्निंग इन पैनडमिक' में कहा गया था कि प्राइमरी और मिडिल के बच्चों में पढ़ाई की क्षमता में कमी आई है। यह कमी समझने, पढ़ने और लिखने में भी है। साथ ही यह भी पाया कि बच्चे चित्र देखकर भी उसके बारे में बोल नहीं पाते।

'लॉस ऑफ लर्निंग इन पैनडमिक' क्षेत्र सर्वेक्षण में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय ने पाया था कि भाषा (लैंग्वेज) और गणित में बच्चे कमजोर हो रहे हैं। उनमें गणित के सवाल और भाषा के शब्द कहने, बोलने, समझने और लिखने में समस्या हो रही है। सर्वेक्षण में 92 फीसदी बच्चे भाषा और 82 फीसदी बच्चे गणित में कमजोर मिले। भाषा में चित्र देखकर समझ पाने, लिखने और शब्दों की पहचान करने में दिक्कत हुई। इसी तरह गणित में दो अंकों की पहचान और बोलने में तथा 2डी और 3डी आकार में अंतर बता पाने में भी बच्चों को समस्या आ रही है। 'लॉस ऑफ लर्निंग इन पैनडमिक' क्षेत्र सर्वेक्षण देश के पांच राज्यों में किया गया जिसमें मप्र में शामिल है।

स्कूल बंदी ने बच्चों की पढ़ने, लिखने और तार्किक सभी क्षमताओं पर असर डाला है।

ऑनलाइन पढ़ाई में शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच तालमेल की कमी

स्कूली शिक्षा के विशेषज्ञ भी इस बात को मानते हैं कि कक्षा में पढ़ाने और ऑनलाइन पढ़ाई दोनों में अंतर है। इसका कारण शिक्षक और बच्चे दोनों ही इस नए विकल्प के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाए हैं। रीवा संभाग के पूर्व संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा विभाग अंजनी कुमार त्रिपाठी (62 वर्ष) गांव कनेक्शन से टेलीफोन पर कहते हैं क्लास रूम की पढ़ाई और ऑनलाइन की पढ़ाई में अंतर तो होगा। न शिक्षक न ही बच्चे ऑनलाइन की पढ़ाई से तालमेल बैठा पा रहे। क्लासरूम में बच्चे एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धी होकर भी कुछ सीखते हैं लेकिन ऑनलाइन में घर में खाते-पीते, इधर-उधर बैठे पढ़ रहे हैं। पढ़ाई में एकाग्रता जरूरी है यही कमी तालमेल नहीं बैठाने दे रही है। स्कूल चिल्ड्रेन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग (स्कूल) सर्वे में 97 फीसदी ग्रामीण चाहते थे कि स्कूल जल्द से जल्द खोले जाएं।

सुमित चौधरी (11 वर्ष) ने 25 में 5 जोड़ और घटा तो लिया लेकिन भाग नहीं दे पाए। पूछने पर बताया कि भाग नहीं आता है। सुमित कक्षा छठवीं के विद्यार्थी हैं। वह कैमा उन्मूलन अपने बुआ के घर आए थे। उनका गांव कैथी, सतना जिले की ही ऊंचेहरा तहसील में आता है। हालांकि कैमरा ऑन करता देख वह भाग गए।

सतना के नागौद ब्लॉक के एक प्राथमिक शाला के शिक्षक ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर कहा, 'सर्वेक्षण की बातें हद तक सही हैं। मप्र में प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए पिछले सत्र में मोहल्ला क्लास शुरू की गईं थी। हम जाते थे। राज्य शिक्षा केंद्र (स्कूल शिक्षा विभाग की प्राथमिक और मिडिल विंग) द्वारा भेजे गए टॉपिक वीडियो बच्चों को दिखाना पड़ता था। इसके लिए एक बच्चे के घर में ही पांच बच्चों को बुलाते थे उन्हें वह वीडियो दिखाते थे। इसके बाद उनके प्रश्नों के उत्तर हम देते थे। इस तरह से साल भर पढ़ाई चली लेकिन बच्चों को इससे समझ में कम ही आता था। प्रश्न पूछने में भी वह हिचकिचाते थे।' वह कहते हैं 'स्कूल बंद होने के कारण पढ़ाई का रूटीन बिगड़ा है।'

कोरोना वायरस के खतरे के कारण स्कूल बंद थे। घर में ही रहकर बच्चों की पढ़ाई चल रही है लेकिन शब्दों और अंकों को लिखने, बोलने और समझने की क्षमता में आई कमी से अभिभावकों में भी चिंता साफ दिख रही है। सतना जिले के किटहा गांव की चैतूनिया बसोर (49 वर्ष) गांव कनेक्शन से कहती हैं, पिछले साल पढ़ाई का क्या है हुई ही नहीं। हम लोगों के घर में तो वैसे भी मास्टर साब लोग नहीं आते। हमारे बच्चों के भविष्य तो आपको भी पता है लेकिन सोचते हैं कि पढ़-लिख लेंगे तो जो हम करते हैं (बांस का व्यवसाय) उन्हें नहीं करना पड़ेगा पर स्कूल नहीं खुले थे इसी के कारण बच्चे घर में ही रहे और पढ़ाई-लिखाई सब स्वाहा ही गई।

● **विकास दुबे**

मप्र आने वाले दिनों में देश के लिए विकास का मॉडल बनेगा। इस लक्ष्य को साकार करने के लिए मप्र की सरकार कार्य कर रही है। इसके लिए प्रदेश में कई एक्सप्रेस-वे का खाका तैयार किया गया है। फिलहाल अटल एक्सप्रेस-वे, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे हो या फिर नर्मदा एक्सप्रेस-वे आदि को भारत माला प्रोजेक्ट के तहत बनाने की तैयारी चल रही है। इन एक्सप्रेस-वे से विकास के साथ रोजगार को भी स्पीडअप मिलेगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए मप्र को हरी झंडी दे दी है।

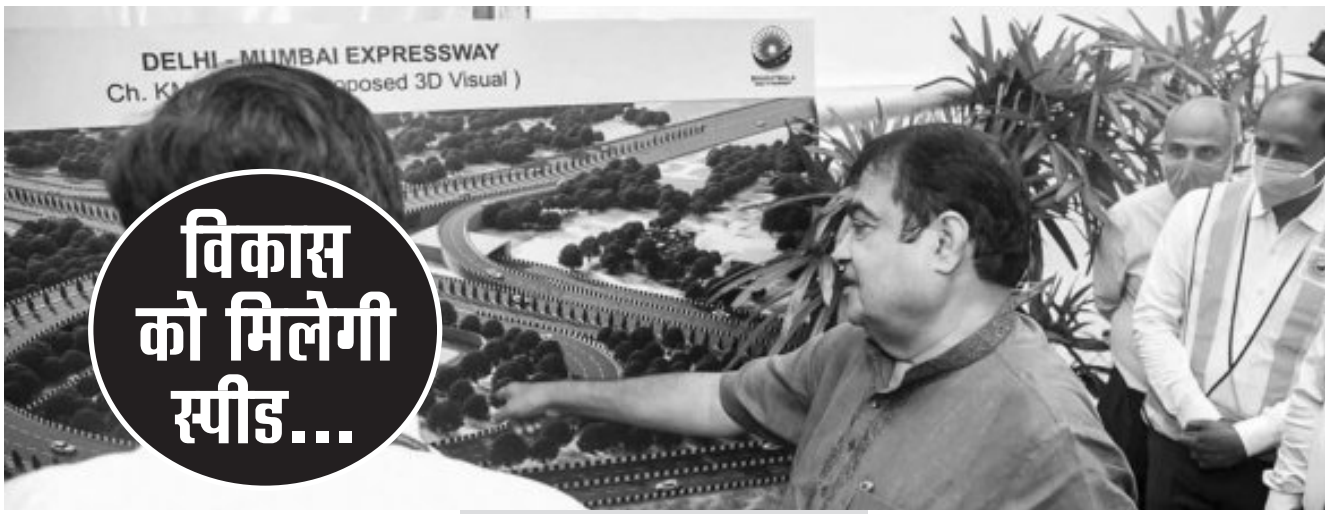

विकास को मिलेगी स्पीड...

मप्र में बिछाए जा रहे एक्सप्रेस-वे की श्रृंखला में चाहे वह अटल एक्सप्रेस-वे हो, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे हो या फिर नर्मदा एक्सप्रेस-वे, ये सभी मप्र में सड़क संपर्क बढ़ाने के साथ ही रोजगार के अनेक अवसर भी पैदा करेंगे। पर इन सबमें दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे को सबसे महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। एक तो यह विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे है, दूसरे इसके दोनों तरफ औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स हब बनेगा। इसी तरह अटल एक्सप्रेस-वे और नर्मदा एक्सप्रेस-वे भी मप्र में विकास को गति देंगे। यही नहीं इन तीनों एक्सप्रेस-वे से मप्र निवेश भी बढ़ेगा, क्योंकि इससे अन्य राज्यों से कनेक्टीविटी आसान हो जाएगी।

एक समय मप्र बीमारू राज्यों की गिनती में आता था, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में विकास को एक नई दिशा मिली है। मप्र ने आधारभूत ढांचों के विकास से लेकर कृषि क्षेत्र, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी समेत सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठता हासिल की है। किसी भी राज्य का समग्र विकास तभी संभव है, जब उसकी अधोसंरचना मजबूत हो। इसको देखते हुए मप्र सरकार ने एक्सप्रेस-वे बनाने का निर्णय लिया है। मप्र को मजबूती प्रदान करने के लिए गत दिनों केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 9 हजार 577 करोड़ रुपए की लागत से कुल 1356 किलोमीटर लंबी 34 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है।

1350 किमी लंबा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे है। फर्स्ट फेज में एक्सप्रेस-वे एट लेन का और दूसरे फेज में इसे 12 लेन का बनाएंगे। मप्र में 245 में से 106 किमी का काम पूरा हो गया है। नवंबर 2022 तक काम पूरा हो जाएगा। इसे मालवा से कनेक्टिविटी देने के लिए 173 किमी का फोरलेन भी बनाया जाएगा, जो इंदौर, देवास, उज्जैन, आगर और गरोठ तक जाएगा। एक्सप्रेस-वे पर प्रदेश सरकार से प्रस्ताव मिलने के बाद रतलाम के बिबड़ौद में 1800 हैक्टेयर में राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से लॉजिस्टिक हब, औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे बनने से मुंबई की मिनी मुंबई इंदौर से दूरी महज 4 घंटे की रह जाएगी। जबकि अभी इंदौर से मुंबई पहुंचने में 11 घंटे से ज्यादा का समय लगता है। ऐसे में ये एक्सप्रेस-वे मप्र के **आर्थिक विकास की एक** नई इबारत लिखेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में विश्व के सबसे लंबे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के निर्माण का जायजा लिया और 170 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही कार में थर्मस से चाय निकालकर भी पी।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने खुद बताया कि मैंने हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों को हिदायत दी थी कि यदि चलती कार में थर्मस से एक बूंद भी चाय गिरी, तो आप लोगों की खैर नहीं होगी। इस हाइवे को इतना स्मूथ बनाया गया है कि 120 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार पर वाहन चल सकेंगे। 1380 किलोमीटर लंबा 8 लेन वाला ये एक्सप्रेस-वे मार्च 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा। इस हाईवे के बनने से मुंबई और इंदौर के बीच 11 घंटे का समय घटकर 4 घंटे रह जाएगा। इससे दोनों आर्थिक राजधानियों के बीच व्यापार और आसान हो जाएगा। इससे मालवा के लोगों को रेडीमेड कपड़े, सराफा, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, फल-सब्जियों, अनाज का एक बहुत बड़ा बाजार मिल जाएगा। इस एक्सप्रेस-वे के बनने

मप्र के ग्रोथ इंजन बनेंगे

जानकारों का कहना है कि मप्र में बनने वाले तीनों एक्सप्रेस-वे कई राज्यों से होकर गुजरेंगे। वहीं से तीनों एक्सप्रेस-वे से उप्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात के लिए यातायात आसान हो जाएगा। जिससे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे, अटल एक्सप्रेस-वे और नर्मदा एक्सप्रेस-वे मप्र के ग्रोथ इंजन बनेंगे। इससे प्रदेश के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। भारतमाला परियोजना के तहत बनने वाले इन एक्सप्रेस-वे से मप्र में विकास की नई क्रांति होगी। गौरतलब है कि देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार रेल, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर फोकस कर रही है। इसी के तहत साल 2017 में केंद्र सरकार ने भारतमाला परियोजना की शुरुआत की थी। इस परियोजना के पहले चरण में देश में 24,500 किलोमीटर के रोड और नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। इसके साथ ही 10 हजार किमी सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा।

से ट्रैफिक जाम खत्म होगा। साथ ही, लॉजिस्टिक्स-ट्रांसपोर्टेशन लागत में भी कमी आएगी। इंदौर से मेडीकल हेल्प के लिए कई बार मरीजों को रेफर किया जाता है, अब ये और आसान हो जाएगा। 1350 किमी लंबे इस एक्सप्रेस-वे का अकेले मप्र में 8500 करोड़ की लागत से 8 लेन मार्ग बन रहा है। जरूरत पड़ने पर दूसरे फेज में इसे 12 लेन का बनाने का प्रस्ताव है।

भारत सरकार का मिशन आत्मनिर्भर भारत अब देश और मप्र में बन रहे माहौल को देखते हुए प्रदेश सरकार ने भी अपना काम तेज करते हुए दिल्ली-मुबंई एक्सप्रेस-वे के आसपास इंदौर और उज्जैन संभाग में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का रोडमैप तैयार किया है। निगम इस रीजन में दो बड़े और दो छोटे औद्योगिक क्षेत्र बनाने की तरफ अग्रसर है। जानकारी के अनुसार इस एक्सप्रेस-वे के कारण बड़ा निवेश क्षेत्र रतलाम के समीप तैयार हो रहा है। यहां 2 हजार एकड़ में लॉजिस्टिक पार्क और 3 हजार एकड़ में मल्टी प्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र और इसके अलावा 1 हजार एकड़ में मंदसौर, नीमच में मल्टी प्रॉडक्ट व टेक्सटाइल पार्क बना रहे हैं। इस तरह 6 हजार एकड़ के नए औद्योगिक क्षेत्र की योजना बनाए गई है। ऐसे में प्रदेश के इस रीजन को बहुत लाभ होने वाला है। इसके अलावा बेटमा के समीप पीथमपुर-7 में लगभग 3500 एकड़ में औद्योगिक टाउनशिप व उज्जैन में भी लघु-सूक्ष्म उद्योग का मॉडल तैयार होकर काम भी शुरू हो चुका है। इस तरह एक्सप्रेस-वे के आसपास 10 हजार एकड़ से अधिक के औद्योगिक क्षेत्र तैयार हो रहे हैं। इनमें अगले तीन सालों में 70 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और व्यवसाय भी बढ़ेगा।

अटल एक्सप्रेस-वे मप्र, उप्र और राजस्थान के पिछड़े इलाकों से होकर गुजरेगा। करीब 8500 करोड़ के इस एक्सप्रेस-वे को भारत माला में शामिल कर लिया गया है। 403 किमी लंबे एक्सप्रेस-वे का 313 किमी मार्ग मप्र में पड़ेगा। इस एक्सप्रेस में लॉजिस्टिक पार्क, औद्योगिक केंद्र, कृषि उत्पादन केंद्र, खाद्य प्रसंस्करण केंद्र, शिक्षा केंद्र और मनोरंजन केंद्र भी प्रस्तावित है। केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मप्र के अटल एक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार के महत्वकांक्षी भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत शामिल कर लिया है। अटल एक्सप्रेस-वे 404 किलोमीटर लंबा होगा और चंबल के भिंड, मुरैना और श्योपुर जिलों से होकर गुजरेगा। यह एक्सप्रेस-वे उप्र के झांसी और राजस्थान के कोटा को जोड़ेगा। इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण में करीब 7 हजार करोड़ रुपए का खर्च आएगा। एक्सप्रेस-वे के निर्माण से ग्वालियर चंबल इलाके के विकास में तेजी आएगी।

विकास में मील का पत्थर

सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कहते हैं, मुझे खुशी है कि वर्ल्ड का यह सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे है। यह हमारे देश के लिए अभिमान का विषय है। दिल्ली से मुंबई हम 12 घंटे में पहुंच सकेंगे। इससे इंदौर के अलावा भोपाल, उज्जैन, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अहमदाबाद, सूरत जैसे शहरों तक आना-जाना आसान होगा। इसमें जगह-जगह हेलीपैड की भी व्यवस्था होगी, जिससे आकस्मिक स्थिति में किसी मरीज को एयर एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये हाइवे मप्र के आर्थिक विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। दरअसल, दिल्ली-मुंबई रोड कॉरिडोर दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे होगा और मप्र इसका हिस्सा है। 1350 किमी का हाईवे 2023 तक पूरा होगा। अभी तक 608 किमी का काम हो चुका है। 139 किमी का काम बचा है। इसके जरिए लोकल स्तर पर रोजगार मिलेगा। किसानों को उनकी जमीन का सबसे उचित मूल्य दिया गया। लॉजिस्टिक हब के रुप में मप्र को विकसित किया जाएगा। राज्य में 40 लॉजिस्टिक हब बनाए जाएंगे। रतलाम को पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके लिए योजना बनाने और गोदाम से लेकर लॉजिस्टिक हब शहर से बाहर रखना होगा।

बता दें कि अटल एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल कोरिडोर विकसित किए जाएंगे, जिनसे इलाके में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और औद्योगिक विकास होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। अटल एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए 2771 हैक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। जिसमें से 1523 हैक्टेयर जमीन सरकारी है। निजी जमीन 1248 हैक्टेयर है, जिसका जल्द से जल्द अधिग्रहण करने की योजना है। प्रोजेक्ट के तहत आने वाली 284 हैक्टेयर जमीन वन विभाग की है, जिसके लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है। प्रदेश में अमरकंटक से अलीराजपुर तक नर्मदा एक्सप्रेस-वे तैयार किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। यह एक्सप्रेस-वे अमरकंटक (मप्र) को अंकलेश्वर (गुजरात) से जोड़ेगा। यह देश का सबसे लंबा 6 लेन एक्सप्रेस-वे होगा। 1265 किमी लंबे इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण में 31 हजार करोड़ की लागत आएगी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह एक्सप्रेस-वे अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगौन और बड़वानी जिले से गुजरेगा। इन एक्सप्रेस-वे से इन जिलों के लोगों को निश्चित रूप से फायदा होगा। इस एक्सप्रेस-वे के तैयार होने से रोजगार और स्व-रोजगार की संभावाएं बढ़ जाएंगी। क्योंकि इसके आसपास इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाया जाएगा। इस क्लस्टर के अलावा यहां 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। यह पार्क भारत सरकार की भारतमाला परियोजना के तहत बनाए जाएंगे।

यह एक्सप्रेस-वे मप्र के जरिए छत्तीसगढ़ और गुजरात को जोड़ेगा। एक तरह से कहा जाए तो पूर्वी मप्र और पश्चिमी मप्र इस एक्सप्रेस-वे के जरिए सीधे तौर पर जुड़ जाएंगे। इस एक्सप्रेस के बनने से टूरिज्म बढ़ेगा। ओंकारेश्वर, अमरकंटक, भेड़ाघाट-लमेटाघाट में टूरिज्म बढ़ेगा। प्रदेश में निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी। बता दें, प्रदेश में भारत सरकार की भारतमाला योजना के तहत 35 हजार करोड़ रुपए लागत की नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। प्रदेश में अक्टूबर महीने में एक लाख करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की भी घोषणा होगी।

● **राकेश ग्रोवर**

भूमाफिया पर एक्शन में सरकार

मप्र में मुख्यमंत्री के तौर पर चौथी पारी शुरू करने के साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश को माफिया मुक्त बनाने का अभियान शुरू कर दिया। इस अभियान के तहत भूमाफिया, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया आदि पर लगातार कार्रवाई की गई। भूमाफिया के खिलाफ प्रदेश सरकार ने मोर्चा खोल रखा है। बीते 6 महीने में प्रदेश में 2 हजार से ज्यादा अवैध कब्जे ध्वस्त कर दिए गए हैं, जबकि 3839 एकड़ से ज्यादा जमीन भूमाफिया से मुक्त कराई गई है। शिवराज सरकार ने इन 6 महीनों में 300 करोड़ से ज्यादा की अवैध जमीन को भूमाफिया के चंगुल से छुड़ाया है। खासतौर पर भोपाल-इंदौर सहित बड़े शहरों में अवैध कब्जे व अतिक्रमण पर एक्शन लिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिलों में प्राथमिकता से इस मुहिम को चलाने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर माफिया पर एक्शन के आदेश कलेक्टर-कमिश्नर को दिए हैं। इसके तहत भूमाफिया के खिलाफ भी एक्शन बढ़ना है। इसके तहत नए सिरे से भूमाफिया को चिन्हित करके सूचियां बनाना तय किया गया है।

इसी कड़ी में 24 सितंबर को इंदौर के कनाड़िया रोड पर सीलिंग की 38 एकड़ जमीन पर बने पटेल परिवार के प्रेम-बंधन गार्डन, रिवाज गार्डन सहित 150 से ज्यादा दुकानें जमींदोज कर दी गईं। प्रशासन का दावा है कि जमीन की कीमत 1000 करोड़ है। हालांकि कार्रवाई के बाद भी प्रशासन जमीन का कब्जा नहीं ले पाएगा, क्योंकि वह सुप्रीम कोर्ट में यह केस हार चुका है। अधिकारियों ने समय पर कोर्ट में जवाब ही पेश नहीं किए, जिसके कारण पटेल परिवार के पक्ष में एकतरफा फैसले होते रहे। कार्रवाई के लिए एडीएम, अपर आयुक्त, दो एएसपी, सीएसपी, चार थानों के बल के साथ 100 का पुलिस बल, 250 निगमकर्मियों की फौज तैनात की गई थी।

यह जमीन 1993 में सीलिंग में आई। प्रशासन ने 1996 में कब्जा लेने का आदेश दिया। 1999 में कब्जा ले भी लिया, लेकिन इस बीच 1997 में भूस्वामी की मृत्यु हो गई। इसे आधार बनाकर भूस्वामी की संतान कोर्ट चली गई। उन्होंने दावा किया कि जमीन हमारी है। वे केस जीत गए। 2007 में पटेल परिवार सत्र न्यायालय में भी केस जीत गया, क्योंकि प्रशासन ने समय पर अपील ही नहीं की। 2016-17 में हाईकोर्ट और 2021 में सुप्रीम कोर्ट में भी प्रशासन हार गया क्योंकि समय पर अपील ही नहीं की गई। इन 28 वर्षों में 14 कलेक्टर आए और चले गए, कोई कब्जा नहीं ले पाया। उधर, प्रशासन ने सीलिंग की जमीन पर गार्डन बनाने की इजाजत देने वाले तत्कालीन कनाड़िया सरपंच नारायणसिंह ठाकुर के अलावा पटेल परिवार के 6 लोगों पर केस दर्ज कराया है। इनमें वली मोहम्मद, अहमद नूर, बाबू पटेल, नबीबख्श, रुस्तम और सिकंदर शामिल है। इन पर धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120बी में धोखाधड़ी व फर्जी दस्तावेज से अवैध निर्माण के आरोप में केस दर्ज किया गया है।

मप्र में माफिया से मुक्त जमीनों पर अब स्कूल, वृद्धाश्रम और सरकारी दफ्तर खुलेंगे। ग्रीन फील्ड भी विकसित होगी। कलेक्टरों ने राज्य सरकार को यह प्रस्ताव भेज दिया है, जिस पर जल्द निर्णय होगा। माफिया, आदतन अपराधियों और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ दो साल चले इस बड़े अभियान से 2000 हैक्टेयर सरकारी जमीन मुक्त कराई गई है, जिसकी अनुमानित लागत 8 हजार 800 करोड़ है।

शासन ने कलेक्टरों के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। साथ ही कहा है कि यह अभियान अब और सख्त तरीके से होगा। माफिया और अतिक्रमण के साथ अपराध को आर्थिक चोट दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इसकी मॉनीटरिंग करेंगे। मुख्य सचिव से रिपोर्ट लेंगे। अभी तक 1500 भू-माफिया पर शिकंजा कसा है। कलेक्टर और नई सूची तैयार कर रहे हैं। इसमें रेत माफिया भी शामिल किया गया है, क्योंकि पिछले डेढ़ साल में रेत का अवैध खनन करने पर 5281 केस दर्ज हुए हैं। इनसे 25 करोड़ मूल्य की एक लाख 26 हजार घन मीटर रेत जब्त की गई। पांच हजार ट्रैक्टर, ट्रॉली, डंपर, ट्रक और जेसीबी पकड़े गए। इसलिए इस सेक्टर को भी निगरानी में लिया गया है।

● **जितेंद्र तिवारी**

माफिया पर ऐसी नकेल

प्रदेशभर में भू-माफिया के खिलाफ अब तक चलाए गए अभियान में हजारों एकड़ जमीन छुड़ाई गई। 1360.57 एकड़ पुलिस ने मुक्त कराई, 719.49 एकड़ राजस्व ने मुक्त कराई, 1760.18 एकड़ पुलिस-राजस्व ने संयुक्त, इस प्रकार प्रदेश में कुल 3839.69 एकड़ जमीन मुक्त कराई है। वहीं भूमाफिया के खिलाफ अपराध भी दर्ज किए गए हैं। इनमें 273 प्रकरण पुलिस ने दर्ज किए, 275 प्रकरण राजस्व ने दर्ज कराए, 97 प्रकरण नगरीय निकायों ने दर्ज कराए, 479 प्रकरण इनके संयुक्त दर्ज हुए, कुल 1034 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा अवैध अतिक्रमण वालों के खिलाफ केस दर्ज किए गए। इनमें 108 केस अवैध कब्जा व गुंडागर्दी के पुलिस ने दर्ज किए, 1277 केस अवैध कब्जा व गुंडागर्दी के राजस्व ने दर्ज किए, 277 केस अवैध कब्जे व गुंडागर्दी के पुलिस-राजस्व के संयुक्त, कुल 1712 केस प्रदेश में अवैध कब्जे व गुंडागर्दी के दर्ज किए गए हैं। प्रदेश में हजारों की संख्या में अवैध अतिक्रमण भी तोड़े गए हैं। इनमें 370 पुलिस ने तुड़वाएं, 382 राजस्व ने तुड़वाएं, 1650 संयुक्त रूप से तोड़े गए। इस तरह प्रदेश में कुल 2402 अतिक्रमण तोड़े गए। अपने अभियान के दौरान पुलिस प्रशासन ने किसी भी रसूख के आगे अपना माथा नहीं टेका। दरअसल, यह पूरी कार्रवाई शासन के निर्देश पर प्रशासन ने की है।

ई-टेंडर महाघोटाले की जांच पर ब्रेक

मप्र के महाघोटालों में शामिल ई-टेंडरिंग घोटाले की जांच ठंडे बस्ते में चली गई है। इससे इस घोटाले में शामिल बड़ी-बड़ी मछलियां फिलहाल बची हुई हैं। उधर, कांग्रेस इस मामले को फिर से उछाल रही है।

आयकर छापा 2019 की जांच भी पड़ी धीमी

मप्र के बहुचर्चित ब्लैकमनी मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी ईओडब्ल्यू की जांच सालभर बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। इस मामले में तीन आईपीएस अफसर और एक एसपीएस अफसर पर प्राथमिक जांच भी दर्ज है। जांच के घेरे में कई मंत्री, विधायक, नेता और कारोबारी हैं। लोकसभा चुनाव-2019 से पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नजदीकियों के घर आयकर का छापा पड़ा था। आरोपों के घेरे में तीन आईपीएस और एक एसपीएस अफसर आए। निर्वाचन आयोग के पत्र के बाद ईओडब्ल्यू ने दिसंबर 2020 में प्राथमिकी जांच दर्ज की थी। राज्य शासन की तरफ से भी आईपीएस अफसर वी मधुकुमार, सुशोवन बनर्जी, संजय वी माने के साथ राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी अरुण मिश्रा को आरोप पत्र दिया जा चुका है। सीबीडीटी की रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी अधिकारियों पर प्रतीक जोशी के माध्यम से करोड़ों रुपए के लेनदेन का आरोप लगा। ईओडब्ल्यू आयकर विभाग से दस्तावेज लेने का हवाला देकर इस मामले में खानापूर्ति कर रहा है। ब्यूरो के जिम्मेदार अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के समय में हुई गड़बड़ियों का पर्दाफाश होने से रह गया है। हालांकि सरकार इस मामले को ठंडा नहीं होने देगी।

मप्र में सबसे बड़े महाघोटाले पर पर्दा डाल दिया गया। व्यापमं से भी बड़ा ई-टेंडर घोटाला है लेकिन राजनेताओं और नौकरशाहों के गठजोड़ के कारण पिछले तीन साल में सिर्फ 9 टेंडर्स में ही एफआईआर दर्ज हो सकी। जबकि जांच के दौरान 803 टेंडर्स में टेंपरिंग के सबूत मिले थे। इतना ही नहीं 2014 से 2017 के बीच हजारों टेंडर्स में गड़बड़ी के संकेत भी मिले थे। इसके बावजूद इस अरबों-खरबों के घोटाले में आगे एक भी एफआईआर नहीं कराई गई।

मप्र का बहुचर्चित ई-टेंडर अब तक का सबसे बड़ा घोटाला साबित हुआ है। ईओडब्ल्यू ने शिवराज सरकार में हुए करीब 3000 करोड़ के ई-टेंडर घोटाले को लेकर सबसे पहली एफआईआर 10 अप्रैल 2019 को दर्ज कराई गई थी। ये एफआईआर 9 टेंडर में टेंपरिंग को लेकर की गई थी। सभी 9 टेंडर्स जनवरी से मार्च 2018 के दौरान प्रोसेस हुए थे। इसके बाद 52 टेंडर जो अक्टूबर 2017 से मार्च 2018 के दौरान प्रोसेस हुए थे, उनमें से 42 टेंडरों में टेंपरिंग का खुलासा हुआ था। लेकिन जिन 42 टेंडरों की तकनीकी जांच भारत सरकार की इंडियन कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को करनी थी वो आई ही नहीं इसलिए आज तक इस केस में एफआईआर नहीं हो सकी। यह घोटाला पहले करीब 3000 करोड़ तक सीमित था, लेकिन आगे की जांच में यह घोटाला अरबों-खरबों तक पहुंचने का आंकलन किया गया था।

गौरतलब है कि प्रदेश में विगत कुछ सालों के दौरान हजारों टेंडर्स में टेंपरिंग हुई थी। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा सरकार में 2014 से 2017 के बीच साढ़े तीन लाख टेंडर्स जारी किए गए थे। ईओडब्ल्यू ने 2014 से 2017 के बीच शिवराज सरकार के दौरान जारी हुए टेंडर्स की कमलनाथ सरकार के दौरान जांच की तो 803 टेंडर्स में टेंपरिंग के सबूत मिले थे। आगे की जांच में ये संख्या हजारों में पहुंचने की संभावना जताई थी। जिन 9 टेंडर्स में एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें ऑस्मो आईटी सॉल्यूशन कंपनी के जरिए टेंपरिंग हुई थी। ईओडब्ल्यू को आगे की जांच के दौरान इसी कंपनी पर बाकी के पुराने टेंडर्स में गड़बड़ी करने के सबूत मिले थे।

कांग्रेस ने इसे मप्र के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव कहते हैं, इस घोटाले की हमने अपनी सरकार में जांच कराई, तो सैकड़ों मामलों तक जांच पहुंच गई थी। भाजपा सरकार बनते ही उनके मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कई लोगों का नाम आने के कारण मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। भाजपा सरकार के संरक्षण में घोटाला हुआ था।

जिन टेंडर्स में तीन साल में अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, उनमें जल संसाधन, सड़क विकास निगम, नर्मदा घाटी विकास, नगरीय प्रशासन, नगर निगम स्मार्ट सिटी, मेट्रो रेल, जल निगम, एनेक्सी भवन समेत कई निर्माण काम करने वाले विभागों के टेंडर्स शामिल हैं। इसमें कई दलाल, संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी और राजनेता भी शामिल हैं। ईओडब्ल्यू ने अपनी पहली एफआईआर अज्ञात नौकरशाहों और राजनेताओं के खिलाफ धारा 120बी, 420, 468, 471, आईटी एक्ट 2000 की धारा 66, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 7 सहपठित धारा 13(2) के तहत दर्ज की थी।

भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। भाजपा नेता रजनीश अग्रवाल ने कहा कमलनाथ की सरकार के दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि दम है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। उस समय कांग्रेस सरकार ने बदनाम और गुमराह करने का काम किया था। सबूत पहले भी नहीं थे और अभी भी नहीं हैं। कांग्रेस सिर्फ लोगों को गुमराह और राजनेताओं को अपमानित कर रही है।

कमलनाथ सरकार के दौरान भाजपा नेताओं और उनके स्टाफ के लोगों के नाम आने के बाद इस घोटाले पर जमकर सियासत हुई थी। लेकिन अब भाजपा की सरकार में इस मामले में जांच पर ब्रेक लगने से फिर एक बार कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। ईओडब्ल्यू एजेंसी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार किसके दवाब में जांच रोकी गई और किसे बचाने की कोशिश की जा रही है।

● **प्रवीण कुमार**

9 लाख खसरों के मालिक लापता!

मप्र में जमीनों का खेल किस तरह चलता है इसका खुलासा कई बार हो चुका है। अब भू-अभिलेखों के रियल टाईम संधारण में कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। प्रदेश के भू-अभिलेख रिकार्ड में अभी काफी अशुद्धियां हैं। दिवंगत हो चुके लोग अभी भी रिकार्ड में भूमिस्वामी बने हुए हैं। बड़ी बहू, मंझले भैया के नाम से भूमिस्वामी रिकॉर्ड में दर्ज है। खसरा, खतौनी और नक्शे का रिकार्ड अलग-अलग है। कई खसरों में क्षेत्रफल शून्य चला आ रहा है। प्रदेश के 8 लाख 96 हजार 984 खसरा नंबरों में भूमिस्वामी के नाम ही नहीं है। अब विभाग इन लापता मालिकों की पड़ताल में जुट गया है।

भू-अभिलेखों का रियल टाईम संधारण में कई गांवों में नक्शा और खसरों में उपलब्ध भूखंडों की संख्या में अंतर पाया गया है। इन त्रुटियों के चलते आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, जमीन पर कर्ज लेने में दिक्कत आ रही है वहीं नामांतरण और बंटवारा करने में राजस्व अमला भी परेशान हो रहा है। इसलिए अब राज्य सरकार प्रदेशभर के भूअभिलेख रिकार्ड को पखवाड़े का आयोजन कर शुद्ध करेगी। राजस्व विभाग द्वारा वर्तमान में प्रदेश में भू-अभिलेखों का रियल टाईम संधारण भूलेख पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। खसरा, नक्शा, खतौनी, अधिकार अभिलेख आदि की ऑनलाईन डिजिटली हस्ताक्षरित प्रतिलिपि निर्धारित शुल्क पर नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही है। रिकार्ड को अद्यतन करने का सभी कार्य भूलेख पोर्टल पर संपादित किया जा रहा है।

विभाग के सामने बड़ी चुनौती है कि वह असली मालिक को पोर्टल पर दर्ज करे। अभी रिकार्ड में बड़ी संख्या में भूमिस्वामी ऐसे दर्ज है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। नामांतरण के लिए कोई आवेदन नहीं मिलने के कारण मृतकों के नाम रिकार्ड में दर्ज है। इस पखवाड़े में इस प्रकार के कर ठीक करेगा ताकि रिकार्ड फौती नामांतरण की कार्यवाही होगी। इसी तरह रिकार्ड में भूमिस्वामी के रुप में बड़ी बहू, छोटी बहू, मंझले भैया जैसे नाम प्रचलित है। पीएम किसान योजना के तहत जब किसान के नाम को कारण योजनाओं का लाभ लेने आधार कार्ड में दर्ज नाम के आधार पर सत्यापन किया जाता है तो समस्या सामने आती है और किसान को योजना का वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता इन त्रुटिपूर्ण नामों के सुधार के लिए पखवाड़ा अभियान चलाकर इन्हें ठीक किया जाएगा।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अनुसार सैटेलाइट के माध्यम से हो रहे सर्वे में कई ऐसे लोग चिन्हित हो रहे हैं, जिन्होंने मकान तो बनवा लिया लेकिन हाउस टैक्स के लिए निगम में आवेदन नहीं कर रहे हैं।

लाखों खसरा नंबरों में क्षेत्रफल शून्य

प्रदेश के कई गांवों के नक्शे और खसरों में उपलब्ध भूखंडों की संख्या में अंतर है और कुछ मिसिंग है। भूमिप्रकार और भूमिस्वामी प्रकार में भी अंतर है। प्रदेश के 8 लाख 96 हजार खसरा नंबरों में क्षेत्रफल शून्य है। कुछ खसरों में क्षेत्रफल न्यून है। एनआईसी सॉफ्टवेयर से भूलेख पोर्टल में अन्य डाटा के साथ अंतरित हो जाने से यह स्थिति बनी है। मूल खसरों से बटांक बनाने पर मूल खसरा नंबर डिलीट ही नहीं किया गया। कुछ खसरा नंबरों में अन्य खसरा नंबर शामिल हो गए। इसे भूलेख पोर्टल पर खसरा डाटा सुधार मॉडयूल से सुधारा जाएगा। खसरे, खतौनी और नक्शे में अलग रिकार्ड है। इसे एक किया जाएगा। अल्फा न्यूमरिक खसरे बनाकर इसे सुधारा जाएगा। आयुक्त भू-अभिलेख ज्ञानेश्वर पाटिल कहते हैं कि प्रदेशभर में राजस्व रिकार्ड में जो त्रुटियां हैं उन्हें राजस्व विभाग पखवाड़े का आयोजन कर ठीक करेगा ताकि रिकार्ड दुरुस्त हो और लोगों को इनके कारण योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत नहीं हो।

प्रदेश के भू-अभिलेख रिकार्ड में अशुद्धियों के कारण विभाग को काफी परेशानी हो रही है। पहले यह काम एनआईसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता था जो ऑफलाईन काम करता था। उसमें डाटा का संधारण तहसीलवार किया जाता था। तहसीलवार परिपाटी अनुसार शब्दावली भिन्न-भिन्न थी। तहसीलवार प्राप्त डाटा को भूलेख पोर्टल पर पोर्ट किया गया जिसके बाद पता चला कि संपूर्ण प्रदेश के भू-अभिलेख डाटा में एकरुपता नहीं है और नागरिकों को उपलब्ध कराए जा रहे कुछ कम्प्यूटरीकृत अभिलेख पूर्णतः शुद्ध नहीं है। प्रचलित नाम अभिलेख में दर्ज नहीं है और आधार में वास्तविक नाम भिन्न है। इस प्रकार की भूमि स्वामी के नाम में भी त्रुटियां हैं।

सरकार ने 7 साल पहले भोपाल, इंदौर सहित 294 निकायों में जीआईएस (ज्योग्राफिकल इंफार्मेशन सिस्टम) सर्वे शुरू करवाया था ताकि निकायों को संपत्ति का वाजिब टैक्स मिल सके। लेकिन अभी तक 152 निकायों में सर्वे कार्य पूरा हो पाया है। इस लापरवाही से सरकार को हर साल करोड़ों रुपए की चपत लग रही है। अब नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने निकायों को संपत्ति का जीआईएस सर्वे करने के लिए 2023 तक का समय दिया है। जानकारी के अनुसार निकायों में जीआईएस सर्वे पिछले सात सालों से चल रहा है जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। जिन 152 निकायों में सर्वे किया गया है वहां के टैक्स कलेक्शन में 30 से 40 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

गोदामों में रखे अनाज बेचेगी सरकार

मप्र देश का सबसे बड़ा अनाज उत्पादक प्रदेश बनता जा रहा है। इसका असर यह हो रहा है कि सरकार किसानों का एक-एक दाना खरीद रही है। इससे प्रदेश के गोदाम भरे पड़े हैं। ऐसे में सरकार ने अनाज बेचने का निर्णय लिया है।

मप्र के गोदामों और ओपन कैप में गेहूं, धान, मूंग सहित कई तरह के अनाज भरे पड़े हैं। सरकार इन अनाजों को बेचकर आर्थिक तंगी दूर करेगी। कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में उपार्जित धान की मिलिंग के लिए शेष मात्रा 3.82 लाख मेट्रिक टन एवं खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 की 1250 मेट्रिक टन धान को भारत शासन द्वारा केंद्रीय पूल में मान्य नहीं करने के कारण मप्र स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन एवं मप्र राज्य सहकारी विपणन संघ को मिलिंग के लिए उनके पास शेष रही मात्रा ई-ऑक्शन के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए विक्रय करने की अनुमति दी। उक्त धान के विक्रय के लिए रिजर्व प्राईस, ऑफसेट मूल्य के निर्धारण, निविदा प्रक्रिया के निर्धारण एवं नीलामी में प्राप्त दरों के अनुमोदन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया। सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया है ताकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधर सके।

गौरतलब है कि वर्तमान में सरकार को हर माह लगभग 2 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ा रहा है। ऐसे में सरकार अनाजों को बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहती है। गौरतलब है कि प्रदेश में हर साल अनाज का रिकार्ड उत्पादन और सरकारी खरीदी हो रही है। इस कारण प्रदेश के गोदाम और कैप भरे पड़े हैं। पिछली बार प्रदेश सरकार छह लाख 45 हजार टन गेहूं की नीलामी करने के बाद अब धान की भी नीलामी करेगी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2017-18 और 2019-20 की मिलिंग से शेष पौने चार लाख टन से अधिक धान को अब सेंट्रल पूल में लेने से इंकार कर दिया है। नीलामी से एक हजार 400 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति क्विंटल तक राशि मिलने की उम्मीद है। जबकि, जुलाई 2021 तक धान का प्रति क्विंटल औसत आर्थिक लागत 2 हजार 476 रुपए है। इस प्रकार सरकार को धान नीलाम करने के बाद भी करोड़ों रुपए की हानि होगी पर सरकार के पास इसके अलावा अन्य विकल्प भी नहीं है।

गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर 25 लाख 54 हजार टन धान का उपार्जन किया था। इसमें से 20 लाख 47 हजार टन धान की मिलिंग हुई और चावल भारतीय खाद्य निगम को सेंट्रल पूल के लिए दिया गया। तीन लाख 82 हजार टन धान की मिलिंग अब तक नहीं हो पाई है। जबकि, राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने बार-बार मिलिंग की अवधि में वृद्धि की। 29 अप्रैल 2021 को पत्र लिखकर केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि अब मिलिंग की अवधि में वृद्धि नहीं होगी और शेष धान का निराकरण राज्य सरकार ही करे। यह धान गोदाम और कैप में रखी हुई है। इसलिए सरकार इस धान को नीलाम करने जा रही है।

खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि एक अप्रैल 2020 से मिलिंग प्रारंभ हुई। कोरोनाकाल में प्रतिमाह औसतन एक लाख टन धान की मिलिंग हुई थी। गति ठीक चल रही थी पर जुलाई अंत में चावल की गुणवत्ता को लेकर बालाघाट, मंडला सहित अन्य जिलों में कार्रवाई हुई और निम्न गुणवत्ता का चावल मिलर को लौटा दिया। इससे मिलिंग लगभग बंद हो गई। मिलर ने धान की गुणवत्ता का सवाल उठाया और टेस्ट मिलिंग करके धान लेने की मांग रखी पर केंद्र सरकार ने अनुमति नहीं दी। मिलिंग नहीं होने से सरकार ने मिल संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और मिलों को सील तक कर दिया पर यह कदम कारगर साबित नहीं हुआ। इसी तरह वर्ष 2017-18 की एक हजार 250 टन धान मिलिंग के लिए शेष है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने मिलिंग के लिए शेष धान को अब नीलाम करने की तैयारी शुरू कर दी है।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

गेहूं, धान के साथ मूंग भी बिकेगी

गेहूं, धान के साथ ही मूंग भी बेचने की तैयारी हो रही है। प्रदेश में चार लाख 39 हजार टन ग्रीष्मकालीन मूंग का उपार्जन समर्थन मूल्य 7 हजार 196 रुपए प्रति क्विंटल पर किया है। जबकि, केंद्र सरकार ने 2 लाख 47 हजार टन मूंग खरीदने की ही अनुमति दी थी। शेष मूंग को सेंट्रल पूल में लेने की मांग पिछले दिनों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से की है। वहीं, 80 हजार टन मूंग मध्यान्ह भोजन योजना में बच्चों को देने का प्रस्ताव है, जिस पर अंतिम निर्णय होना बाकी है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा सेंट्रल पूल में 6 लाख 45 हजार टन गेहूं लेने से इंकार करने के बाद सरकार ने इसे नीलाम करने के लिए छोटे-छोटे समूह बनाकर निविदा बुलाई तो परिणाम बेहतर सामने आए हैं। खरीदारों ने 1 हजार 600 रुपए से लेकर 2 हजार रुपए प्रति क्विंटल की दर प्रस्तावित की है। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने गेहूं की प्रति क्विंटल आधार दर एक हजार 590 रुपए तय की थी। निगम ने परीक्षण करने के बाद दर अनुमोदित करने का प्रस्ताव मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली साधिकार समिति को भेज दिया है।

पोषण आहार का नया सिस्टम

पोषण के खिलाफ जंग में प्रदेश सरकार ने महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने के लिए प्रदेश के सातों पोषण आहार प्लांटों को महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपने का निर्णय लिया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने नया सिस्टम लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। संभवत: दिसंबर से समूहों के सातों परिसंघ सरकारी प्लांटों में पोषण आहार उत्पादन शुरू कर देंगे। हालांकि, ये निर्णय लेने में वर्तमान सरकार को भी डेढ़ साल का समय लग गया, क्योंकि पोषण आहार व्यवस्था से जुड़े विभागों को एक राय बनाने में वक्त लगा है। मार्च 2020 में मुख्यमंत्री बनते ही शिवराज सिंह चौहान ने सातों प्लांट एमपी एग्रो से वापस लेकर समूहों के परिसंघों को सौंपने का निर्णय लिया था।

बता दें कि प्रदेश के 97 हजार 135 आंगनबाड़ी केंद्रों में रजिस्टर्ड 6 माह से 3 साल के बच्चों, गर्भवती-धात्री माताओं और किशोरियों को टेकहोम राशन दिया जाता है। फरवरी 2018 तक टीएचआर पर ठेकेदारों का कब्जा था। वे महिला एवं बाल विकास विभाग से ऑर्डर लेकर सीधे आंगनबाड़ी केंद्रों तक पोषण आहार पहुंचाते थे, लेकिन वर्ष 2017 में पोषण आहार सप्लाई करने वाली कंपनियों से विवाद के बाद राज्य सरकार ने मार्च 2018 में व्यवस्था बदल दी। 13 मार्च 2018 की कैबिनेट ने पोषण आहार उत्पादन का जिम्मा स्व-सहायता समूहों के परिसंघ को सौंपते हुए प्रदेश में सात सरकारी प्लांट तैयार करने का भी निर्णय लिया था। इन प्लांटों को अक्टूबर 2018 में काम शुरू करना था, पर समय से तैयार नहीं हुए। वर्ष 2019 में धार, देवास, होशंगाबाद, सागर एवं मंडला के प्लांट तैयार हुए और उनमें उत्पादन शुरू हुआ था कि अक्टूबर 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने इस व्यवस्था से समूहों को हटा दिया और एमपी एग्रो को प्लांट सौंप दिए। कैबिनेट में अतिरिक्त एजेंडे के रूप में आए इस प्रस्ताव को एक मिनट में पारित कर दिया गया। रीवा और शिवपुरी के प्लांट वर्ष 2020 में तैयार हुए। ज्ञात हो कि वर्तमान में प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में हर माह औसत 1050 टन पोषण आहार दिया जा रहा है।

पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा है कि राज्य सरकार महिला स्वसहायता समूहों को मजबूती देकर ग्रामीण विकास में तेजी लाने के हर संभव प्रयास कर रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में पोषण आहार संयंत्रों का संचालन एमपी एग्रो से लेकर आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित महिला स्व-सहायता समूहों के परिसंघों को सौंपा जा रहा है। इस फैसले से प्रदेश में पोषण आहार तैयार कर उसके मुनाफे से प्रदेश के लाखों समूह सदस्य लाभांवित होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भोपाल में 16 सितंबर को स्व-सहायता समूह संवाद कार्यक्रम में महिलाओं को यह पोषण आहार संयंत्र सौंपे जाने का आश्वासन दिया गया था जिसे उन्होंने पूरा किया। जिस पर कैबिनेट ने सहमति दे दी है। मंत्री सिसोदिया ने कहा कि पोषण आहार संयंत्रों के संचालन से प्राप्त होने वाले लाभांश में से 5 प्रतिशत का उपयोग संयंत्रों के संधारण के लिए सुरक्षित रखते हुए शेष 95 प्रतिशत लाभांश स्व-सहायता समूहों को प्राप्त होगा। इन संयंत्रों में प्रतिमाह 50 से 60 करोड़ रुपए का पोषण आहार तैयार होता है। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा काम समूहों को सौंपे जाने से सरकार की महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण के लिए प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में अनूठी योजनाएं लागू की हैं ताकि प्रदेश को देश में अग्रणी राज्य बनाया जा सके।

प्रस्ताव के अनुसार प्लांटों का संचालन, प्रबंधन, उत्पादन, वितरण और वित्तीय नियंत्रण स्व-सहायता समूहों को सौंपा जाएगा। सालभर में प्लांट को जो लाभ होगा, उसमें से पांच फीसदी राशि प्लांट के रखरखाव के लिए आरक्षित कर शेष राशि सभी संकुल स्तरीय संगठनों में समान अनुपात में बांटी जाएगी। जिन भूमि-भवनों में प्लांट संचालित हैं, वह पंचायत विभाग की संपत्ति रहेंगे। भवन, प्लांट, मशीनों की देखरेख का जिम्मा समूहों के परिसंघ का होगा। एमपी एग्रो के अमले को छोड़कर शेष अमला राज्य आजीविका मिशन को सौंपा जाएगा। इन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पहले साल आजीविका मिशन और इसके बाद संयंत्रों के लाभांश से वेतन दिया जाएगा। प्लांटों के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवाशर्तों के निर्धारण का अधिकार मिशन को रहेगा। पंचायत विभाग का अमला मिशन को सौंपा जाएगा।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी

प्लांटों की गतिविधियों में समूह की महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएंगे। प्लांटों के संचालन, प्रबंधन, पोषण आहार वितरण, दरों, रेसिपी, गुणवत्ता सहित अन्य विषयों में निर्णय लेने के लिए अंतरविभागीय समिति बनेगी। जिसमें अपर मुख्य सचिव पंचायत विभाग, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी रहेंगे। एमपी एग्रो से वापस ली जाएगी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। इसके पुनर्गठन के अधिकार मिशन को होंगे। प्लांट चलाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग प्लांटों को तीन माह की राशि अग्रिम देगा। जिसका समायोजन अगले बिलों में किया जाएगा। प्लांटों के लिए कच्चा माल खरीदने के लिए राज्य आजीविका मिशन स्तर पर अलग से शाखा बनाई जाएगी। राज्य आजीविका मिशन पूर्व में दिए गए 60 करोड़ रुपए 30 सितंबर 2023 तक लौटाएगा। यह राशि प्लांटों में मशीनें स्थापित करने के लिए सरकार ने मिशन को वर्ष 2018 में दी थी।

अलग बुंदेलखंड राज्य की हांडी

उप्र विधानसभा चुनाव 2022 के नजदीक आते ही सियासी दलों के नायकों ने एकबार फिर पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग तेज कर दी है। बुंदेलखंड राज्य निर्माण को लेकर चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत गावों के युवाओं, किसानों, महिलाओं को बुंदेलखंड राज्य निर्माण अभियान में जोड़ने के लिए प्रधानों को संकल्प दिलाया जा रहा है। वहीं महोबा जिले के चरखारी विधानसभा से भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत ने जन सहभागिता के माध्यम से पृथक बुंदेलखंड राज्य बनाने की हुंकार भरी है। भाजपा विधायक का मानना है कि अगर बुंदेलखंड के लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री तक अपनी मांग को पहुंचाएं तो वह दिन दूर नहीं, जब बुंदेलखंड अलग राज्य बनने के बाद देश के अन्य छोटे-छोटे राज्यों के बीच एक विकसित राज्य के रूप में जाना जाएगा।

इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक मेसेज ने बुंदेलखंड में हलचल बढ़ा रखी है। इसमें बताया गया है कि सरकार उप्र को तीन अलग-अलग राज्यों में बांटने जा रही है। इनमें उप्र, पूर्वांचल के अलावा बुंदेलखंड भी है। बुंदेलखंड राज्य में झांसी और चित्रकूट मंडल के सात जनपदों के अलावा प्रयागराज, मिर्जापुर और कानपुर मंडल के 10 जिले और जोड़े जा रहे हैं और राजधानी प्रयागराज बनाई जाएगी। हालांकि, इसे लेकर सरकार की ओर से कोई अधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन, अलग बुंदेलखंड राज्य के पैरोकारों के बीच बहस तेज हो चली है। वे इस नए बुंदेलखंड राज्य को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि उप्र और मप्र के सात-सात जनपदों को मिलाकर ही बुंदेलखंड राज्य बनाया जा सकता है। वास्तविक बुंदेलखंड यही है।

उप्र के 7 जिले झांसी, ललितपुर, जालौन, बांदा, महोबा, हमीरपुर व चित्रकूट तथा मप्र के 7 जिले दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर व निवाड़ी को बुंदेलखंड माना जाता है। इन 14 जिलों की भौगोलिक स्थितियां समान हैं, साथ ही भाषा-बोली और परंपराओं के मामले में भी ये एक जैसे हैं। यही वजह है कि 2009 में केंद्र सरकार द्वारा बुंदेलखंड विशेष पैकेज उक्त जिलों के लिए ही दिया गया था। लेकिन, हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए मेसेज में प्रस्तावित बुंदेलखंड राज्य में उप्र के उक्त 7 जिले तो दर्शाए जा रहे हैं, परंतु मप्र के जनपद इसमें नहीं है। इनके स्थान पर प्रयागराज मंडल के प्रयागराज, फतेहपुर, कौशांबी व प्रतापगढ़, मिर्जापुर मंडल के मिर्जापुर, संत रविदास नगर व सोनभद्र और कानपुर मंडल के कानपुर नगर, कानपुर देहात व औरैया को बुंदेलखंड राज्य में दिखाया जा रहा है। प्रस्तावित बुंदेलखंड राज्य की राजधानी प्रयागराज को बताया जा रहा है। इस मेसेज ने क्षेत्र में एक नई बहस शुरू कर दी है। खासतौर पर पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण की लड़ाई लड़ने वाले संगठन बुंदेलखंड के इस नए नक्शे को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि नक्शा बेमेल है। प्रयागराज मंडल और कानपुर मंडल की भाषा बोली तक अलग हैं। बुंदेलखंड की जरूरतें अलग हैं। यहां औद्योगिक विकास की जरूरत है। क्षेत्र के पर्यटन विकास की जरूरत है। रोजगार की जरूरत है। लेकिन, यदि प्रस्तावित बुंदेलखंड राज्य बन जाता है तो औद्योगिक विकास कानपुर मंडल में पहुंच जाएगा और पर्यटन विकास की धारा प्रयागराज की ओर मुड़ जाएगी। ऐसे में बुंदेलखंड राज्य बन जाने के बाद भी क्षेत्र का कोई भला होने वाला नहीं है। उप्र और मप्र के 14 जिलों को सरकार भी बुंदेलखंड क्षेत्र मानती है। इसके अलावा पिछले साल सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत पूछे गए एक सवाल के जवाब में भी गृह मंत्रालय की ओर से बताया गया था बुंदेलखंड राज्य का प्रस्ताव लंबित पड़ा हुआ है, जिसमें उप्र और मप्र के जिले शामिल हैं।

2007 में मायावती के नेतृत्व में बनी उप्र की बसपा सरकार ने बुंदेलखंड राज्य के प्रस्ताव को पारित कर केंद्र के पास भेजा था। प्रदेश सरकार ने झांसी और चित्रकूट मंडल के सातों जनपदों को मिलाकर बुंदेलखंड राज्य बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा था। लेकिन, इसके बाद से मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में झांसी-ललितपुर संसदीय सीट से भाजपा ने उमा भारती को प्रत्याशी बनाया था। चुनाव से पहले उन्होंने वादा किया था कि केंद्र में भाजपा सरकार बनने पर तीन साल में अलग राज्य बना दिया जाएगा। सरकार बनने के बाद उमा को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इससे लगने लगा था कि अब केंद्र में अलग राज्य की तगड़ी पैरोकारी होगी। लेकिन, हुआ कुछ नहीं। बुंदेलखंड के इतिहास के जानकार मुकुंद मेहरोत्रा ने बताया कि आजादी के बाद सरकार ने 12 मार्च 1948 को पैंतीस रियासतों को मिलाकर बुंदेलखंड राज्य बनाया था। इसके 8 साल बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद 31 अक्टूबर 1956 को इसे खत्म कर दिया गया। इसका कुछ हिस्सा उप्र और कुछ मप्र में मिला दिया गया।

● **सिद्धार्थ पांडे**

बुंदेलखंड राज्य के पक्ष में नहीं मप्र के जिले

मप्र की पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती का अलग बुंदेलखंड राज्य निर्माण पर कहना है कि एक राय न होने से यह संभव नहीं है। इसमें कई दिक्कतें हैं। मप्र के जिले बुंदेलखंड राज्य में शामिल नहीं होना चाहते। वह कहती हैं कि मायावती सरकार में बुंदेलखंड राज्य का प्रस्ताव विधानसभा में रखा गया पर सीमांकन नहीं किया। स्पष्ट आम सहमति से प्रस्ताव रखा जाए तो तीन माह में बुंदेलखंड राज्य बन सकता है। झांसी-ललितपुर लोकसभा चुनाव के दौरान तीन साल में बुंदेलखंड राज्य की घोषणा करने वाली उमा भारती के अलग राज्य के सवाल पर सुर बदल गए हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर बुंदेलखंड राज्य का मुद्दा उप्र एवं मप्र के आपसी सामंजस्य पर छोड़ दिया। वह कहती हैं कि आंदोलनकारी पहले तय कर लें कि आखिर कितना बुंदेलखंड चाहिए। मप्र के जिले बुंदेलखंड राज्य में जुड़ना नहीं चाहते।

मप्र में 2 साल बाद विधानसभा चुनाव होना है। भाजपा और कांग्रेस अभी से मिशन 2023 की तैयारी में जुट गई है। लेकिन इससे पहले एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। वैसे तो इन उपचुनावों का सत्ता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इनके परिणाम मप्र का राजनीतिक भविष्य जरूर तय करेंगे। इन चारों सीटों के परिणाम जिनके पक्ष में जाएंगे, वह पार्टी 2023 के मोर्चे पर और उत्साह दिखाएगी। इसलिए इन उपचुनावों का महत्व बढ़ गया है।

● **राजेंद्र आगाल**

मप्र में 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही राजनीतिक घमासान चरम पर है। इस घमासान में उपचुनाव समय-समय पर घी का काम करते रहते हैं। पहले 28 सीटों पर उपचुनाव के दौरान घमासान दिखा, फिर दमोह में। अब खंडवा लोकसभा सीट सहित जोबट, पृथ्वीपुर और रैगांव में विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल बज गया है। इन उपचुनावों को जीतने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने मैदानी मोर्चा संभाल लिया है। मैदानी मोर्चे पर भाजपा कांग्रेस से काफी आगे है। फिर भी दोनों पार्टियां **चारों सीटें** जीतने का दावा कर रही हैं। इसकी वजह यह है कि इन उपचुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। दरअसल, इन उपचुनावों के परिणाम से भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ ही मप्र की राजनीति का भविष्य तय होना है। इसलिए इन उपचुनावों को जीतने के लिए दोनों पार्टियां हर तरह का दांव खेलने की रणनीति पर लगातार मंथन करती रही हैं।

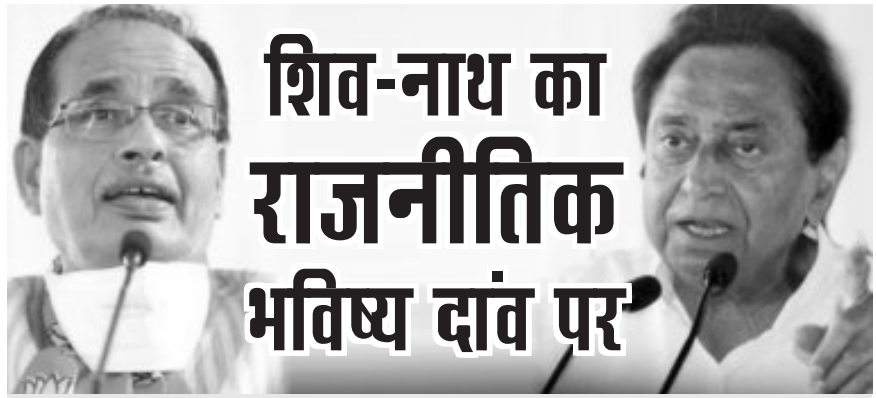

शिव-नाथ का राजनीतिक भविष्य दांव पर

मप्र में एक लोकसभा और तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही जीत-हार का गुणा-भाग शुरू हो गया है। इस उपचुनाव में जीत या हार से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि, इन नतीजों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का राजनीतिक भविष्य जरूर तय होगा। मप्र में बीते डेढ़ साल से भाजपा की सरकार है, जिसके मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। शिवराज सिंह देश के सबसे **चर्चित** मुख्यमंत्रियों में से एक हैं और मप्र में भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा भी हैं। शिवराज ने इसी को ध्यान में रखते हुए उपचुनाव वाली सभी सीटों पर बीते दिनों जनदर्शन यात्रा की। इस दौरान शिवराज ने अपनी छवि के विपरीत एक सख्त मुखिया का अंदाज दिखाया। उन्होंने इस जनदर्शन यात्रा में ना सिर्फ जनता की समस्याओं को सुना बल्कि ऑन द स्पॉट एक्शन लेते हुए इनका समाधान कराया और जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की। शिवराज बेशक मप्र मे सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते विपक्ष के निशाने पर भी वही रहते हैं। विपक्षी दल यानि कांग्रेस के पास फिलहाल उपचुनावों में मुद्दों की कोई कमी नहीं है। ऐसे कई मुद्दे हैं जो विपक्ष के लिए हथियार का काम करेंगे और शिवराज के लिए सिरदर्द रहेंगे। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में बड़ी संख्या में लोगों की जान जाने का मामला हो, महंगाई का मुद्दा, प्रदेश मे बेरोजगारी और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस भाजपा सरकार को घेरेगी। मप्र में बीते कुछ महीनों से दलितों और धर्म विशेष के लोगों के साथ जो घटनाएं घटित हुईं उसके चलते भी शिवराज सरकार की जमकर किरकिरी हुई। दूसरी तरफ 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर जो पेच फंसा हुआ है, उसे लेकर भी सरकार निशाने पर है। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया था लेकिन तब से लेकर अब तक यह मामला कानूनी पेंच में उलझा हुआ है। हालांकि सरकार का दावा है कि जो मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं उन्हें छोड़कर सभी जगह 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण लागू कर दिया गया है। उपचुनाव के नतीजे अगर भाजपा के पक्ष में आता है, तो यकीनन शिवराज बतौर मुख्यमंत्री और मजबूत होंगे। लेकिन बाजी अगर कांग्रेस के हाथ में जाती है तो माना जाएगा कि शिवराज का जादू कम हो रहा है और जिस तरह से भाजपा आलाकमान ने उत्तराखंड, कर्नाटक और गुजरात में चेहरे बदले हैं मप्र में भी इसी तरह की अटकलें शुरू हो सकती हैं।

एक साल के भीतर ही मप्र में भाजपा और कांग्रेस की एक और परीक्षा 30 अक्टूबर को होगी। इस दिन खंडवा लोकसभा सीट के साथ ही जोबट, पृथ्वीपुर और रैगांव की विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। 2 नवंबर को इनके परिणाम आएंगे। इन उपचुनावों का वैसे तो कोई प्रभाव नहीं होना है, लेकिन ये कई नेताओं की भावी राजनीति पर असर डालेंगे। इसलिए इन उपचुनावों को कोई भी हल्के में नहीं ले रहा है। कांग्रेस के सामने फिर उपचुनाव चुनौती के तौर पर खड़े हुए हैं। पिछले साल सत्ता गंवाने के बाद 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस कोई बड़ा करिश्मा नहीं कर पाई थी। दमोह विधानसभा के उपचुनाव के नतीजों से भाजपा पर जो दबाव बना, उसने कांग्रेस को अतिविश्वास से भर दिया।

सर्वे ने उड़ाई नींद

लोकसभा की तरह ही विधानसभा की सीटों की हार-जीत से भी मौजूदा सरकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर भी यह चुनाव दोनों दलों के लिए प्रतिष्ठा का है। इस उपचुनाव को 2023 की सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। यही कारण है कि चुनावों की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही दोनों दलों ने रणनीति तेज करने के साथ नेताओं की तैनाती भी शुरू कर दी थी। कांग्रेस जहां तीनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारी नियुक्त कर चुकी है तो वहीं भाजपा ने विधानसभा वार सत्ता और संगठन से जुड़े लोगों को तैनात कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के अलावा प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव राज्य पर खास नजर रखे हुए हैं।

राज्य में खंडवा लोकसभा के अलावा पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव में विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। इन **चार स्थानों** में से खंडवा के अलावा रैगांव से पिछला चुनाव भाजपा जीती थी तो वहीं पृथ्वीपुर और जोबट से कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। उपचुनाव से पहले कराए गए सर्वे के नतीजों ने सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की नींद उड़ा दी है। भाजपा द्वारा कराए गए सर्वे के मुताबिक भाजपा खंडवा लोकसभा

अर्चना चिटनीस

हर्षवर्धन सिंह चौहान

अरुण यादव

सुरेंद्र सिंह शेरा

इसलिए हो रहे हैं उपचुनाव

खंडवा में लोकसभा सीट का उपचुनाव होना है। जबकि जोबट, पृथ्वीपुर और रैगांव में विधानसभा के उपचुनाव हैं। चारों सीटों पर उपचुनाव की स्थिति मौजूदा सांसद और विधायकों के निधन के कारण बनी है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में खंडवा सीट पर भाजपा के नंदकुमार चौहान निर्वाचित हुए थे। जोबट और पृथ्वीपुर की विधानसभा की सीट कांग्रेस के कब्जे वाली सीट हैं। जोबट की विधायक कलावती भूरिया और पृथ्वीपुर के विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर का निधन कोरोना संक्रमण के कारण हो गया था। रैगांव की सीट से भाजपा विधायक जुगल किशोर बागरी का निधन भी कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ जाने के कारण हुआ था। जिन तीन सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, वे राज्य के अलग-अलग अंचल वाली हैं। पृथ्वीपुर की सीट बुंदेलखंड क्षेत्र में आती है। जबकि रैगांव विंध्य प्रदेश में हैं। जोबट विधानसभा और खंडवा लोकसभा की सीट मालवा-निमाड़ का हिस्सा है।

चेहरों की चुनौती पर रस्साकशी

प्रदेश में तीन विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान होते ही प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस ने ताल ठोंक दी है। दोनों दलों ने अब मैदान में उतरकर जोर-आजमाईश की तैयारी कर ली है। चुनाव का ऐलान होने के बाद अब टिकट की रस्साकशी प्रमुख हो गई है। दोनों पार्टियों को जल्द उम्मीदवार चेहरों का फैसला करना होगा। तब तक के लिए राज्य मुख्यालय से लेकर बूथ तक दोनों पार्टियों ने अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। प्रदेश भाजपा लगातार उपचुनाव के लिए तैयारी कर रही है। भाजपा में सत्ता-संगठन ने मिलकर संयुक्त रूप से मैदान में बिसात बिछा दी है। गत दिनों प्रदेश भाजपा कार्यालय में अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक की गई। इसके बाद पदाधिकारियों से भी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अलग से बैठक की। सभी को उपचुनाव में जुटने का साफ संदेश दे दिया गया। दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मंत्रियों के साथ उपचुनाव को लेकर चर्चा की। जिन मंत्रियों को उपचुनाव वाले क्षेत्रों की जिम्मेदारी हैं, उन्हें अब आचार संहिता के हिसाब से काम करने की नसीहत दी गई। भाजपा हर सीट के लिए मंत्री और संगठन पदाधिकारी की ड्यूटी लगा चुकी है। इसके अलावा अन्य प्रभारी भी नियुक्त किए जा चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस भी उपचुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस ने हर सीट के लिए प्रभारी पहले ही तैनात कर दिए हैं, लेकिन टिकट को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। अभी कांग्रेस टिकट के लिए सर्वे करा रही है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ तीन नवंबर को भोपाल आएंगे। इसके बाद उपचुनाव के लिए बैठक होगी।

सीट पर होने वाले उपचुनाव में जीत हासिल कर सकती है, जबकि विधानसभा उपचुनावों के नतीजे पार्टी के लिए किसी बुरे सपने के तरह हो सकते हैं। यही वजह है कि पार्टी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इन क्षेत्रों में मोर्चा संभालने उतार दिया है। खुद मुख्यमंत्री भी उपचुनाव वाले इन क्षेत्रों में जनदर्शन यात्रा निकालकर जनता के सामने अधिकारियों की क्लास लगाकर उन पर तत्काल कार्रवाई भी कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक चार सीटों पर होने वाले उपचुनाव में पार्टी को जिन वजहों से नुकसान हो सकता है, वे महंगाई, कोरोनाकाल के चलते रोजगार का खत्म होना, हालात संभालने में सरकार की नाकामी और बेरोजगारी ये मुद्दे भाजपा पर भारी पड़ने वाले हैं।

हर सीट पर अलग चुनौती

एक लोकसभा और तीन विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। हर सीट की चुनौती अलग है। मुख्यत: दो चुनौतियां कांग्रेस के सामने हैं। पहली चुनौती गुटबाजी की है। दूसरी बड़ी चुनौती पार्टी के नेतृत्व को लेकर है। पिछले साढ़े तीन साल से कमलनाथ राज्य में कांग्रेस को अपने हिसाब से चला रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पंद्रह साल बाद सत्ता में वापस लौटी तो कमलनाथ ने इसे अपनी रणनीति की जीत के तौर पर लिया। कांग्रेस के दिग्गज नेता मसलन ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव सरकार बनने के बाद हाशिए पर डाल दिए गए। सिंधिया, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। अजय सिंह और अरुण यादव अपने आपको उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। अजय सिंह के पिता स्वर्गीय अर्जुन सिंह कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं। जबकि अरुण यादव के पिता स्वर्गीय सुभाष यादव दिग्विजय सिंह सरकार में उपमुख्यमंत्री रहे हैं। वे बड़े किसान नेता माने जाते थे। कमलनाथ से पहले अरुण यादव प्रदेश कांग्रेस के साढ़े चार साल तक अध्यक्ष रहे हैं। केंद्र में मंत्री भी रहे। हाल ही में कमलनाथ के करीबी पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने अरुण यादव के खिलाफ तीखी टिप्पणी की थी। उन्होंने तंज कसा था कि उनके कई कॉलेज और हजार एकड़ कृषि जमीन है। पूर्व मंत्री का अपनी पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष पर यह तंज इस बात को लेकर था क्योंकि वे उपचुनाव की बैठक में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे थे। सज्जन सिंह वर्मा उस कमेटी के समन्वयक हैं, जो चार सीटों के उपचुनाव के लिए बनाई गई है। इससे पहले कमलनाथ ने खंडवा सीट पर अरुण यादव की दावेदारी पर कहा था कि मेरी जानकारी में उनकी दावेदारी नहीं है।

कमलनाथ भरोसे कांग्रेस

राज्य में उपचुनाव हैं और कमलनाथ मैदान में नहीं हैं। राज्य के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि उस सेना की बात ही क्या करना जिसका सेनापति सामने नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया के अनुसार कमलनाथ अपने स्वास्थ्यगत कारणें से देश से बाहर हैं। वे दो अक्टूबर से भोपाल में ही रहेंगे। कांग्रेस के नेताओं के मैदान में न होने का पूरा लाभ भाजपा उठाने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा लगातार उपचुनाव वाले क्षेत्रों के दौरे कर रहे हैं। इन दौरों में कमलनाथ की अनुपस्थिति को भी बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश चल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी अभी यही नहीं पता। पार्टी अध्यक्ष वीडी शर्मा का सवाल है कि क्या दिग्विजय सिंह चुनाव का नेतृत्व करेंगे ? पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के लिए अजय सिंह और अरुण यादव को साधना वक्त की जरूरत है। दोनों ही नेताओं के प्रभाव वाले क्षेत्रों में उपचुनाव हैं। खंडवा सीट पर अरुण यादव की दावेदारी को नकारना भी जोखिम भरा हो सकता है। प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में यादव ओबीसी चेहरा हैं। निमाड़ के ओबीसी वोटर में उनकी अच्छी पैठ है। अजय सिंह के प्रभाव वाले सतना जिले की रैगांव सीट पर विधानसभा के उपचुनाव हैं। यह सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। जुगल किशोर बागरी इस सीट पर चुनाव जीतते रहे हैं। अजय सिंह की उपेक्षा कर कांग्रेस के लिए उपचुनाव जीतना मुश्किल भरा है। यही कारण है कि पिछले दिनों जब अजय सिंह का जन्मदिन आया तो उनके घर बधाई देने पहुंचने वालों में राज्य के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा और पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी थे। इन मुलाकातों के बाद अजय सिंह के पार्टी छोड़ने की चर्चाएं भी चल निकलीं। इन चर्चाओं पर

अजय सिंह ने कहा कि मैं कांग्रेसी था और रहूंगा। इसी तरह की चर्चाएं पूर्व में अरुण यादव की भी चलती रही हैं। निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर सीट के समीकरण कमलनाथ के अनुकूल बनते दिखाई दे रहे हैं। जबकि जोबट में पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया को एक बार फिर अपना वर्चस्व सिद्ध करना पड़ रहा है।

खंडवा में दोनों ओर भितरघात

इस लोकसभा सीट पर भाजपा का कब्जा रहा है भाजपा के नंदकुमार सिंह चौहान यहां से सांसद थे, लेकिन कोरोनाकाल में उनका निधन होने से यह सीट खाली है। यहां पर भाजपा को सहानुभूति वोट मिलने की उम्मीद है, लेकिन नंदकुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन पूर्व मंत्री के अलावा अर्चना चिटनीस और कृष्ण मुरारी मोघे टिकट की दौड़ में शामिल हैं। खंडवा लोकसभा सीट पर कुल 19 लाख 59 हजार 760 मतदाता हैं। इनमें से 10 लाख 4 हजार 509 पुरुष और 9 लाख 54 हजार 854 महिला मतदाता हैं। 73 थर्ड जेंडर हैं। उपचुनाव के लिए संसदीय क्षेत्र में आने वाले खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और देवास जिले की 8 विधानसभाओं में 2367 मतदान केंद्र निर्धारित किए हैं। कोरोना के मद्देनजर करीब 500 सहायक मतदान केंद्र और बनाने का प्रस्ताव है। सन् 1962 से अब तक हुए 15 चुनाव में इस सीट पर 8 बार भाजपा तथा बीएलडी और 7 बार कांग्रेस का कब्जा रहा है। वर्ष 2019 के चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की थी। 76.80 फीसदी मतदान हुआ था। भाजपा प्रत्याशी नंदकुमार सिंह चौहान को 8,38,909 यानी 57.14 फीसदी और कांग्रेस के अरुण यादव को 5,65,566 यानी 38.52 फीसदी वोट मिले थे। वैसे नंदकुमार सिंह चौहान और अरुण यादव के बीच तीन बार मुकाबला हुआ। इनमें दो बार अरुण यादव को हार का सामना करना पड़ा है। दिवंगत सांसद चौहान 6 बार खंडवा लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमित होने के बाद इलाज के दौरान सांसद चौहान की मौत हो जाने से इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है।

भाजपा के सामने यहां पर उम्मीदवार घोषित करने को लेकर असमंजस की स्थिति है। इधर कांग्रेस से अरुण यादव को टिकट मिलने की उम्मीद है, लेकिन बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा अपनी पत्नी को उम्मीदवार बनाने के लिए ताकत लगा रहे हैं। ऐसे में भितरघात का डर भी कांग्रेस को सता रहा है।

जयस मैदान में उतरा तो दोनों का नुकसान

जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन यानी जयस की खंडवा लोकसभा सीट और जोबट विधानसभा सीट पर सक्रियता काफी बढ़ गई है। जयस दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका है। संगठन के अध्यक्ष हीरालाल अलावा ने खुद ये बात कही है। यह भी संभावना है कि अगर कांग्रेस किसी युवा आदिवासी को टिकट देती है तो दोनों मिलकर भी चुनाव लड़ सकते हैं। दोनों ही सीटों पर आदिवासी वोट निर्णायक होते हैं। यही वजह है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इन सीटों पर सक्रियता बढ़ा दी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जयस के चुनाव लड़ने की स्थिति में भाजपा और कांग्रेस दोनों को नुकसान होना तय है। ऐसी खबरें हैं कि जयस जोबट सीट पर नीतेश अलावा को टिकट दे सकती है। बीते दिनों महू में जयस के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए नीतेश अलावा को निलंबित कर दिया गया था।

26 लाख से ज्यादा मतदाता चुनेंगे अपना प्रतिनिधि

खंडवा लोकसभा सहित पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव विधानसभा उपचुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने पूरी तैयारी कर ली है। 26 लाख से ज्यादा मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। मतदान के लिए 3 हजार 204 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 9 हजार 650 बैलेट और 9 हजार 370 कंट्रोल यूनिट जिलों में मतदान के लिए उपलब्ध हैं। चुनाव कराने के लिए 20 हजार अधिकारी-कर्मचारी लगेंगे, जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है। अब चुनाव क्षेत्रों में बिना निर्वाचन आयोग की अनुमति न तो कोई नवीन पदस्थापना होगी और न ही स्थानांतरण। निर्वाचन कार्यालय ने सामान्य प्रशासन विभाग को आदर्श आचरण संहिता का पालन कराने संबंधी पत्र भी भेज दिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। चुनाव के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। मतदान केंद्र पर यदि मतदाता मास्क पहनकर नहीं आएगा तो उसे उपलब्ध कराया जाएगा। 80 वर्ष से अधिक आयु, दिव्यांग और कोरोना से प्रभावित या संदिग्ध व्यक्ति को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा दी जाएगी।

किस चुनाव क्षेत्र में कितने मतदाता

खंडवा लोकसभा क्षेत्र

- कुल मतदाता- 19,68,389
- पुरुष मतदाता- 10,07,135
- महिला मतदाता- 9,61,184
- अन्य मतदाता- 70

पृथ्वीपुर विधानसभा

- कुल मतदाता- 1,98,168
- पुरुष मतदाता- 1,04,857
- महिला मतदाता- 93,310
- अन्य मतदाता- 1

रैगांव विधानसभा

- कुल मतदाता- 2,06,910
- पुरुष मतदाता- 1,09,750
- महिला मतदाता- 97,160

जोबट विधानसभा

- कुल मतदाता- 2,75,237
- पुरुष मतदाता- 1,37,625
- महिला मतदाता- 1,37,612

कांग्रेस की ओर से सचिन बिरला, राजनारायण सिंह पुर्नी भी दावेदार हैं।

रैगांव में भाजपा को खतरा

सतना की रैगांव विधानसभा सीट भाजपा से दिवंगत विधायक जुगल किशोर बागरी के निधन से खाली हुई थी। यहां से उनके बड़े पुत्र पुष्पराज बागरी टिकट मांग रहे हैं, वहीं उनकी छोटी बहू वंदना बागरी भी दावेदारी कर रही हैं। इसके अलावा भाजपा नेत्री रानी बागरी और नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश कोरी भी दौड़ में हैं। दूसरी तरफ संघ से जुड़े सत्यनारायण बागरी और प्रतिमा बागरी भी दावेदारी जता रहे हैं। एक सीट के लिए इतने सारे लोगों का दावा अंतर्विरोध की वजह बन सकती है, जिससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। भाजपा यहां सहानुभूति वोट की उम्मीद रखे हुए है लेकिन बागरी परिवार के बीच मचा द्वंद्व पार्टी पर भारी पड़ सकता है। स्व. जुगलकिशोर बागरी के परिवार के किसी सदस्य को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन एक से अधिक दावेदार होने के कारण अभी फैसला नहीं हो सका है। उधर, कल्पना वर्मा को पिछले विधानसभा में 48 हजार से अधिक वोट मिले थे। वहीं उषा चौधरी बसपा से पिछला विधानसभा चुनाव लड़ी थीं, कांग्रेस इन्हें अपने पक्ष में लाकर टिकट दे सकती है।

जोबट में जयस निर्णायक

आलीराजपुर के जोबट विधानसभा उपचुनाव में मतदाता 16वीं बार विधायक चुनेंगे। विधानसभा में 2,75,205 मतदाता हैं। इनमें 1,37,638 पुरुष तथा 1,37,567 महिलाएं हैं। 325 केंद्रों पर मतदान होगा, जिनमें 49 संवेदनशील हैं। बता दें कि करीब पांच माह पूर्व कांग्रेस की विधायक रहीं कलावती भूरिया का कोरोना के चलते निधन हो गया था। उसके बाद से यह सीट रिक्त है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां जनदर्शन यात्रा निकालने के साथ ही इमोशनल कार्ड भी खेल चुके हैं। मुख्यमंत्री ने अपने हेलीकॉप्टर में आदिवासी को सवार कराकर यह संदेश देने की कोशिश की यह सिर्फ शिवराज सरकार में ही संभव है कि जो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर न बैठा

हो वह सीधे हेलीकॉप्टर में बैठ गया। हालांकि, कांग्रेस ने इस पर फोटो जारी करते हुए कहा था कि ये वो आदिवासी हैं, जो भाजपा और संघ से जुड़े हैं। इस सीट पर आदिवासी संगठन जयस भी भाजपा का खेल बिगाड़ सकता है। कांग्रेस अगर यहां कांतिलाल भूरिया की पसंद का उम्मीदवार उतारती है तो भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती है। जोबट में कांग्रेस को ऐसे किसी आदिवासी चेहरे की तलाश है, जो जीत सके। यहां सुलोचना रावत, दीपक भूरिया, महेश पटेल दावेदार हैं।

पृथ्वीपुर उपचुनाव सहानुभूति भरोसे

पृथ्वीपुर में शिशुपाल सिंह यादव (सपा से नंबर दो पर रहे थे, अब भाजपा में) और अभय प्रताप सिंह की पिछले चुनाव में जमानत जब्त हो गई थी। इसके अलावा भाजपा, कांग्रेस के किसी चेहरे को मैदान में उतार सकती है। यह सीट पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह के दबदबे वाली मानी जाती रही है, लेकिन कोरोना में उनके निधन से यह सीट भी खाली हो गई। कांग्रेस चाहती है कि उनके परिवार से किसी को टिकट देकर सहानुभूति वोट बटोरे, वहीं शिवराज ने जनदर्शन के दौरान यहां पर घोषणाओं का पिटारा खोलते हुए कई घोषणाएं की हैं। भाजपा की अनीता नायक 2013 और 2018 तक विधायक रहीं, लेकिन वे ज्यादा सक्रिय नहीं रही। इस बार भाजपा से गनेणी लाल दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी दल को 5 बार के विधायक रहे बृजेंद्र सिंह राठौर के परिवार से लड़ना है, जिनको कांग्रेस के गढ़ रहे इस इलाके में सहानुभूति वोट भी मिलने की उम्मीद है।

सत्तारूढ़ भाजपा चारों सीटें जीतकर 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव का आधार मजबूत करना चाहती है। लेकिन दमोह उपचुनाव में मिली हार के बाद पार्टी काफी सतर्क है और उसे जीत की राह आसान नहीं लग रही है। शायद यही वजह है कि देश के दूसरे राज्यों में उपचुनाव की घोषणा में मप्र को शामिल नहीं किया गया है। आधार मजबूत करने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी को संभवत: और वक्त चाहिए। भाजपा ने चुनाव की घोषणा से पहले अपने नेताओं को मैदान में उतार दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खंडवा और रैगांव का दौरा भी कर चुके हैं। उधर, दमोह के नतीजे से उत्साहित कांग्रेस भी तैयारी में जुट गई है। पार्टी का मानना है कि लोगों में भाजपा के प्रति भारी रोष है। इसलिए सत्ता में होने के बाद भी उसे दमोह में हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस का दावा है कि दूसरे उपचुनावों में भी नतीजे यही होंगे।

छिंदवाड़ा कांग्रेस मॉडल पर उपचुनाव लड़ेगी कांग्रेस

मप्र का 2018 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने विकास के छिंदवाड़ा मॉडल को आधार बनाकर लड़ा और जीता था। वहीं कांग्रेस ने दमोह उपचुनाव में छिंदवाड़ा कांग्रेस मॉडल को अपनाकर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ खंडवा लोकसभा के साथ ही पृथ्वीपुर, रैगांव और जोबट विधानसभा क्षेत्र में छिंदवाड़ा कांग्रेस मॉडल को लागू करके चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पार्टी को भरोसा है कि इससे कांग्रेस चारों उपचुनाव वाले क्षेत्रों में इससे भाजपा को मात दे सकती है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार दमोह उपचुनाव में कमलनाथ ने छिंदवाड़ा मॉडल को हुबहू लागू किया था, इसके चलते यहां कांग्रेस को जीत भी मिली। अब इसी तर्ज पर तीनों विधानसभा उपचुनाव और खंडवा लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस छिंदवाड़ा मॉडल को लागू कर रही है। इसके लिए पार्टी ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। जल्द ही छिंदवाड़ा मॉडल के अनुसार उपचुनाव वाले क्षेत्रों में कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदारी देकर सक्रिय किया जाएगा। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पिछले 25 साल से कांग्रेस छिंदवाड़ा में इसलिए मजबूत है, क्योंकि वहां पर कमलनाथ द्वारा तैयार मॉडल के आधार पर संगठन काम कर रहा है। छिंदवाड़ा में 6 भागों में जिला कांग्रेस को विभाजित कर बूथ स्तर तक जिम्मेदारी बांट रखी है। वहां जिला कांग्रेस अध्यक्ष, पर्यवेक्षक, ब्लॉक अध्यक्ष, 8-12 बूथ पर एक क्षेत्रीय अध्यक्ष, 2-3 बूथ पर एक समन्वयक, 1 बूथ पर संयोजक बनाकर ग्राउंड स्तर पर कांग्रेस काम करती है। इसी आधार पर काम करते हुए कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा जिले की सातों सीटों पर कब्जा जमाया था।

देश में एक तरफ किसान कृषि कानून के विरोध में धरना दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने के अभियान में जुटी हुई है। वहीं देश में एक ऐसी तस्वीर भी सामने आ रही है, जिसके तहत किसान मजदूर बनकर रह गया है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में खुलासे के बाद सरकार की नीतियों पर सवाल उठने लगा है।

मजदूरी करके किसान होगा खुशहाल?

अगले साल यानी 2022 में देश को किसानों की आय को 2015-2016 की आय से दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल करना है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 77वें दौर के 'परिवारों की भूमि व पशुधन संपत्ति और खेती पर निर्भर परिवारों की स्थिति का आंकलन' नामक सर्वेक्षण से कुछ संकेत मिलते हैं कि यह लक्ष्य हासिल किया भी जा सकता है अथवा नहीं। इस सर्वेक्षण में 2018-2019 की स्थितियों को शामिल किया गया है और इससे पहले ऐसा ही एक सर्वेक्षण 2012-2013 में किया गया था। इस तरह यह सर्वेक्षण मौजूदा सरकार के कार्यकाल के दौरान किसानों की स्थिति को दर्शाने वाला पहला सर्वेक्षण भी है।

किसानों की मासिक आय 2012-2013 की तुलना में 59 फीसदी बढ़ी है। इस तरह से यह 7.8 फीसदी की वार्षिक वृद्धि है। इस वृद्धि का सही अर्थ समझने के लिए हमें वार्षिक महंगाई दर को भी देखना होगा। सर्वेक्षण यह भी दिखाता है कि इसके दो दौर अथवा 2012-2018 की समयावधि में खेती से होने वाली आय घटी है। एक कृषि-परिवार के लिए आय के तीन मुख्य स्रोत हैं- खेती, मजदूरी और पशुधन। फिलहाल एक कृषि-परिवार के लिए उसकी कुल आय में से खेती से होने वाली आय सिर्फ 38 फीसदी रह गई है, जो 2013 में 48 फीसदी थी।

यानी खेती पर निर्भर एक किसान की कमाई का बड़ा जरिया खेती की बजाय मजदूरी और पशुधन हैं। इसमें भी बड़ा योगदान मजदूरी का है, जिससे मिलने वाला पैसा उसके परिवार की आय में सबसे ज्यादा योगदान देता है। इसका मतलब यह है कि एक किसान परिवार, पैसे के लिए खेती से ज्यादा मजदूरी पर निर्भर है। खेती से उसकी आय दोगुनी करने के लिए उसके परिवार की आर्थिकी में बुनियादी बदलाव की जरूरत है। सवाल यह है कि 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने के लिए कहां ध्यान केंद्रित करना होगा? इसका सीधा सा जवाब है कि इसके लिए खेती से होने वाली उसकी आय पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। हम यह नहीं मान सकते कि 2022 तक यह आय दोगुनी होकर किसी किसान परिवार की कुल आय को दोगुना कर देगी।

किसानों के लिए व्यापार की स्थितियां लंबे समय से अनुकूल नहीं हैं, और वे अपनी फसल का उचित मूल्य भी नहीं पा रहे हैं। उनकी आय का दूसरा बड़ा हिस्सा पशुधन से आता है। आज की हकीकत यह है कि इसकी आर्थिकी, खाद्यान्न से भी बड़ी है। इस क्षेत्र में तेज वृद्धि के बावजूद पशुधन से होने वाली आय को इतना नहीं बढ़ाया जा सकता कि उससे किसान की कुल आय दोगुनी हो जाए। इस तरह हम देखें तो हमें किसान की कुल आय बढ़ाने के लिए तीसरे हिस्से, यानी मजदूरी पर फोकस करना चाहिए। 2018 के बाद से देश में रोजगार का परिदृश्य बदतर बना हुआ है। पहले 2016 से अर्थव्यवस्था में गिरावट आई और फिर उसके बाद नोटबंदी ने असंगठित क्षेत्र को झटका दिया। इसके बाद हम जानते ही हैं कि कोरोना महामारी ने इस क्षेत्र को गहरा आघात दिया है।

अगर किसान परिवार, मजदूरी के जरिए अपनी आय दोगुनी करने की सोचते हैं तो पहले यह देखना पड़ेगा कि नौकरियां हैं कहां? फिलहाल बेरोजगारी दर पिछले कई दशकों में सबसे ज्यादा है। यहां तक कि यह बेरोजगारी ऐसी है कि अधिक से अधिक लोग खेती पर लौट आए हैं, भले ही उन्हें इसके लिए पर्याप्त मेहनताना भी न मिल रहा हो। चूंकि हमारे पास किसानों की तुलना में अधिक खेतिहर मजदूर हैं, और किसान मजदूरी से अधिक कमा रहे हैं, इसलिए यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के परिदृश्य को और बिगाड़ने वाली है। इससे कृषि क्षेत्र में ज्यादा लोग आएंगे और उनकी आय कम होगी, चाहे वह किसान हों या मजदूर। इससे आने वाले समय में किसानों की आय दोगुनी करने का वादा पूरा नहीं होगा। इससे भी खराब बात यह कि इससे गरीबी कम करने की योजना खतरे में पड़ेगी। खेती को कुल आर्थिक वृद्धि की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी कम करने में दोगुना असरदार कारक माना जाता है। अब, जो क्षेत्र पहले से संकट में घिरा हो, उसमें अगर रोजगार के लिए भीड़ बढ़ जाती है तो बहुत संभव है कि इससे किसानों की आय घटने लगे और उनकी गरीबी कम न हो। इस तरह देखें तो किसानों की आय दोगुनी करना और उससे राष्ट्रीय आय भी बढ़ाना सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है।

● **राजेश बोरकर**

हर साल 63 हजार करोड़ की उपज नहीं बेच पाते किसान

भारत के किसानों को हर साल लगभग 63 हजार करोड़ रुपए का नुकसान इसलिए हो जाता है, क्योंकि वे अपनी उपज बेच ही नहीं पाते। दिलचस्प बात यह है कि इस राशि से लगभग 30 फीसदी अधिक खर्च करके सरकार किसानों को इस नुकसान से बचा सकती है। यह बात तीन साल पहले केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुना करने के लिए बनाई गई दलवाई कमेटी ने कही थी। कमेटी के मुताबिक फलों और सब्जियों के उत्पादन पर खर्च करने के बाद जब फसल को बेचने का समय आता है तो अलग-अलग कारणों के चलते यह फसल बर्बाद हो जाती है। कमेटी का अनुमान है कि ऐसा न होने पर किसानों को हर साल 63 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होता है। दिलचस्प बात यह है कि देशभर में कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना खर्च किया जाना चाहिए, उसका 70 फीसदी नुकसान किसान को एक साल में हो जाता है।

भारत अब दो तरह के मुख्यमंत्रियों का देश बन गया है। एक वे हैं जो क्षेत्रीय दलों के उभरते सितारे हैं और हर चुनाव के साथ राजनीति पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। दूसरी तरह के मुख्यमंत्री वे हैं जो दो बड़े राष्ट्रीय दलों के अस्थायी प्रादेशिक चेहरे हैं और जिनकी हुकूमत अपने पार्टी आलाकमान के फैसले पर ताश के महल की तरह ढह जाती है। निरंतर उत्कर्ष की ओर बढ़ते अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, और जगन मोहन रेड्डी सरीखे मुख्यमंत्रियों के साथ-साथ कांग्रेस और भाजपा के कमजोर होते मुख्यमंत्री भी हैं जिन्हें आलाकमान जरूरत पड़ने पर हटाकर ज्यादा 'फायदेमंद' चेहरे को सामने ले आता है।

उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत और कर्नाटक के बीएस येदियुरप्पा से लेकर गुजरात के विजय रूपाणी और अब पंजाब के अमरिंदर सिंह तक को राजनीतिक मजबूरियों के चलते या मनमर्जी से दरकिनार करने या हटा देने में राष्ट्रीय दलों के शीर्ष नेतृत्व को कोई हिचक नहीं होती, जबकि येदियुरप्पा या अमरिंदर सरीखे नेता दबदबा रखते हैं, और अमरिंदर ने तो मोदी लहर में भी कांग्रेस को चुनाव जितवाया। इनकी तुलना दूसरी तरह के मुख्यमंत्रियों से कीजिए, जो क्षेत्रीय दलों के कर्ताधर्ता हैं, जैसे पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, दिल्ली के केजरीवाल, आंध्र प्रदेश के जगन रेड्डी, तमिलनाडु के एमके स्टालिन। इन सबकी धीरे-धीरे एक राष्ट्रीय छवि और हैसियत बन रही है, जो मोदी की भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकते हैं और प्रबल चुनौती के रूप में उभर भी रहे हैं।

बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा सामने लाना महत्वपूर्ण है, और क्या वोट उस चेहरे के लिए या पार्टी के लिए या मोदी या गांधी परिवार के रूप में पार्टी सुप्रीमो के लिए ही डाले जाते हैं? इन सवालों के जवाब आसान नहीं हैं, और जवाब प्राय: व्यापक राजनीतिक परिस्थिति अथवा प्रदेश-केंद्रित स्थिति पर निर्भर करते हैं। लेकिन यह तो साफ है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, कांग्रेस और भाजपा आलाकमान के हुक्मनामे को ही तरजीह देती दिख रही हैं, और मुख्यमंत्रियों का बस इस्तेमाल करना चाहती हैं। ये पार्टियां राज्यों के लिए लोकलुभावन वादों और कामकाज की पंचवर्षीय योजना पर अमल करती हैं। इनका मूल सूत्र यह है कि चुनाव से पहले एक ऐसा चेहरा पेश करो जो जीत दिला सकता हो, और वह सरकार बना ले तो उसके कामकाज पर नजर रखो, और अगर वह एक थाती से ज्यादा एक बोझ साबित हो रहा या रही हो तो अगले चुनाव से ठीक पहले फिर लोकलुभावन राजनीति का सहारा लेते हुए उसे बदल डालो।

भाजपा ने लगातार तीन मुख्यमंत्रियों रावत, येदियुरप्पा, और रूपाणी को हटा दिया। इस बीच कांग्रेस ने पंजाब में अमरिंदर सिंह को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को गद्दी सौंप दी और अब वह राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कुर्सी की लड़ाई से निपटने में व्यस्त है। रावत और रूपाणी भले छोटे राजनीतिक कद वाले रहे होंगे लेकिन अमरिंदर सिंह और येदियुरप्पा को राजनीतिक और चुनावी लिहाज से कम कद्दावर कैसे माना जा सकता है। लेकिन कांग्रेस और भाजपा में कमान तो आलाकमान के हाथों में ही है और ताकतवर नेता भी उसकी मर्जी के मोहताज हैं।

यह तो पहले से स्पष्ट है कि कांग्रेस में एक ताकतवर आलाकमान ढांचा हमेशा मौजूद रहा है, जहां गांधी परिवार को छोड़कर हर कोई एक सीमा के बाद ताकत विहीन हो जाता है। लेकिन जिस मुख्यमंत्री ने आपको उन मात्र तीन राज्यों में से एक में चुनाव जिताया जिनमें आज आप सत्ता में हैं, और जबकि आप अपने बूते वोट हासिल करने में असमर्थ दिख रहे हों, तब उसे हटा देना कुछ अलग ही मामला है। बाकी दो राज्यों, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अशोक गहलोत और भूपेश बघेल की गद्दी डगमग ही है और वे इंतजार कर रहे हैं कि आलाकमान की नजर न जाने कब टेढ़ी हो जाए। जब मोर्चा लेकर चुनाव जिताने वाले मुख्यमंत्री को चलता किया जा सकता है, तब चुनाव के बाद कुर्सी की भारी खींचतान के बाद उस पर बिठाए गए नेता कब तक भरोसे से बैठे रह सकते हैं?

देश में जिन राज्यों में भाजपा और कांग्रेस का शासन है, वहां के मुख्यमंत्री की अपेक्षा क्षेत्रीय दलों के मुख्यमंत्री काफी ताकतवर हैं। इसकी वजह यह है कि इन मुख्यमंत्रियों को स्वयं ही निर्णय लेना पड़ता है, जबकि भाजपा-कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को आलाकमान की मर्जी के अनुसार काम करना पड़ता है।

रीजनल स्टार दमदार

क्यों बदल रहे हैं मुख्यमंत्री?

ऐसा लगता है कि भाजपा में मुख्यमंत्रियों के बदलने का दौर है। क्या वजह है इस बदलाव की? मुख्यमंत्रियों की अक्षमता, स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक समीकरणों का दबाव या फिर और कुछ? पिछले चंद महीनों में तीन प्रदेशों में चार मुख्यमंत्री, जबकि मोदी के पहले कार्यकाल में एक भी मुख्यमंत्री नहीं बदला। उस समय कहा गया कि जिसे मौका दिया है, उस पर भरोसा करना चाहिए। मुख्यमंत्रियों के इस तरह बदलने का चलन कांग्रेस में रहा है। एक स्वाभाविक-सा सवाल उठता है कि क्या भाजपा का कांग्रेसीकरण हो रहा है? यह शायद इस राजनीतिक परिघटना का अति सरलीकरण होगा। यह भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीयकरण की राजनीति करते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है।

भाजपा मोदी से लेकर शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, वसुंधरा राजे आदि और अब योगी आदित्यनाथ के नाम लेकर अपने ताकतवर प्रादेशिक नेताओं की मिसाल देती रही है लेकिन ऐसा लगता है कि अब वह अपने मुख्यमंत्रियों को कुर्सी के खेल में उलझाकर संतुष्ट हैं। तीन मुख्यमंत्रियों की विदाई के बाद शायद हरियाणा के मनोहर खट्टर 'उस' फोन का इंतजार करते दिन काट रहे हैं। चौहान भी इस बार अपनी गद्दी के लिए पार्टी के आला नेताओं के शुक्रगुजार हैं इसलिए उन्हें कर्नाटक के बासवराज बोम्मई की तरह उनके इशारे पर ही चलना होगा।

भाजपा के दो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिसवा सरमा फिलहाल मजबूत दिखते हैं लेकिन योगी का भविष्य अगले साल होने वाला चुनाव तय करेगा, और सरमा को भी अति आत्मविश्वास नहीं पालना चाहिए। आखिर उनकी पूर्ववर्ती सर्वानंद सोनोवाल को दूसरी बार गद्दी नहीं सौंपी गई जबकि भाजपा ने उनके कार्यकाल में ही चुनाव जीता। भाजपा और कांग्रेस के आज अधिकतर मुख्यमंत्रियों के हाथ से अपनी जमीन और सत्ता खिसक रही है, चुनावी दृष्टि से न सही मगर राजनीतिक दृष्टि से तो खिसक ही रही है। दूसरी ओर वे मुख्यमंत्री हैं, जो क्षेत्रीय दलों के नेता हैं। ममता बनर्जी ने अपने राज्य में शक्तिशाली भाजपा को पैर जमाने नहीं दिया, बल्कि एक छोटे क्षेत्रीय दल की नेता के नाते उन्होंने कहीं ज्यादा बड़ा कद बना लिया है। केजरीवाल भी ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी जमीन मजबूती से थाम रखी है और मोदी के खिलाफ मुखर रहे हैं।

आंध्रप्रदेश में जगन मोहन रेड्डी काफी बेहतर काम कर रहे हैं, जिसकी तस्दीक हाल में हुए स्थानीय चुनावों ने भी की है। तमिलनाडु में स्टालिन ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने कामकाज से सबको आश्चर्य में डाला है और सत्ता में उनके पहले 100 दिन उनकी सफलता की कहानी कह रहे हैं। क्षेत्रीय दलों के मुख्यमंत्री राजनीतिक और चुनावी दृष्टि से मजबूत होते जा रहे हैं, उनका कद भी बड़ा हो रहा है जबकि राष्ट्रीय दलों के मुख्यमंत्री उनकी तुलना में फीके नजर आ रहे हैं। ममता और जगन सरीखे मुख्यमंत्री जिस तरह अपने बूते ताकतवर नेता के रूप में उभर रहे हैं और अमरिंदर जैसे नेता जिस तरह हाशिये पर पहुंच रहे हैं वह इस भारी अंतर को उजागर कर रहा है।

उधर, कांग्रेस पार्टी ने सबको हैरत में डालते हुए एक दलित सिख चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री चुनकर मौजूदा सियासी बिसात में एक शानदार चाल चली है। एक दलित सिख का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना और एक जाट सिख नेता नवजोत सिंह सिद्धू का राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर होना सिख-बहुल राज्य में एक सशक्त समीकरण बनाता है। चन्नी एक रामदसिया सिख हैं, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम इसी समुदाय से आते थे। कांग्रेस अपने इस ताजा फैसले से शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) और बसपा के बीच गठबंधन का असर नगण्य होने की उम्मीद कर सकती है। अकाली दल और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी दलित डिप्टी सीएम के चुनावी वादे के साथ इस समुदाय को लुभाने की कोशिशें की जा रही हैं।

बहरहाल, पंजाब और गुजरात में हुए बदलाव दोनों पार्टियों के आलाकमानों के लिए अलग-अलग नतीजों वाले हैं। भाजपा के लिए तो और ही कुछ दांव पर था। विचार यह था कि मतदाताओं के सामने 'नई सरकार' लाकर सत्ता विरोधी लहर पर काबू पाया जाए और पाटीदारों की नाराजगी को भी खत्म किया जाए। इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को सत्ता से बाहर किया और उनकी पूरी मंत्रिपरिषद का भी बोरिया-बिस्तर समेट दिया। आप मोदी-शाह पर आरोप लगा सकते हैं कि वे परोक्ष रूप से (नौकरशाहों के एक समूह के जरिए) गुजरात की सत्ता चला रहे हैं, लेकिन वह मोदी ही हैं जिन्हें लोग वोट देते हैं और वह अपने उन सिपहसालारों को बदल देते हैं जो प्रदर्शन में नाकाम साबित होते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर कुछ भी दांव पर नहीं लगा था। यह कवायद गुजरात में भाजपा के हित में ही थी और उस लिहाज से देखा जाए तो पार्टी आलाकमान सफल रहा है, यह बात ज्यादा मायने नहीं रखती कि अगले साल चुनावों में नतीजा क्या होगा।

भाजपा और कांग्रेस की कार्यशैली का फर्क दोनों की राजनीतिक स्थिति में नजर आता है। भाजपा लगातार मजबूत हो रही है और कांग्रेस कमजोर। भाजपा और कांग्रेस की कार्यशैली में यह फर्क तब तक तो बना ही रहेगा, जब तक गांधी परिवार कांग्रेस को चला रहा है। रही बात भाजपा के कांग्रेसीकरण की तो वह उसकी कार्यशैली, विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण कभी नहीं हो पाएगा। एक और कारण है, जिसकी वजह से भाजपा का कभी कांग्रेसीकरण नहीं होगा। वह है, भाजपा का हमेशा परिवार रहेगा, लेकिन वह कभी परिवार की पार्टी नहीं होगी। भाजपा में हर तीन साल में राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष बदल जाता है। सामान्य कार्यकर्ता के मन में यह भरोसा है कि वह संगठन और सरकार के शिखर तक पहुंच सकता है।

● **रजनीकांत पारे**

प्रधानमंत्री का अपना वोट है

यह सही है कि पार्टी के अलावा प्रधानमंत्री का अपना वोट है। वह जब खुद के लिए लोकसभा चुनाव में वोट मांगने जाते हैं तो जितने लोग भाजपा का समर्थन करते हैं, वे सब विधानसभा चुनाव में नहीं करते। कई मामलों में यह अंतर 5 से 19 फीसदी तक का होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि राज्य के नेतृत्व पर लोगों का उतना भरोसा नहीं रहता। पार्टी इस अंतर को कम करना चाहती है। इसके लिए विश्वसनीय और जनाधार वाले नेता चाहिए। जो मोदी के अतिरिक्त वोट की मदद से हार को जीत में बदल सकें। यह काम बहुत आसान नहीं होता। मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने 13 राज्यों में 19 मुख्यमंत्री बनाए हैं। योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा सरमा, सर्वानंद सोनोवाल, देवेंद्र फडणवीस, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, पुष्कर सिंह धामी, जयराम ठाकुर, बिप्लब देब, मनोहर लाल खट्टर, रघुबर दास, लक्ष्मीकांत पारसेकर, प्रमोद सावंत, बीरेन सिंह, पेमा खांडू, आनंदी बेन पटेल, विजय रूपाणी, भूपेंद्र पटेल, बासवराज बोम्मई। इनमें से छह को हटाया जा चुका है। ये तीन राज्यों गुजरात, गोवा और उत्तराखंड से हैं। सर्वानंद सोनोवाल को विचारधारा के प्रति ज्यादा प्रतिबद्ध और पूर्वोत्तर में पार्टी के विस्तार में भूमिका निभाने वाले हिमंता बिस्व सरमा के लिए जगह खाली करनी पड़ी। फडणवीस और रघुबरदास सत्ता से बाहर हैं। फडणवीस, उद्धव ठाकरे के धोखे का शिकार हुए और रघुबरदास अपने अहंकार और दुर्व्यवहार का। इन बदलावों से एक बात साफ है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व राज्यों में नेतृत्व की लगातार समीक्षा कर रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा कई मायनों में अहम रही। प्रधानमंत्री ने इस यात्रा के माध्यम से जहां आतंकवाद के खिलाफ जमकर हमला बोला, वहीं उन्होंने पूरे विश्व को कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा कर भारत की दरियादिली को भी दिखाया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की कूटनीति और राजनीति दोनों देखने को मिली। पहले उपराष्ट्रपति कमला हैरिस उसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भावात्मक रिश्ते को दिखाकर मोदी ने यह दर्शाने की कोशिश की कि भारत और अमेरिका कई मोर्चों पर साथ-साथ है। प्रधानमंत्री ने चीन, पाकिस्तान और तालिबान को संदेश दिया कि भारत उनकी गतिविधियों पर पूरी तरह नजर रखे हुए है। अब देखना यह है कि भारत की कूटनीति कितनी असरकारी होती है।

कूटनीति और रणनीति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बार की अमेरिका यात्रा कूटनीतिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण कही जा सकती है। पिछले डेढ़ सालों में देश और दुनिया में स्थितियां काफी कुछ बदल गई हैं। अमेरिका में बाइडेन सरकार आने के बाद वहां के राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने लोकतांत्रिक सरकार को अपदस्थ कर सत्ता हासिल कर ली है। चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के तहत वहां अपनी जड़ें रोपना चाहता है।

पाकिस्तान को भी लग रहा है कि अफगानिस्तान के सहारे वह कश्मीर में भारत को अस्थिर कर सकता है। ऐसे में अमेरिका ने ब्रिटेन, जापान और आस्ट्रेलिया के साथ भारत को शामिल करके चार देशों का जो क्वाड नामक चतुर्गुट बनाया है, वह दुनिया की बदलती स्थितियों से निपटने के लिए रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना रहा है कि भारत को अब अमेरिका से वैसी नजदीकी नहीं हासिल होगी, जो पहले थी। मगर क्वाड सम्मेलन ने उस धारणा को निराधार साबित कर दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की दुनिया के कुछ प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात और संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनके भाषण से स्पष्ट हो गया कि आने वाले समय में दुनिया के राजनीतिक समीकरण और बदलेंगे। प्रधानमंत्री का संयुक्त राष्ट्र में दिया भाषण न सिर्फ साहसिक और बेबाक था, उन देशों के लिए एक तरह से चुनौतीभरा भी था, जो भारत की तरफ टेढ़ी नजर रखते हैं। माना जा रहा है कि क्वाड का गठन चीन को चुनौती देने के मकसद से किया गया है, पर किसी भी सदस्य देश ने अभी तक उसका नाम नहीं लिया है। इस बैठक को अफगानिस्तान में हुए सत्ता परिवर्तन के मद्देनजर अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा था और सारी दुनिया की नजरें लगी थीं कि इसके सदस्य देश इस मुद्दे पर क्या रुख अख्तियार करते हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने दुनिया में लोकतंत्र की अहमियत बताते हुए रेखांकित किया कि किसी भी रूप में इसका गला घोटा जाना बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी लोकतंत्र के महत्व को रेखांकित किया और चीन व पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कह दिया कि कुछ देश अफगानिस्तान की जमीन को अपने राजनीतिक

भारत की जूनियर अफसर इमरान पर भारी

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए संबोधन में भी कश्मीर राग अलापा है। इमरान ने कहा कि दक्षिण एशिया में स्थायी शांति जम्मू-कश्मीर विवाद के समाधान पर निर्भर है। इमरान के इस प्रोपेगैंडा का भारत की एक जूनियर अफसर ने करारा जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की डिप्लोमेट स्नेहा दुबे ने जिस तीखे अंदाज में इमरान पर पलटवार किया, उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है और सोशल मीडिया पर उनके लिए नारी शक्ति हैशटैग ट्रेंड हो रहा है। स्नेहा ने इमरान खान को जवाब दिया- पूरा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हमेशा से भारत के अभिन्न हिस्से हैं और रहेंगे। इनमें पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से भी शामिल हैं, पाकिस्तान को इन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश जानते हैं कि पाकिस्तान का इतिहास आतंकियों को पालने और उनकी मदद करने का रहा है, यह पाक की नीति में शामिल है।

मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। फिर समुद्री सीमा में बेजा दखल की कोशिशों और आतंकवाद को शह देने वाले देशों की भी उन्होंने जम कर आलोचना की।

चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के तहत भारत की सीमाओं पर चुनौतियां पेश करता रहा है। पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद के प्रति उसका नरम रुख और संयुक्त राष्ट्र में उसके खिलाफ लाए गए प्रस्तावों पर विरोध में चीन का खड़ा होना भी जगजाहिर है। इसलिए अफगानिस्तान में आतंक के बल पर बनी सरकार के साथ उसका खड़ा होना दुनिया के तमाम देशों के लिए चिंता का विषय बन गया है। इससे निपटने की रणनीति में संयुक्त राष्ट्र के ढांचे को बदलने की जरूरत अब पहले से कहीं अधिक गाढ़ी हो गई है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि संयुक्त राष्ट्र में बदलाव किया जाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने न सिर्फ इसका समर्थन किया, बल्कि संयुक्त राष्ट्र और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की सदस्यता की हिमायत भी की। अमेरिका अगर इसे लेकर गंभीरता दिखाता है, तो यह निसंदेह चीन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। इस तरह इस बार की प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा न सिर्फ व्यापारिक और वाणिज्यिक, बल्कि कूटनीतिक सामरिक रणनीतिक दृष्टि से भी दूरगामी नतीजे लाने वाली साबित हो सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सयुंक्त राष्ट्र के मंच से पूरी दुनिया को काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है, खासकर दक्षिण एशियाई देशों को। चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बगैर ही बहुत ही स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है और अफगानिस्तान के बहाने नसीहतें भी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सेशन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को ही मिसाल बनाकर पेश किया और भारतीय लोकतंत्र की ताकत से रूबरू कराने की कोशिश की, ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है... एक छोटा बच्चा जो कभी एक रेलवे स्टेशन की टी स्टॉल पर अपने पिता की मदद करता था वो आज चौथी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित कर रहा है। साथ ही, ये भी समझाए कि भारत ऐसा देश है जहां दर्जनों भाषाएं, सैकड़ों बोलियां, अलग-अलग जीवन शैलियां और व्यंजन हैं, और ये जीवंत लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है।

लिहाजा याद रहे, मोदी ने अपने भाषण की अभिलाक्षणिक शैली और चेतावनी भरे लहजे में जताया भी और बताया भी, भारत बढ़ेगा तभी दुनिया बढ़ेगी... दुनिया भारत को नजरअंदाज करके नहीं चल सकती। याद रहे। दुनिया अभी से गांठ बांध ले। लगे हाथ प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये भी समझाने की कोशिश की है कि भारत को नजरअंदाज करना महंगा साबित हो सकता है, और कुछ तथाकथित ताकतवर देशों की कठपुतली बना संयुक्त राष्ट्र अब भी नहीं सुधर पाया तो आने वाला समय उसे समाप्त करने में भी नहीं हिचकेगा, क्योंकि यही दस्तूर है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र में सुधार का भी ये एक तरीके से आखिरी मौका ही है।

ठीक दो साल पहले सितंबर, 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है... पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया है। एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने उसी बात को आगे बढ़ाते हुए समझाने की कोशिश की है कि भारत का मंत्र है- 'सेवा परमो धर्म:' यानी सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। ड्यूटी है। कर्तव्य है। कोरोना वायरस को लेकर दुनियाभर के देशों के निशाने पर रहे चीन के विस्तारवादी रवैये की तरफ इशारा तो किया ही, बोले- मैं दुनिया भर के टीका निर्माताओं को भी आमंत्रित करता हूं, वे आएं और भारत में टीके का उत्पादन करें।

प्रधानमंत्री ने बताया कि मानवता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए भारत ने एक बार फिर दुनिया भर के जरूरतमंद लोगों को वैक्सीन देना शुरू किया है और भारतीय वैज्ञानिक नेजल वैक्सीन तैयार करने में भी जुटे हैं, मैं संयुक्त राष्ट्र महासभा को ये जानकारी देना चाहता हूं, भारत ने दुनिया का पहला डीएनए वैक्सीन टीका विकसित कर लिया है जो 12 साल की उम्र से ऊपर के सभी लोगों को दिया जा सकता है।

मोदी ने चीन को साफ-साफ चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जीवन रेखा हैं... हमें विस्तार और बहिष्कार की दौड़ से **उनकी सुरक्षा करनी चाहिए।** अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को नियम आधारित विश्व व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए एक सुर में आवाज उठानी होगी। वहीं अफगानिस्तान पर दुनिया को आगाह किया कि अफगानिस्तान की महिलाओं-बच्चों और अल्पसंख्यकों को मदद की जरूरत है, हमें ये मदद देकर अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि जो देश आतंकवाद का इस्तेमाल एक राजनीतिक औजार के रूप में कर रहे हैं... ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी समान रूप से बड़ा खतरा है।

● **इन्द्र कुमार**

भारत बढ़ेगा तभी दुनिया बढ़ेगी

'भारत बढ़ेगा तभी दुनिया बढ़ेगी' के नए नारे के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के तमाम मुल्कों को याद दिलाने की कोशिश की कि वो ऐसे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे लोकतंत्र की जननी के तौर पर जाना जाता है। दमदार दलील के साथ अपनी बात रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आंकड़ों के जरिए भी भारत की ताकत को समझाने की कोशिश की। बोले, 'आज विश्व का हर छठा व्यक्ति भारतीय है, जब भारतीयों की प्रगति होती है, तो विश्व के विकास को भी गति मिलती है। और इसीलिए सबसे जरूरी है कि दुनिया ये तो कतई न भूले, जब भारत बढ़ेगा तो विश्व बढ़ेगा। जब भारत सुधार करेगा तब विश्व का कायापलट होगा। ये बातें बताती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच की परवाह नहीं करते और ऐसा कोई भी मौका नहीं चूकते जब ब्रांड मोदी को प्रमोट करने का मौका हो, ये बात मैडिसन स्क्वॉयर पर अपने रॉकस्टार रूप से ठीक पहले 2014 के आम चुनाव में भी दिखा चुके हैं, खुद ही ब्रांड मोदी को प्रोजेक्ट करने के फायदे भी पिछले सात साल में अलग-अलग फोरम पर देखने को मिला है।

'काका अभी जिंदा हैं...'

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद के लिए मची रार धीमी भले पड़ गई हो, लेकिन खत्म नहीं हुई है। भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव के बीच ढाई साल के पॉवर शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही। गत दिनों इससे जुड़े एक सवाल के जवाब में टीएस सिंह देव जल्द समाधान होने की बात कही। वहीं छत्तीसगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह कहना कि 'काका अभी जिंदा हैं...' को उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी से जोड़कर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि भूपेश बघेल अपने समर्थकों में 'काका' उपनाम से जाने जाते हैं।

सिंह देव ने कहा कि अगर मीडिया यह पूछ रही है कि आगे क्या होगा तो जरूर वह सुन रही है राज्य के लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। इस दौरान उनका इशारा पावर शेयरिंग फॉर्मूले की तरफ था। उन्होंने आगे कहा कि मेरी लोगों से अपील है कि वह इन बातों पर ध्यान न दें। हम राज्य के भले के लिए काम कर रहे हैं। आगे जो भी होगा राज्य में कल्याणकारी काम होते रहेंगे। इससे पहले सिंह देव और बघेल इंडियन फार्मास्युटिकल एसोसिएशन की छत्तीसगढ़ शाखा द्वारा रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में साथ देखे गए थे।

इसी कार्यक्रम के दौरान जब भूपेश बघेल लोगों को संबोधित कर रहे थे उनके समर्थक 'काका जिंदाबाद' के नारे लगा रहे थे। तभी भूपेश बघेल अपना भाषण रोककर बोल पड़े, 'काका अभी जिंदा हैं...'। यह वीडियो क्लिप बघेल कैंप के नेताओं और समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है। खुद बघेल ने अपने ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया हुआ है। माना जा रहा है कि इस एक वाक्य से भूपेश बघेल ने बताने की कोशिश है कि मुख्यमंत्री की उनकी कुर्सी पर कोई खतरा नहीं है। इसी कार्यक्रम में टीएस सिंह देव ने भी भूपेश बघेल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी विभागों की मांग को पूरा किया है। वह इसको लेकर बहुत संवेदनशील रहे हैं। सिंह देव ने कहा कि यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग में 3900 पदों को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने कई क्षेत्रों में तरक्की की है। देश में लोग अब छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने भले ही ढाई साल से ज्यादा समय हो गया हो, लेकिन ढाई-ढाई साल के मुख्यमंत्री के कथित फॉर्मूले पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश में सीएम पद के दावेदार स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के दिल्ली दौरे के बाद फिर से राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई। फिर से चर्चा होने लगी क्या भूपेश बघेल की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अब जब वे गत दिनों दिल्ली से रायपुर लौटे, तो फिर से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदलने का सवाल सामने आ गया। इस सवाल पर टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया। सिंहदेव के इस बयान के बाद कयास लगने शुरू हो गए कि अब भी सीएम बदलने की हलचल अंदरखाने चल रही है।

स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ढाई-ढाई साल के सीएम मुद्दे पर कहा कि सभी जगह कुछ न कुछ गतिविधियां चल रही थीं। सिंहदेव ने कहा कि पंजाब में सीएम बदल गया तो क्या ये अचानक हुआ? अचानक पंजाब में भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन बड़ा फैसला हुआ, यह भी हाईकमान की इच्छाशक्ति को प्रदर्शित करता है। हाईकमान जो निर्णय लेगा स्वाभाविक है कि वह कार्य रूप में आएगा। सीएम बदलने पर हाईकमान का फैसला सुरक्षित है। ये उनका विशेषाधिकार है। फैसला भी उन्हीं के पास से आएगा। इसमें समय सीमा की बात नहीं रहती। अचानक हमने देखा कि पंजाब में निर्णय आ गया। हमने नहीं सोचा था कि पंजाब में ऐसी स्थिति आएगी। कई कारण रहते हैं, उनके आधार पर हाईकमान द्वारा निर्णय होता है।

कहने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस में 'ऑल इज वेल' है। लेकिन असलियत में यह सिर्फ ऊपरी तौर नजर आने वाला भ्रम है। अंदरूनी हकीकत कहीं ज्यादा तल्ख है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के सत्ता संघर्ष में फिलहाल तो शांति है। लेकिन इसे यहां पर उठने वाले सियासी तूफान से पहले की शांति भी कह सकते हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि कांग्रेस शासित पंजाब में हाल में नेतृत्व परिवर्तन के कारण अनिश्चितता और बढ़ गई है। बिलासपुर में कांग्रेस की स्थानीय इकाई ने एक स्थानीय नेता के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज होने के विरोध में प्रदर्शन करने के कारण पार्टी के एक विधायक को निष्कासित करने की मांग की। जिस नेता के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, वह सिंहदेव का समर्थक है।

असल में यहां नेतृत्व परिवर्तन की मांग तब जोर पकड़ने लगी जब बघेल ने जून 2021 में मुख्यमंत्री के तौर पर ढाई साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। सिंहदेव धड़े का दावा था कि आलाकमान ने 2018 में सरकार का कार्यकाल आधा पूरा होने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाने पर सहमति जताई थी। हालांकि राज्य में कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया कई बार इन दावों से इंकार कर चुके हैं।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

वरिष्ठ नेताओं में संघर्ष, कार्यकर्ताओं में टकराव

बिलासपुर पुलिस ने राज्य कांग्रेस के पूर्व सचिव पंकज सिंह के खिलाफ एक सरकारी अस्पताल के कर्मचारी के साथ कथित मारपीट को लेकर मामला दर्ज किया। अगले दिन सिंहदेव के समर्थक और कांग्रेस विधायक शैलेश पांडेय अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचे और कार्रवाई का विरोध किया। किसी का नाम लिए बगैर पांडेय ने आरोप लगाया कि वरिष्ठ नेताओं के इशारे पर कार्रवाई हुई है। बिलासपुर जिले में पार्टी की स्थानीय इकाई ने पार्टी विरोधी गतिविधियों को शह देने के लिए पांडेय को निष्कासित करने की मांग की। राजनीतिक विश्लेषक आर कृष्णदास ने कहा कि पार्टी आलाकमान जब तक नेतृत्व के मुद्दे को नहीं सुलझाता है तब तक दोनों वरिष्ठ नेताओं के बीच संघर्ष की कीमत कार्यकर्ता चुकाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब में हाल में नेतृत्व परिवर्तन ने राज्य के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अनिश्चितता की भावना पैदा की है।

महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में रोज नए गुल खिल रहे हैं। कभी शरद पवार तो कभी उद्धव ठाकरे यह संकेत दे रहे हैं कि वे भाजपा के साथ जा सकते हैं। इन दिनों प्रदेश में भाजपा नेता राव साहब दानवे और उद्धव ठाकरे की दोस्ती चर्चा का विषय बनी हुई है।

गुल खिलाने वाली दोस्ती

दोस्ती में मजाक भी खूब चलता है और उद्धव ठाकरे ने भी भाजपा नेता राव साहब दानवे को लेकर अपने बयान को मजाक बता दिया है, लेकिन उनका मजाक बताना भी डिस्क्लेमर जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उद्धव ठाकरे बचाव के लिए किसी व्यावहारिक रास्ते के तकनीकी लूप-होल की मदद ले रहे हो। दोस्ती जब दुश्मनी में बदल जाती है तो मजाक की बातें, मजाक न होकर मैसेज का शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। शिवसेना और भाजपा के मौजूदा रिश्तों के बीच उद्धव ठाकरे की बातें ऐसी ही लगती हैं।

भाजपा को भूत और भविष्य के दोस्त के तौर पर पेश करने के उद्धव ठाकरे के अंदाज को बहुत ज्यादा तूल भी नहीं दिया जाता, अगर महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल की बातों को शिवसेना नेतृत्व आगे बढ़ाते हुए नजर नहीं आता। उद्धव ठाकरे से ठीक एक दिन पहले ही चंद्रकांत पाटिल ने एक बड़ा शिगूफा छोड़ा था, दो तीन दिन में देखो। अंदाज तो चंद्रकांत पाटिल का भी मजाकिया ही था, लेकिन बात नहीं। बात बहुत गंभीर थी। करीब-करीब उतनी ही गंभीर जितनी उद्धव ठाकरे ने कही थी और फिर उसे मजाक बता दिया, आखिर उद्धव ठाकरे इतने गंभीर मजाक क्यों करने लगे हैं? आखिर क्या गम है जो हंसी-मजाक के पीछे छुपा रहे हैं?

औरंगाबाद के एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और रेल राज्यमंत्री राव साहेब दानवे के बीच चला हंसी-मजाक का दौर एक साथ कई इशारे कर रहा है और ये सिर्फ शिवसेना और भाजपा के रिश्ते तक ही सिमटा हुआ नहीं लगता। शिवसेना नेतृत्व और महाराष्ट्र से मोदी कैबिनेट में शामिल सीनियर मराठा भाजपा नेता के बीच खुशनुमा माहौल में हुई बातचीत और भी इशारे कर रही और एक इशारा ये है कि गुजरे जमाने के गठबंधन साथियों के बीच टकराव की वजह बना नारायण राणे प्रकरण करीब-करीब खत्म हो चुका है। राव साहेब दानवे के रेल राज्यमंत्री होने के कारण ही उद्धव ठाकरे ने अपनी बात भी उसी भाषा में समझाने की कोशिश की। बोले, 'मुझे एक कारण से रेलवे पसंद है... आप ट्रैक नहीं छोड़ सकते और दिशा नहीं बदल सकते... हां, लेकिन अगर कोई डायवर्जन हो तो आप हमारे स्टेशन पर आ सकते हैं, लेकिन इंजिन पटरियों को नहीं छोड़ता...।

अब इन बातों का मतलब तो साफ-साफ यही समझ आता है कि शिवसेना और भाजपा की राजनीति ट्रैक पर ही है और ट्रैक पर ही रहने वाली है। डायवर्जन को शिवसेना और भाजपा के गठबंधन के टूटने की तरह समझ सकते हैं और स्टेशन पर आने की बात को आमंत्रण के भाव से भी देखा जा सकता है। क्या उद्धव ठाकरे ऐसा बोलकर भाजपा को इंजिन और शिवसेना को पटरी बताने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब, ये कि भाजपा बेशक बड़ी राजनीतिक पार्टी हो, भाजपा भले ही नेतृत्व के काबिल हो लेकिन जमीन या कहें कि महाराष्ट्र में शिवसेना नींव की तरह है जिस पर भाजपा की राजनीति टिकी हुई है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि उद्धव ठाकरे ने बातों-बातों में अपना मैसेज मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश निश्चित रूप से की है। मानकर चलना चाहिए कि उद्धव ठाकरे के शब्दों के मतलब भाजपा में भी हाई लेवल पर निकाले जा रहे होंगे।

उद्धव ठाकरे बुलेट ट्रेन के बहाने फिर से भाजपा के सपोर्ट में खड़े होने का इशारा भी किया है। कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे का ये कहना क्या संकेत देता है- 'अगर मेरे राज्य की राजधानी (मुंबई) और उप-राजधानी (नागपुर) को जोड़ने वाली ट्रेन मुंबई-नागपुर बुलेट ट्रेन शुरू होती है तो रावसाहेब, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं।' मतलब, बस बुलेट ट्रेन चलने से भाजपा और शिवसेना के बीच हर बिगड़ी बात बन जाएगी। पूरा किस्सा सुनाने से पहले ही, अपने संबोधन की शुरुआत ही उद्धव ठाकरे ने ऐसे किया जैसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हों। रावसाहेब दानवे का नाम लेते हुए उद्धव ठाकरे ने उनको 'मेरे पूर्व मित्र-और अगर हम फिर से एक साथ आते हैं, तो भविष्य के मित्र' बोलकर किसी शक शुबहे की गुंजाइश छोड़ी है क्या? भला ऐसे भी कोई मजाक करता है क्या? एनसीपी नेता और गठबंधन सरकार में सबसे दमदार हिस्सेदार शरद पवार को ये सब तो जरा भी नहीं सुहा रहा होगा, लेकिन ज्यादा कुछ कर भी तो नहीं सकते।

● **बिन्दु माथुर**

सब एक जैसे मजाक क्यों करने लगे हैं?

उद्धव ठाकरे के मजाकिया अंदाज से ठीक एक दिन पहले एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का मिजाज भी वैसा ही देखा गया और बात दूर तलक तब जाने लगी जब कार्यक्रम का वीडियो वायरल हो गया। जिस अंदाज में चंद्रकांत पाटिल ने बात आगे बढ़ाई वो किसी संयोग जैसा नहीं बल्कि प्रयोग जैसा ही लगा। हुआ ये था कि कार्यक्रम के संचालक की तरफ से चंद्रकांत पाटिल के बारे में पूर्व मंत्री कह कर संबोधित किया जा रहा था ऐसा कई बार होने पर चंद्रकांत पाटिल ने कार्यक्रम संचालक को आगाह करते हुए टोक दिया। कार्यक्रम में संचालक को बीच में ही टोकते हुए चंद्रकांत पाटिल बोले, 'मुझे बार-बार पूर्व मंत्री... पूर्व मंत्री न कहें... दो-तीन दिन में सब समझ में आ जाएगा।' ये अंदाज भी तो मजाकिया ही लगता है, लेकिन चंद्रकांत पाटिल के ऐसा बोलने के 24 घंटे बाद ही उद्धव ठाकरे भी ठीक वैसे ही पेश आएं तो कैसे मान लिया जाए कि ये कोई प्रयोग नहीं बल्कि महज एक संयोग हो सकता है। दोनों नेताओं के बयानों के जो सियासी मायने निकाले जा सकते थे, निकाले जाने लगे। जब उद्धव ठाकरे और चंद्रकांत पाटिल की बातों पर चर्चा होने लगे तो देवेंद्र फडणवीस के भी बोलने का हक बनता ही है। देवेंद्र फडणवीस भी कह देते हैं, 'राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है... उद्धव जी ने हमारे मन की बात कही है, ये सुनकर अच्छा लगा।

'क्लाइमैक्स' की ओर सियासी कलह

पंजाब के बाद अब 'ऑपरेशन राजस्थान' की बारी है। राजस्थान में सियासी संकट के दौरान कहां तो राहुल गांधी 13 माह तक सचिन पायलट से नहीं मिले थे और अब सप्ताह में दो बार मुलाकात हो चुकी है। बदलाव का ब्लू प्रिंट तैयार हो गया है।

राजस्थान कांग्रेस के लिए अहम राज्य है। यहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट में सुलह करवाने के लिए राहुल गांधी ने कमर कस ली है। मुलाकातों का दौर जारी है। एक हफ्ते में दूसरी बार गत दिनों फिर सचिन पायलट ने राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान खास बात यह रही कि प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। वहीं इससे भी अहम बात यह भी है कि पायलट के राहुल के निवास 12 तुगलक रोड पहुंचने से पहले ही गहलोत सरकार के मंत्री रघु शर्मा वहां से निकले थे। रघु शर्मा ने राहुल गांधी से मुलाकात की। अब पिछले 7 दिनों में चले मुलाकातों के दौर के बाद दिल्ली में हुई राहुल और सचिन पायलट की मुलाकत अहम मानी जा रही है। इस दौरान राजस्थान में कांग्रेस के वर्तमान और भविष्य का खाका खींचा गया। इस बैठक के बाद पायलट राहुल के आवास से रवाना हो गए। पायलट के रवाना होने के बाद राहुल-प्रियंका और वेणुगोपाल की अहम मीटिंग हुई है। पायलट ने राहुल और प्रियंका की मुलाकात से पहले मुख्यमंत्री गहलोत के खास सिपहसालार चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने मुलाकात की। इस मुलाकात को भी अहम माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो रघु शर्मा जयपुर से मुख्यमंत्री गहलोत का मैसेज लेकर दिल्ली गए थे। साथ ही यह भी कहा जा रहा है राहुल गांधी ने ही रघु शर्मा को दिल्ली बुलाया था। राहुल ने राजस्थान के वर्तमान हालातों पर शर्मा से फीडबैक लिया है।

पंजाब के बाद राजस्थान पर कांग्रेस आलाकमान का फोकस है। पिछले दिनों कई सियासी मुलाकातों और बातचीतों का दौर चला है। सोनिया गांधी और मुख्यमंत्री गहलोत के बीच फोन पर लंबी बात हुई है। इन दोनों के बीच क्या बात हुई किसी को नहीं पता। वहीं 17 सितंबर को राहुल गांधी और सचिन पायलट की उनके निवास पर लंबी बैठक हुई। इस दौरान इन दोनों नेताओं के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। राहुल और सचिन की बीच क्या-क्या बात हुई ये केवल इन दोनों को ही पता है। इसके बाद 19 सितंबर को विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की मुलाकात संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से होती है। अब इन दोनों के बीच क्या चर्चा हुई इसके बारे में भी किसी को नहीं पता। वहीं गत दिनों पायलट ने सीपी जोशी के घर पर जाकर एक अहम मुलाकात की। सीपी जोशी वही व्यक्ति हैं जो 2008 विधानसभा चुनाव में एक वोट से अपना चुनाव हार गए थे और मुख्यमंत्री बनते-बनते रह गए थे। किसी जमाने में जोशी राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते थे।

पंजाब के बाद दिल्ली कांग्रेस हैडक्वार्टर और 10 जनपथ पर सबसे ज्यादा राजस्थान की चर्चा हो रही है। जब से कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब में दलित चरण जीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया है तब से राजस्थान की राजनीति में हलचल है। साथ ही पिछले एक हफ्ते में दिल्ली से राजस्थान तक कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ है जो आने वाले भविष्य के संकेत देता है। राहुल गांधी ने गांधी परिवार के सबसे करीबी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर को हटाकर बड़ा संदेश दिया है। अब इसके बाद इस बात को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पंजाब के बाद राजस्थान में भी राहुल गांधी चौंकाने वाले हैं।

ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि पंजाब मुख्यमंत्री को हटाए जाने के साथ ही दिल्ली और राजस्थान में ऐसा घटनाक्रम हुआ है जो बदलाव के संकेत दे रहा है। अब आपको बता देते हैं कि क्या-क्या हुआ है इन दिनों में। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी के पंजाब ऑपरेशन की तो किसी को नहीं पता था कि चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। अगर कोई कहे कि ये मुझे पता था तो वो झूठ बोल रहा है। केवल राहुल गांधी को इस बात की जानकारी थी। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं जैसे पंजाब में राहुल गांधी ने किसी को कानों-कान खबर नहीं लगने दी कि कौन मुख्यमंत्री बन रहा है ऐसा वो राजस्थान में भी करने वाले हैं।

दिल्ली में इस बात की चर्चा है कि उप्र चुनाव से पहले दलित को जिस तरह से पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया है, वैसे ही राजस्थान में किसी ब्राह्मण नेता को सत्ता की कमान सौंपी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो सचिन पायलट को एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस की कमान मिल सकती है, वहीं अशोक गहलोत को केंद्रीय नेतृत्व में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। आपको बता दें, कांग्रेस अपने दलित और ब्राह्मण वोट बैंक को फिर से अपने साथ लाना चाहती है। कहा जाता रहा है कि दलित ब्राह्मण ही कांग्रेस को वोट करते रहे हैं। दलित को पंजाब की कमान सौंपकर कांग्रेस संदेश दे चुकी है। हालांकि ये सब दिल्ली में चल रहीं चर्चाएं हैं।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

पंजाब एपिसोड के बाद पायलट समर्थक उत्साह में

पंजाब में राहुल गांधी के एक्शन के बाद पायलट समर्थकों कहना है कि राजस्थान में सरकार की कमान सचिन पायलट को सौंपी जाए। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और पायलट के करीबी राजेंद्र चौधरी ने हाल ही में बयान दिया था कि सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि जनता चाहती है कि पायलट मुख्यमंत्री बने। हालांकि, गहलोत गुट भी पलटवार कर रहा है। गहलोत कैंप का कहना है कि राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत नहीं है और मुख्यमंत्री गहलोत पांच साल सरकार चलाने में सक्षम हैं। आपको बता दें, सचिन पायलट कैंप लगातार यह मांग कर रहा है कि कांग्रेस सरकार के बचे दो साल में पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए और अगला चुनाव पायलट के चेहरे पर लड़ा जाए। इसलिए पायलट राजस्थान छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहते हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कई बार कह चुके हैं कि राजस्थान उनके करीब है। अब तो भविष्य के गर्भ में छिपा है कि आखिर राजस्थान में होने क्या वाला है।

चुनावी विस्तार

योगी आदित्यनाथ ने आखिरकार उप्र में मंत्रिमंडल विस्तार कर ही लिया और ये भी साफ हो गया कि योगी ने अपनी ही टीम बनाई है, न कि मोदी-शाह या भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की संस्तुति से किसी को कैबिनेट में लिया है। बस ये समझ में नहीं आया कि जब तीन महीने के लिए ही मंत्री बनाने थे तो अरविंद शर्मा के नाम पर योगी आदित्यनाथ को नो-एंट्री लगाकर क्या मिला? अरविंद शर्मा को भी मंत्री बना देते तो कम से कम बातें जरूर होतीं। एक तो कोरोना संकट में वाराणसी मॉडल के जरिए उनके काम को लेकर टोकेन ऑफ थैंक्स हो जाता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात की अवहेलना से भी बच जाते।

अभी योगी आदित्यनाथ ने जो वैमनस्यता मोल ली है उसका असर साफ-साफ दिखाई देने लगा है। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्या की सक्रियता योगी आदित्यनाथ के लिए उप्र भाजपा के उपाध्यक्ष अरविंद शर्मा से ज्यादा खतरनाक साबित होने जा रही है। एक भी छोटी सी चूक भारी पड़ सकती है। जितिन प्रसाद को लेकर भी असमंजस लगने लगा था, लेकिन मायावती के ब्राह्मण सम्मेलन ने लगता है उनका मंत्री पद पक्का हो गया और बाकियों को तो जातीय समीकरणों के तहत लगता है जैसे गुलदस्ते में सजाकर पेश किया गया हो। ऐसे में जबकि चुनाव की तारीख आने में ज्यादा से काफी कम वक्त बचा है, सवाल ये है कि नए नवेले मंत्री काम क्या और कितना कर पाएंगे? जितिन प्रसाद पश्चिम बंगाल चुनाव में कांग्रेस के प्रभारी बनाकर भेजे गए थे और लौटे तो कांग्रेस की बजाय भाजपा दफ्तर पहुंच गए। भगवा धारण किया और मंत्री बनाए जाने की चर्चा शुरू हो गई। केंद्र में यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री रह चुके जितिन प्रसाद अब योगी सरकार में भी मंत्री बन गए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में वो अकेले कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं।

कांग्रेस में रहते जितिन प्रसाद उप्र में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जाने जाते रहे और ब्राह्मणों के बीच पार्टी की पैठ बढ़ाने के लिए लगातार काम भी कर रहे थे, लेकिन जी-23 नेताओं के साथ में शुमार थे जिन्होंने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर निशाने पर आ गए थे। जितिन प्रसाद के पिता जितेंद्र प्रसाद को भी सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत करने के लिए ज्यादा याद किया जाता है। शाहजहांपुर से आने वाले जितिन प्रसाद कभी राहुल गांधी की युवा टोली के सक्रिय सदस्य हुआ करते थे, लेकिन चिट्ठी पर दस्तखत करने के बाद वो कांग्रेस नेतृत्व और करीबियों के निशाने पर आ गए थे। 2019 के आम चुनाव के दौरान ही जितिन प्रसाद के भाजपा ज्वाइन करने की जोरदार चर्चा रही, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने मिलकर तब मना लिया था।

योगी आदित्यनाथ सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार 6 महीने पहले ही हो चुका होता, लेकिन तब शायद वो पूरी तरह अपनी टीम नहीं बना पाए होते। अब जो लोग मंत्री बने हैं उनके सामने तो छह महीने से भी कम का कार्यकाल बचा है। जो विधायक मंत्री बने हैं उनको तो अभी अपने विभागों के काम समझने का मौका मिलेगा तब तक चुनावी माहौल जोर पकड़ लेगा और जब तक कामकाज की समझ हो पाएगी, चुनाव आयोग मतदान की तारीखों की घोषणा के साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू कर देगा। ऐसे में नए जो भी मंत्री है उनकी जिम्मेदारी सरकारी कामकाज के मुकाबले भाजपा के चुनाव प्रचार की ही ज्यादा होनी लगती है।

जितिन प्रसाद तो पहले से ही बड़ा चेहरा रहे हैं, ऐसे में जब उप्र चुनाव 2022 के लिए भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची बनती, निश्चित रूप से उनको भी शामिल किया ही जाता, लेकिन बाकी जो विधायक थे वे तो बस अपने इलाके तक सीमित रहे होंगे। अब मंत्री बन जाने के बाद उनकी भी अहमियत बढ़ जाएगी। अब से वो अपने इलाके में विधायक जी की जगह मंत्रीजी कहलाने लगेंगे और उनकी बातों का असर भी पहले के मुकाबले ज्यादा होगा।

योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के जिन नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया है, ऐसा लगता है जैसे अखिलेश यादव और मायावती के खिलाफ कोई टास्क फोर्स बना रहे हों, जो सात मंत्री बनाए गए हैं उनमें जितिन प्रसाद ब्राह्मण हैं और बाकी या तो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं या फिर दलित समुदाय से। ब्राह्मण और दलित मंत्री मायावती को काउंटर करेंगे और ओबीसी कोटे वाले अखिलेश यादव को। मायावती को घेरने के लिए भाजपा ने जितिन प्रसाद से पहले बेबी रानी मौर्य को भी मैदान में उतार दिया है और जो नए मंत्री बने हैं वे मिल-जुलकर अखिलेश यादव और मायावती से चुनावी मोर्चे पर भिड़ेंगे। जितिन प्रसाद के अलावा जिन लोगों को शपथ दिलाई गई है, वे हैं- छत्रपाल गंगवार, पलटू राम, संगीता बलवंत बिंद, संजीव कुमार गोंड़, दिनेश खटीक और धर्मवीर सिंह प्रजापति। जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री जबकि बाकियों को राज्य मंत्री बनाया गया है और इस तरह योगी कैबिनेट में एक ब्राह्मण, दो दलित, एक एसटी और तीन ओबीसी नेताओं को शामिल कर लिया गया है।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

एक-एक वोट पर नजर

माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने नए मंत्रियों को जिस तरह जातीय समीकरणों में फिट करने की कोशिश की है, साफ है कि चुनावों को देखते हुए हर वोट बैंक को ये मैसेज देने की कोशिश है कि सरकार में उनको भी प्रतिनिधित्व दिया गया है, लेकिन सवाल तो ये भी उठेगा ही कि ऐसा ही करना था तो चुनावों से ऐन पहले करने का क्या मतलब? अगर यही काम पहले किया गया होता तो उसका मतलब भी होता। भाजपा की ही केंद्र सरकार एक तरफ जातीय समीकरण पर जनगणना से परहेज कर रही है और दूसरी तरफ मंत्रिमंडल में विस्तार में जातीय समीकरणों का ध्यान रखा जा रहा है। केंद्र सरकार एक तरफ ओबीसी बिल लाकर अलग मैसेज दे रही है और सुप्रीम कोर्ट में जातीय जनगणना न कराने को नीतिगत फैसला बता रही है। कैबिनेट विस्तार के जरिए या राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हालिया उप्र दौरों का फायदा उठाकर भाजपा चाहे जिन वोट बैंक को टारगेट क्यों न करने में जुटी हो, लेकिन ये सब तो खाने के दांत ही लगते हैं, पश्चिम बंगाल चुनावों में हार की वजह मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण बताने के बाद भाजपा ये तो स्पष्ट कर ही चुकी है कि आने वाले चुनाव में वो श्मशान-कब्रिस्तान 2.0 के साथ ही उतरने वाली है और उसके आगे तो सब फेल है।

लालू भरोसे पीएम मटेरियल

नीतीश कुमार की छटपटाहट स्वाभाविक है। जेडीयू नेताओं के बीच पीएम मटेरियल समझे जाने के बावजूद नीतीश कुमार अपनी हदों की हकीकत भी समझते हैं- और हालात को बदलने की कोशिश में कोई कसर भी बाकी नहीं रखते, लेकिन राजनीतिक विरोधियों से बुरी तरह घिरे होने की वजह से होता ये है कि जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाते हैं, कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि फौरन ही दो कदम पीछे हटना पड़ता है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर अरसे बाद नीतीश कुमार को मौका मिला था और पूरा फायदा भी उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वक्त लेकर उन नेताओं के साथ मिल भी आए जो बिहार की राजनीति दूसरी छोर से करते हैं। बड़े दिनों बाद नीतीश कुमार के लिए एक ऐसे मुद्दे की तलाश पूरी हो सकी थी जिसकी बदौलत प्रधानमंत्री मोदी के साथ आमने-सामने बैठकर थोड़ा मोल-भाव कर सकें।

जातीय जनगणना पर बिहार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने का प्रस्ताव नीतीश कुमार ने काफी सोचसमझ कर स्वीकार किया था। ये फैसला भी मौजूदा राजनीतिक समीकरणों के बीच काफी जोखिमभरा रहा, लेकिन नीतीश कुमार ने नतीजों पर भी विचार किया ही होगा। बेशक जातीय जनगणना की राजनीति में भाजपा नेतृत्व के खिलाफ जाना नीतीश कुमार की राजनीतिक सेहत के लिए खतरनाक है, लेकिन इसी बहाने लालू यादव से नजदीकियां बढ़ाने का स्कोप भी तो बढ़ जाता है, एनडीए के मझधार में फंसे नीतीश कुमार को उबारने की उम्मीद भी अब सिर्फ लालू यादव से ही बची है। लेकिन लालू यादव की तरफ से नीतीश कुमार को विपक्ष का सपोर्ट सिस्टम उपलब्ध कराने का मसला है उसमें भी बड़े सारे पेंच हैं, और लालू यादव भी अगर पुत्रमोह में कोई नया स्टैंड लेते हैं तो कांग्रेस नेतृत्व का पुत्रमोह ज्यादा भारी पड़ सकता है। विपक्षी एकजुटता की राजनीति में भी इतने दांव पेच उलझे हुए हैं कि नीतीश कुमार सारी शर्तें मान लें तो भी लालू यादव कितनी मदद कर पाएंगे ये फैसला भी वो अकेले लेने की स्थिति में नहीं लगते। तब तक तो भाजपा की बल्ले-बल्ले ही समझी जाएगी।

2017 के उप्र विधानसभा चुनावों के दौरान नीतीश कुमार शुरू-शुरू में खासे एक्टिव थे, और करीब-करीब वैसे ही एक बार फिर फ्रंट फुट पर आकर खेलने लगे थे। पांच साल बाद राजनीति इतनी बदल चुकी है कि नीतीश कुमार की ताजा सक्रियता उप्र में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनावों की वजह से तो नहीं लगती। तब भाजपा भी बिहार की हार के बाद उप्र में सत्ता हासिल करने के लिए जूझ रही थी और नीतीश कुमार एक अलग मोर्चा खड़ा करने की कोशिश में रहे। चुनावों से पहले तब नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के आसपास के इलाकों में कई रैलियां की थी। फिर दिल्ली में उप्र के छोटे-छोटे दलों की बैठक बुलाई और सभी साथ आने के लिए तैयार भी दिखे। एक मीटिंग में आरएलडी नेता अजीत सिंह ने अपने बेटे जयंत चौधरी के लिए डिप्टी सीएम की शर्त रख दी। वो भी चुनाव से पहले ही घोषणा किए जाने को लेकर, वो आखिरी मीटिंग तो नहीं थी, लेकिन बाद की एक दो बैठकों के बाद नीतीश कुमार थक हार कर पटना में बैठ गए। ये सब तब भी नीतीश कुमार के लिए कोई आसान काम नहीं था।

नीतीश कुमार की रैलियों को लेकर आरजेडी के तमाम नेता काफी आक्रामक देखे गए। प्रधानमंत्री बनने को लेकर नीतीश कुमार के मन की बात भी पूछी जाने लगी। पहले तो टालने की काफी कोशिश की, लेकिन जब घिर गए तो ऐसे समझाया कि कोई किस्मतवाला ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ पाता है। ये किस्मतवाला शब्द भी नीतीश कुमार की बेचारगी तो दिखा ही रहा था, लेकिन इशारा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ ही था। उससे पहले तेल की कीमतों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक विरोधियों को टारगेट करते हुए कहा था कि अगर उनकी किस्मत से तेल की कीमतें कम हुईं तो देश का फायदा हो रहा है या नहीं। नीतीश कुमार के महागठबंधन में होने के चलते लालू प्रसाद यादव के सामने भी वैसे ही सवाल उठे, कुछ इस तरह कि नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने की बात आए तो क्या वो सपोर्ट करेंगे? लेकिन ये सब बहुत लंबा नहीं चल सका। उप्र में भाजपा की सरकार बनते ही नीतीश कुमार को भाजपा के भीतर से ही भनक लगी कि महागठबंधन छोड़कर एनडीए में नहीं लौटे तो खेल हो जाएगा। फिर क्या था, एक दिन अचानक घर से निकले और राजभवन पहुंच कर इस्तीफा सौंप दिया और **तब तक डटे रहे जब तक** नए सिरे से मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले लिए।

2020 के चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ तो गए, लेकिन भाजपा ने अपने हिस्से में इतनी ताकत तो बढ़ा ही ली थी कि पूरी मनमानी कर सके। भाजपा ने कुर्सी पर बिठा तो दिया लेकिन हाथ-पैर बांध कर। अब हाथ-पैर बंधे आदमी की छटपटाहट क्या होती है, ये नीतीश कुमार पल-पल झेल रहे हैं और ये भी महसूस कर रहे हैं कि एक बार फिर वो महागठबंधन वाले मुख्यमंत्री जैसे ही हो गए हैं। बल्कि, तब तो इतना ही होता कि लालू यादव के सरकारी कामों में दखल देने को बर्दाश्त करना पड़ता था, अब तो बगैर भाजपा नेतृत्व से मंजूरी लिए, कोई बड़ा नीतिगत फैसला भी ले पाना संभव नहीं हो रहा।

● **विनोद बक्सरी**

दोनों को एक-दूसरे की जरूरत

2014 के बाद लालू यादव ने नीतीश कुमार से इसलिए भी हाथ मिलाया था क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कांग्रेस सत्ता से बुरी तरह बाहर हो चुकी थी और आम चुनाव के बाद के चुनावों में भी भाजपा की जीत का मशाल धीमा पड़ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। अब न नीतीश कुमार में वो दम रह गया है और न ही लालू यादव को नीतीश की उस रूप में जरूरत बची है। लालू यादव का एकमात्र मिशन अब जितना जल्दी संभव हो सके बेटे तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने का है और अगर इस मामले में नीतीश कुमार कहीं मददगार बन पाते हैं तो उनकी सहायता से हाथ पीछे खींचने की नौबत नहीं आनी चाहिए।

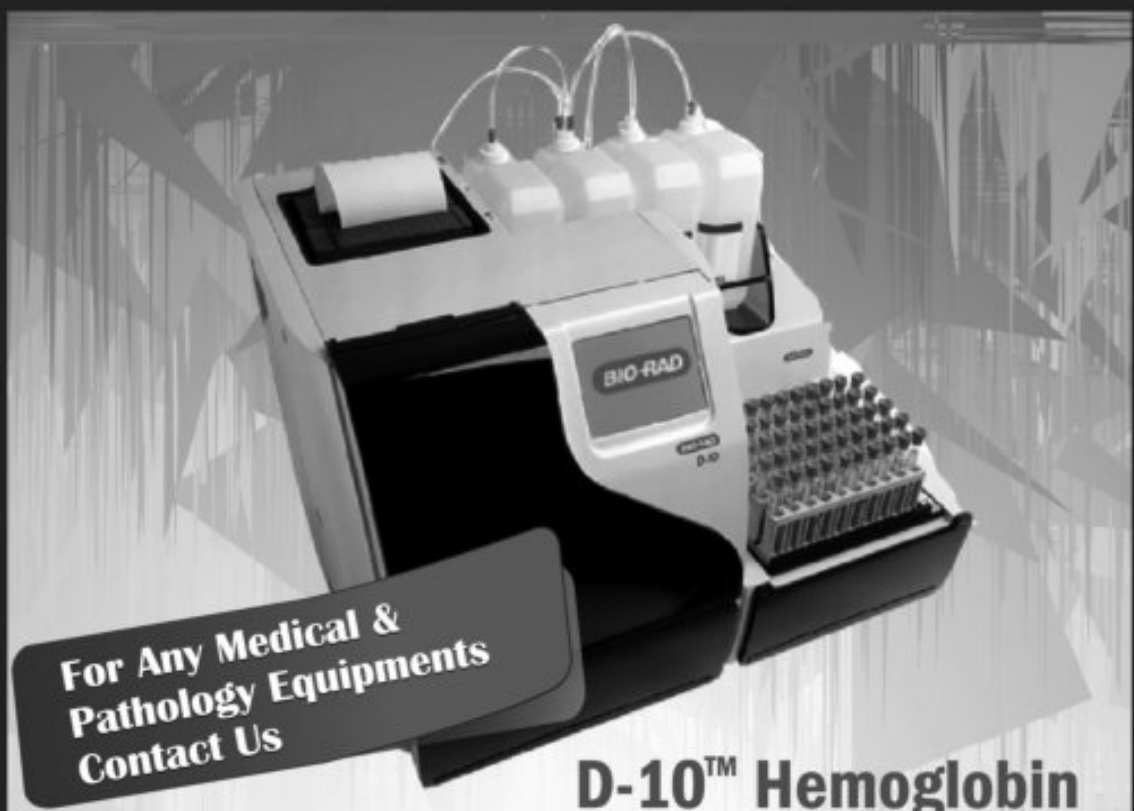

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; it's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

17/1, Sector-1 Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal (M.P.) India-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

अभी खत्म नहीं हुआ खेल

अफगानिस्तान में बदले माहौल और वहां चीन की बढ़ी पैठ ने भारत के लिए अगर नई चुनौतियां खड़ी की हैं, तो कई नई संभावनाएं भी जगाई हैं। एक तो अमेरिका के अचानक भाग खड़े होने से भारत को अमेरिका के पल्लू में बंधे रहने की मजबूरी से मुक्ति मिल गई है। नए समीकरणों में अब वह ईरान और रूस के साथ रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित कर सकता है, क्योंकि न केवल इन दोनों देशों के लिए, बल्कि खुद अमेरिका के लिए भी अब भारत का महत्व पहले से ज्यादा बढ़ने वाला है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद से भारत में एक खास वर्ग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह गया है। इनमें देसी कम्युनिस्ट सबसे आगे हैं, जो एशिया में चीन के बढ़ते दबदबे से आहलादित हैं। साथ ही इस्लामी जिहाद के पैरोकार, भाजपा तथा मोदी विरोधी पार्टियों के नेता और ऐसे छद्म-सेक्युलरिस्ट भी इनमें शामिल हैं, जिन्हें भारत के कमजोर होने का कोई मलाल नहीं, लेकिन मोदी सरकार के मुश्किल में पड़ने के आसार से उनकी बांछें खिल गई हैं। उन्हें अफगानिस्तान में अमेरिकी हार से भी ज्यादा खुशी इस उम्मीद में हो रही है कि अब मोदी सरकार दुनिया में अकेली पड़ जाएगी और उनका अपना एजेंडा चल निकलेगा। उधर, पाकिस्तान में भी उम्मीद जताई जाने लगी है कि अफगानिस्तान में फतह हासिल करने वाले इस्लामी लड़ाके अब कश्मीर में जिहाद शुरू करेंगे।

इन तमाम लोगों के अलावा विश्लेषकों का भी एक वर्ग ऐसा है, जिसका मानना है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी पलायन से भारत के लिए हालात मुश्किल हो गए हैं। सतही तौर पर उनकी दलीलें कुछ हद तक तर्कसंगत भी दिखती हैं, लेकिन ये ऐसे विश्लेषक हैं, जो न तो भारत की भीतरी जिजीविषा को जानते हैं और न ही उस इतिहास को समझना चाहते हैं जिसमें कठिनतम परिस्थितियों के बावजूद भारत बार-बार विजयी और पहले से ज्यादा ताकतवर होकर उभरता आया है। विश्लेषकों की इस बिरादरी को यह याद दिलाना जरूरी है कि 1965 और 1971 के युद्धों में पाकिस्तान को अमेरिका के खुले समर्थन के बावजूद भारत ने उसे बुरी तरह धूल चटाई थी।

वहीं, लद्दाख के नवीनतम अध्याय में चीनी राष्ट्रपति शी चिनपिंग और उनकी सेना सिवाय हाथ मलने और बार-बार अपने सेनापति बदलने के कुछ नहीं कर पा रही। यह बिरादरी मानकर चल रही है कि अफगानिस्तान में अमेरिका की जगह ले रहे चीन की उस योजना को नई गति मिलने जा रही है, जिसके तहत चीनी सरकार पाकिस्तान, रूस और ईरान के साथ मिलकर अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के 'क्वाड' के मुकाबले अपना नया 'क्वाड' बनाने को बेताब थी।

अफगानिस्तान में चीन की दादागिरी वाली उपस्थिति

कोढ़ में खाज का आलम यह है कि ईरान और रूस के बगल में बसे अफगानिस्तान में चीन की दादागिरी वाली उपस्थिति उनके लिए एक गंभीर चुनौती बनने जा रही है। रूस तो चीनी दुश्मनी का स्वाद कई बार चख चुका है। अब बारी है अमेरिका की नई क्षमताओं की, जो विदेशी भूमि पर अपने सैनिकों की शहादत के खौफ से पूरी तरह मुक्त हो गया है। अफगानिस्तान से निकलने के बाद अमेरिका को अपने पैसे, हथियारों और खुफिया तंत्र के बूते पर हर किसी का खेल बिगाड़ सकने की जो नई क्षमता मिल गई है, उसकी कल्पना चीन, रूस और ईरान को अभी से कर लेनी होगी। इस्लामिक आतंकवाद की उलझनों में चीन के उलझने की आशंका भी अब उसकी हेकड़ी को कम ही करेगी। खुद अफगानिस्तान के भीतर पिछले 20 साल में भारत ने जिस तरह से विकास और सहयोग के बूते अपनी दोस्ताना छवि बनाई है वह केवल आम अफगानों के ही मन में नहीं, बल्कि तालिबान के दिलों में भी भारत के लिए अपने दरवाजे खोलेगी। जहां तक भारत में मोदी-विरोध और भारत-विरोध के बुखार में तपे हुए लोगों की बात है तो उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि उनके सभी उकसावों के बावजूद मोदी सरकार अपने हजारों लोगों को सुरक्षित लाने में कामयाब रही है। इतने तनाव भरे माहौल में यह सफलता दिखाती है कि अफगानिस्तान में हुए परिवर्तनों ने अगर भारत के सामने कई चुनौतियां खड़ी की हैं तो एशिया में एक नई शक्ति बनकर उभरने के नए अवसर भी पैदा कर दिए हैं।

भारत के लिए निराशा भरी भविष्यवाणियां करने वालों का यह भी मानना है कि दक्षिण एशिया के नए समीकरणों में अब ईरान और रूस के साथ भारत के रिश्ते पहले की तरह भरोसेमंद नहीं रहेंगे, लेकिन अफगानिस्तान में अमेरिका की जगह चीन और पाकिस्तान की साझा उपस्थिति को भारत की हार बताने वाले लोगों की यह खुशी बहुत लंबी चलने वाली नहीं है। अफगानिस्तान में चीन की नई भूमिका चीन के लिए शायद उससे भी बड़ा जंजाल साबित होने जा रही है, जिसमें पहले सोवियत संघ और बाद में अमेरिका उलझ चुके हैं। फिलहाल तो चीन अफगानिस्तान के अकूत खनिज भंडारों और अपनी उपनिवेशवादी परियोजना बेल्ट एंड रोड के नए विस्तार की संभावनाओं से खुश दिख रहा है, लेकिन वह इस्लाम के उस कट्टरपंथी रूप से एकदम अनजान है, जो चीन के भीतर कम्युनिस्ट शासन और तानाशाही व्यवस्था के लिए भयंकर खतरा बनने वाला है।

चीनी नेता यह भूल रहे हैं कि 1949 में छोटी-सी आबादी वाले मुस्लिम देश ईस्ट-तुर्किस्तान (चीनी नाम शिनजियांग) पर कब्जा करने के 72 साल बाद भी वे उसे हजम नहीं कर पाए और शिनजियांग उनके लिए आज भी भारी सिरदर्द बना हुआ है। चीन को बहुत जल्द पता चल जाएगा कि भ्रष्ट और अक्खड़ तालिबान नेताओं की एक जमात को साध लेने के बाद भी वह शिनजियांग से एकदम सटे हुए अफगानिस्तान में इस्लामी आतंकवादी संगठनों को कभी पालतू नहीं बना सकता है। इतिहास बताता है कि ये संगठन खुद को एक-दूसरे से ज्यादा शुद्ध मुस्लिम सिद्ध करने की होड़ में समूचे शिनजियांग को आग के शोले में बदलने की हैसियत रखते हैं। उधर, पाकिस्तान में कुछ लोग अभी से मानने लगे हैं कि अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद इस्लामी जिहाद जल्द ही पाकिस्तान में भी जोर पकड़ेगी। इससे रूस और ईरान के सामने बड़ी चिंता खड़ी हो गई है। उनकी देहरी पर कट्टर और हिंसक इस्लाम की नई मौजूदगी से उनके आंतरिक समीकरण गड़बड़ाने का खतरा पैदा हो गया है।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

विश्व में कोरोना संक्रमण फैले 2 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन विश्व के विकसित देश अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा और चीन आदि आज भी इस महामारी की चपेट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा में तो मौत के मामले में भी तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं कोरोना के नए-नए वैरिएंट महामारी को और बढ़ा रहे हैं।

नियंत्रण के बाहर हो रहा कोरोना

भारत में स्थिति अभी नियंत्रण में

अमेरिका में मौत संबंधी आंकड़ों को लेकर बेहद स्पष्टता है। जांच से पहले कोरोना के लक्षण होने पर अगर किसी व्यक्ति की मौत हो रही है तो उसे कोरोना से मौत की श्रेणी में शामिल किया जा रहा है। अमेरिका के अलग-अलग प्रांत में सरकारें भी अलग हैं। कोरोना नियमों को भी लोग नहीं मान रहे। वैक्सीन को लेकर भी कुछ लोगों के बीच में विरोध है। जिस कारण वहां पर मौत अधिक हो रही है। लेकिन भारत में स्थिति अभी नियंत्रण में है। वायरस की आर वैल्यू घटकर एक फीसदी से कम हो गई है। लोग टीका लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं।

अमेरिका में कोरोना वायरस का प्रकोप एक बार फिर तेजी से फैल रहा है। स्थिति यह है कि मार्च के बाद से पहली बार पिछले कुछ दिनों से रोज औसतन 1,900 से अधिक मरीजों की मौत हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह संक्रमण एक अलग समूह यानी टीके की खुराक न लेने वाले 7.1 करोड़ अमेरिकियों को अपना निशाना बना रहा है।

देश के राष्ट्रपति जो बाइडन कोविड-19 की इस जानलेवा लहर से निपटने में मदद के लिए लोगों से घर पर संक्रमण की जांच करने का अनुरोध कर रहे हैं। महामारी के कारण अस्पताल क्षमता से अधिक भरे पड़े हैं और देशभर में स्कूलों के बंद होने का खतरा पैदा हो गया है। जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक, अमेरिका की करीब 64 प्रतिशत आबादी ने कोविड-19 रोधी टीके की कम से कम एक खुराक ले ली है। पिछले दो हफ्तों में हर दिन औसतन जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 40 प्रतिशत तक बढ़ गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अस्पताल में भर्ती होने वाले और जान गंवाने वाले लोगों की बड़ी तादाद टीका न लगवाने वाले लोगों की है। स्प्रिंगफील्ड-ब्रैनसन इलाके में कॉक्सहेल्थ अस्पताल में एक हफ्ते में ही 22 लोगों की मौत हो गई। पश्चिमी वर्जीनिया में सितंबर के पहले तीन हफ्तों में 340 लोगों की मौत हो चुकी है। जॉर्जिया में हर दिन 125 मरीज जान गंवा रहे हैं, जो कैलिफोर्निया या किसी अन्य घनी आबादी वाले राज्य से अधिक है।

अमेरिका के कई हिस्सों में दवा की दुकानों में जांच किट खत्म होती दिखाई दे रही हैं। दवा निर्माताओं ने आगाह किया कि इसका उत्पादन बढ़ाने में उन्हें हफ्तों का वक्त लगेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मियों के बाद से जांच की कम होती भूमिका, संक्रमण के कम होते मामलों और टीकाकरण की बढ़ती दर ने लोगों को लापरवाह बना दिया। साथ ही स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह सलाह दी कि टीका लगवा चुके लोग जांच से बच सकते हैं। अधिकारियों ने डेल्टा स्वरूप के कारण संक्रमण और मौत के मामले बढ़ने पर इस सलाह को वापस ले लिया था।

ब्राजील में लंबे समय बाद मौतों के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है। देश में गत दिनों 24 घंटे में 485 लोगों की मौत कोरोना वायरस महामारी की वजह से हुई है। यह अब तक की सबसे कम संख्या हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गत दिनों बताया कि टीकाकरण में लगातार वृद्धि की वजह से लंबे वक्त के बाद मौत के मामले कम हुए हैं। मंत्रालय के अनुसार, अप्रैल में रोज 3,000 मौतों की अपेक्षा पिछले 14 दिनों से औसतन 519 मौत के मामले सामने आ रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 485 ताजा मौतों के बाद कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,91,440 हो गई है। वहीं, मंत्रालय ने कहा कि ब्राजील में संक्रमण के नए मामले 11,455 दर्ज किए गए, लेकिन सेरा राज्य ने कहा कि उसे अपने डेटाबेस को सही करना होगा, जिससे उसके मामले की संख्या 12,028 कम हो गई, जिससे कुल मामले 2,12,47,094 पहुंच गए हैं। मालूम हो कि ब्राजील संक्रमितों के मामले में तीसरे जबकि मौतों के मामले में दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। संक्रमण के मामलों में अमेरिका और भारत ब्राजील से ऊपर है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूरोपीय देशों में कोरोना वैक्सीनेशन की धीमी पड़ी रफ्तार पर गंभीर चिंता जाहिर की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह आशंका भी जाहिर की है कि इस साल 1 दिसंबर तक यूरोप में कोरोना की वजह से 2 लाख 36 हजार लोगों की मौत भी हो सकती है। बता दें कि इस वक्त यूरोपीय देशों में कोरोना के डेल्टा वैरिएंट ने कहर मचाया हुआ है। यूरोप में वैक्सीनेशन की रफ्तार में भी कमी देखी गई है। हालांकि इससे पहले तक विश्व स्वास्थ्य संगठन गरीब देशों में वैक्सीनेशन को लेकर चिंतित रहा है। यही कारण है कि कुछ यूरोपीय देशों की तरफ से बूस्टर डोज की शुरुआत को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनिच्छा जाहिर की थी।

वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन की यूरोप शाखा के प्रमुख ने कहा है कि वह अमेरिकी सरकार के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ की इस बात से सहमत हैं कि कोविड-19 रोधी टीके की तीसरी खुराक अतिसंवेदनशील लोगों को संक्रमण से बचाने में सहायता कर सकती है। डॉ. हंस क्लुगे ने संक्रमण के अधिक प्रसार को बेहद चिंताजनक बताते हुए कहा कि डब्ल्यूएचओ यूरोप क्षेत्र में शामिल 53 में से 33 देशों में पिछले एक सप्ताह से ज्यादा समय में मामलों में 10 प्रतिशत या इससे अधिक की वृद्धि हुई है।

● **कुमार विनोद**

ANU SALES
CORPORATION
R1+S Cycle 17
R1+S Cycle 17
R2 Cycle 1
R2 Cycle 1
R1+S Cycle 18
R1+S Cycle 18
R2 Cycle 2
When time matters,
Real 200 t/h throughput
Even with double reagent reactions, the analyzer keeps its speed. Up to 4 volumes can be handled in every cycle.
1 2 3 • 17 18 19 20 • 33 34 35 36 37 • 45 46
R1+S L1 R2 L2 WS1 WS2
Dispensation
Aspiration
We Deal in Pathology
& Medical Equipment
BA200
BioSystems
The Highest Flexibility
Add : Ground Floor, 17/1, Shanti Niketan
Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
9329556524, 9329556530
Email : ascbhopal@gmail.com

जिम्मेदारी

जब से नई बहू घर में आई थी, गाहेबगाहे अलमारी से पैसे गायब होने लगे थे। रमा को अपनी नई बहू पर शक तो था लेकिन बिना सबूत के वह उसपर आक्षेप भी कैसे लगाती? वह चाहकर भी अपनी बहू से कुछ कह नहीं पा रही थी। महीने के आखिर में उसे घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता, बचत की बात तो बहुत दूर थी।

कई बार बहू को फिजूलखर्ची के लिए टोक भी चुकी थी और बेटे से भी कह चुकी थी लेकिन नतीजा वही 'ढाक के तीन पात'!

रमा ने काफी सोच समझकर एक दिन बहू को बुलाया और उसे समझाते हुए कहा, बहू! नया जमाना आ गया है। अब खरीदारी के तौर तरीके बदल गए हैं जो मेरे लिए तो टेढ़ी खीर समान ही हैं, सो अब आज से तुम ही संभालो पूरे घर की जिम्मेदारी। मेरा क्या है, मुझे जो भी मिलेगा खा लूंगी और राम-राम कर लूंगी! अब अलमारी से पैसों की चोरी और बहू की फिजूलखर्ची भी रुक गई थी।

- राजकुमार कांदु

भाभी-मां

पिता के देहावसान के बाद संजय की स्थिति बद से बदतर हो गई थी। घर-परिवार, गली-मुहल्ले व सगे-संबंधियों में अपनी शराबखोरी के चलते वह सबकी नजरों से गिर हो चुका था। जब बड़े भाई निहाल को ही वह फूटी आंख नहीं सुहाता; तो भाभी अरूणा का पुछो ही मत। यह भी तो सच था कि संजय सुबह घर से निकल जाता, दिनभर कहां रहता, क्या करता; किसी को पता नहीं। देर रात तक लड़खड़ाते कदमों से वह घर आता; और फिर बक-बक शुरू। निहाल ने तो बात करना ही बंद कर दिया था उसके साथ। गालियों के शब्दकोश में ऐसी कोई गाली ही नहीं बची थी, अरूणा ने संजय के लिए उपयोग न किया हो। अब बस बच गई तो मां देविका। संजय तो अब भी 'संजू' ही था छुटपनवाला मां देविका के लिए।

आज रात तो हद हो गई। सब के खाना खाने के बाद अरूणा ने कुकर की बची दाल में पानी डाल दी। बड़बड़ाने लगी- 'सब्जी नहीं बची तो मैं क्या करूं, कुछ भी खाए, मेरो को क्या है? मैं उसकी नौकरानी थोड़ी हूं कि उसके लिए और सब्जी बनाती रहूं।' सब के सब सो गए।

देविका की आंखों से नींद गायब थी। दरवाजे को खुला रखा था उसने। बार-बार बाहर झांककर देखती। पर पता नहीं देविका की नींद कैसे झूप-से लग गई। अचानक आंख खुली; देखती है- संजय थाली में रखा दाल-भात खा रहा था। बगल में कटोरी भर सब्जी थी।

अब देविका को खाली पेट ही नींद लग गई।

- टीकेश्वर सिन्हा 'गब्दीवाला'

मत रोको गंगा की धारा

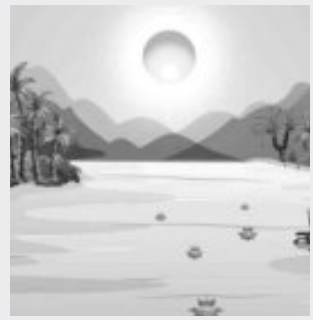

मत रोको गंगा की धारा,
अविरल बहने दो।
उर की सारी पीड़ा खुशियां,
कल-कल कहने दो।
केवल नदी नहीं है गंगा,
अपनी थाती है।
युग-युग से पुरखों की
पढ़ती आई पाती है।
घाटों में इतिहास सुरक्षित,
हलचल रहने दो।
संस्कृति की संवाहक गंगा,
जीवन का राग भरे।
सृजन प्रलय के तटबंध बीच,
बहती आग भरे।
सुरसरि है शुभ श्वास हमारी,
कलरव करने दो।।
पोषण मुक्ति प्रदाता गंगा,
जन विश्वास लिए।
उर भरती हैं उत्साह प्रबल,
नव आकाश लिए।
वक्षस्थल पर वार मशीनी,
अब मत सहने दो।।

- प्रमोद दीक्षित मलय

भारतीय महिला हॉकी टीम का सम्मान

खेलों के महाकुंभ टोक्यो ओलिंपिक में पहली बार चौथे नंबर पर रही भारतीय महिला हॉकी टीम का राजधानी भोपाल के मिंटो हाल में सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी 19 खिलाड़ियों को 31-31 लाख रुपए की राशि से पुरस्कृत किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत की महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया है। इन बेटियों ने देश के लोगों का दिल जीत लिया। देश के दिल मप्र में इन्हें सम्मानित कर हम अपने कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। अगले ओलपिंक में ये बेटियां जरूर गोल्ड मेडल जीतकर आएंगी। इस दौरान खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि मप्र में हॉकी के चार नए एस्ट्रोटर्फ लगेंगे। अभी 11 मौजूद हैं। ओडिशा के बाद मप्र हॉकी का हब बनेगा। कार्यक्रम में हॉकी टीम की कैप्टन रानी ने कहा कि शिवराज सिंह जैसे मुख्यमंत्री हर राज्य में होंगे तो लड़कियां स्पोर्ट्स में आगे आएंगी। इस अवसर पर महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, सविता पूनिया, दीप ग्रेस एक्का, निशा, गुरजीत कौर, सलीमा टेटे, उदिता, मोनिका, निक्की प्रधान, नेहा, पी. सुशीला चानू, वंदना कटारिया, नवनीत कौर, नवजोत कौर, शर्मिला देवी, लालरेम सियामी, ई. रजनी, रीना खोकर और नमिता टोप्पो को सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मप्र में खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए लगातार कार्य हो रहा है। महिला और पुरूष खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के अधिकाधिक अवसर दिए जा रहे हैं। इसके लिए आवश्यक सुविधाएं जुटाई गईं हैं। महिला हॉकी खिलाड़ियों की आर्थिक दिक्कत को दूर करने की पहल वर्ष 2010 में मप्र से हुई। इसके बाद हॉकी अकादमी को सशक्त किया गया। आज यह देश की श्रेष्ठ हॉकी अकादमियों में से एक है। मुख्यमंत्री ने मप्र सरकार की तरफ से भारतीय महिला हॉकी टीम को सम्मानित किए जाने के निर्णय की पृष्ठभूमि के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि जब ओलिम्पिक के सेमीफाइनल मैच में बहुत अच्छा खेलने के बाद भी महिला हॉकी खिलाड़ियों को विजय नहीं मिली और उनकी आंख में आंसू दिखे थे तभी मैंने संकल्प लिया था कि टीम के सदस्यों को भोपाल में सम्मानित किया जाएगा। इसके पहले भारतीय पुरूष हॉकी टीम के प्रतिभाशाली खिलाड़ी विवेक सागर को एक करोड़ रूपए की सम्मान राशि, पुलिस उप अधीक्षक पद पर नियुक्ति और मकान देने का कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय भोपाल को हॉकी की नर्सरी कहा जाता था। यहां से देश को अनेक खिलाड़ी मिले हैं। परंतु कुछ सालों से हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। टोक्यो ओलिम्पिक ने फिर से हॉकी को पुर्नजीवित कर दिया है। मप्र ने न सिर्फ आर्थिक और विकास के क्षेत्र में बीमारू राज्य का तमगा हटाया है बल्कि खेल क्षेत्र में भी मप्र किसी से पीछे नहीं है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय समाज को बेटियों की भूमिका पर गर्व करना चाहिए। निश्चित ही बेटियां प्रतिभा के मामले में बेटों के मुकाबले कहीं भी पीछे नहीं हैं। मप्र में पंचायत राज संस्थाओं और पुलिस में महिलाओं का आरक्षण प्रतिशत बढ़ाया गया है। मप्र में बेटियों और महिलाओं से कोई भेदभाव नहीं होगा, यह राज्य सरकार का संकल्प है। हमारी आधी आबादी आगे बढ़ेगी तो निश्चित ही देश भी आगे बढ़ेगा। मप्र ने बेटियों को लखपति बनाने वाली लाड़ली लक्ष्मी योजना प्रारंभ की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल बहुत सामान्य परिवार से आती हैं। उन्होंने टूटी हॉकी से खेला, प्रतिभा का विकास किया। उप कप्तान सविता भी कठिनाइयों से निकलीं, खेल को निखारा। मोनिका के पिता उसे कुश्ती में लाना चाहते थे। गुरजीत कौर और निक्की प्रधान साधारण किसान परिवारों की सदस्य हैं। सलीमा तो नक्सल प्रभावित ग्राम में रहती थी। बांस की खपच्चियों से खेलीं और भारतीय टीम की सदस्य बन गईं। वंदना और सुशीला ने ग्वालियर में कोचिंग ली। वंदना फॉरवर्ड और सुशीला मिड फील्डर पोजिशन पर खेलती हैं। इसी तरह नेहा और उदिता हरियाणा से मिड फील्डर और डिफेंडर की पॉजिशन पर आई हैं।

● आशीष नेमा

जन निजी भागीदारी से सतगढ़ी में खेल ग्राम का होगा निर्माण

मंत्रिपरिषद ने ग्राम सतगढ़ी भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सर्व सुविधायुक्त खेल ग्राम का जन निजी भागीदारी के माध्यम से निर्माण का निर्णय लिया। ग्राम सतगढ़ी जिला भोपाल की कुल भूमि 69.91 हैक्टेयर (172 एकड़) के 50 एकड़ भूमि पर कंसेशनेयर मेसर्स एस्सेल इंफ्राप्रोजेक्टस लिमिटेड मुंबई द्वारा 200 करोड़ रुपए की लागत से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तथा शेष 122 एकड़ भूमि पर रीयल स्टेट विकास के लिए जन निजी भागीदारी योजनांतर्गत 10 सितंबर 2008 को कंसेशन एग्रीमेंट एवं 4 दिसंबर 2008 को लीजडीड का निष्पादन किया गया। कंसेशनेयर द्वारा कंसेशन की शर्तों अनुसार परियोजना का क्रियान्वयन नहीं करने तथा प्रीमियम की पूर्ण राशि यथासमय जमा नहीं करने के कारण परफॉरमेंस सिक्योरिटी के 20 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी राजसात करने की कार्यवाही के संदर्भ में लंबे समय से प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रिया में होने के कारण मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि कंसेशनेयर द्वारा उच्च न्यायालय में लंबित अपील वापिस लेने के बाद परफारमेंस सिक्योरिटी के 20 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी वापिस की जाए।

केवल 30 रुपए लेकर मुंबई आए थे देव आनंद, एक साल तक की क्लर्क की नौकरी, अशोक कुमार ने फिल्मों में बना दिया हीरो और फिर बन गए सुपरस्टार

झुक-झुक कर संवाद अदायगी का खास अंदाज हो, या फिर फीमेल फैन्स की बात...देव आनंद अपने समकालीन एक्टरों से हमेशा अलग थे।

बॉलीवुड में कितने ही हीरो आए और चले गए, लेकिन ऐसे कुछेक ही हैं, जिनके किस्सों का जिक्र किए बिना हिंदी फिल्मों का इतिहास अधूरा रह जाएगा। देव आनंद भी ऐसे ही सितारों में से एक थे। 26 सितंबर 1923 में उनका जन्म पंजाब के गुरदासपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था।

अपने दौर में रूमानियत और फैशन आइकन रहे देव आनंद को लेकर यूं तो कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन इन सबसे खास उनके काले कोट पहनने से जुड़े किस्से हैं। देव आनंद ने एक दौर में व्हाइट शर्ट और ब्लैक कोट को इतना पॉपुलर कर दिया था कि लोग उन्हें कॉपी करने लगे। फिर एक दौर वह भी आया जब देव आनंद पर पब्लिक प्लेसेस पर काला कोट पहनने पर बैन लगा दिया गया। हिंदी सिनेमा में तकरीबन छह दशक तक दर्शकों पर अपने हुनर, अदाकारी और रूमानियत का जादू बिखेरने वाले सदाबहार अभिनेता देव आनंद को एक्टर बनने के लिए कई पापड़ बेलने पड़े। दिलचस्प बात यह है कि जब देव आनंद मुंबई पहुंचे तब उनके पास मात्र 30 रुपए थे।

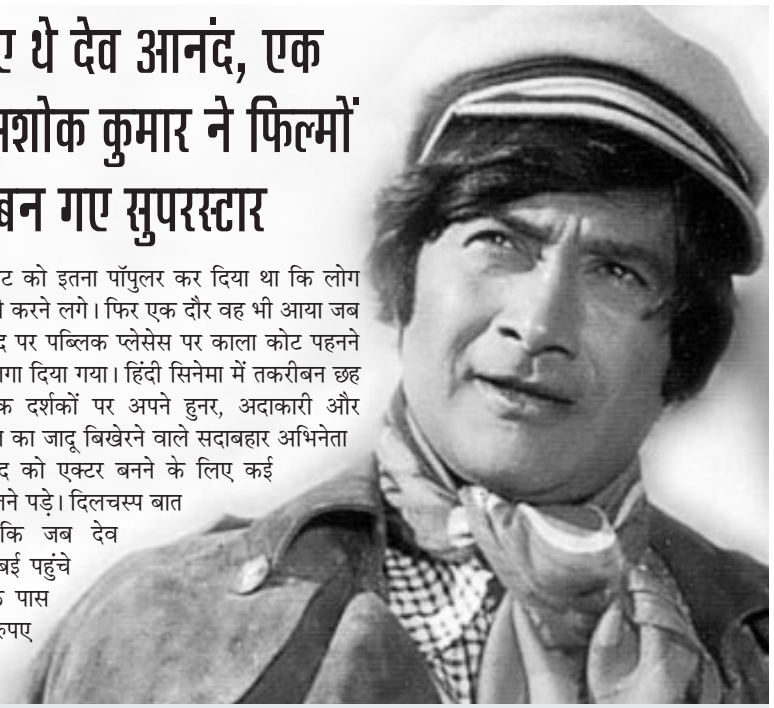

मिलिट्री सेंसर ऑफिस में मिली नौकरी... *1943 में अपने सपनों को साकार करने के लिए जब वह मुंबई पहुंचे। तब उनके पास मात्र 30 रुपए थे और रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। देव आनंद ने मुंबई पहुंचकर रेलवे स्टेशन के समीप ही एक सस्ते से होटल में कमरा किराए पर लिया। उस कमरे में उनके साथ तीन अन्य लोग भी रहते थे जो उनकी तरह ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। काफी दिन यूं ही गुजर गए। उनके पास पैसा खत्म हो रहा था और तब उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें मुंबई में रहना है तो नौकरी करनी ही पड़ेगी। काफी मशक्कत के बाद उन्हें मिलिट्री सेंसर ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिल गई। यहां उन्हें सैनिकों की चिट्ठियों को उनके परिवार के लोगों को पढ़कर सुनाना होता था।*

पहली शादी टूटने के बाद परमीत सेठी में अर्चना पूरन सिंह को मिला हमसफर, शादी करने के लिए आधी रात को पंडित ढूंढने निकल गए थे कपल

इन दिनों अपनी दमदार हंसी से लाफ्टर क्रिएट करने वालीं अर्चना पूरन सिंह का नाम एक जमाने की सबसे बोल्ड एक्ट्रेसेस में शामिल हो चुका है। अर्चना सबसे पहले निकाह फिल्म के गाने में महज 10 सेकेंड के लिए नजर आई थीं। इसके बाद उन्होंने 1987 की फिल्म अभिषेक से अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी, हालांकि चंद फिल्मों के बाद ही उन्हें साइड रोल ऑफर होने लगे। फिल्मी कैरियर के अलावा अर्चना की लव लाइफ भी काफी दिलचस्प रही है। अर्चना पूरन सिंह पहली नाकाम शादी के बाद बुरी तरह टूट चुकी थीं। एक्ट्रेस ने फैसला कर लिया था कि वो कभी शादी नहीं करेंगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अर्चना और परमीत की खूबसूरत लव स्टोरी की शुरुआत एक इवेंट के दौरान हुई थी। एक दिन अचानक ही कपल ने सोच लिया कि उन्हें शादी करनी है और दोनों आधी रात को ही शादी करवाने वाले पंडित की तलाश में निकल गए। इस बात का खुलासा खुद परमीत ने द कपिल शर्मा शो के दौरान किया था।

वीरगति के एक सीन में घबरा गई थीं दिव्या दत्ता, सलमान खान ने की थी मदद, दिल्ली 6 में एक्टिंग देख ऋषि कपूर ने बजाई थी सबके सामने ताली

नेशनल फिल्म अवॉर्ड विनर दिव्या दत्ता का जन्म 25 सितंबर 1977 को पंजाब के लुधियाना शहर में हुआ था। दिव्या के बारे में कहा जाता है कि वे जिस फिल्म में होती हैं, उस फिल्म का कद अपने आप बढ़ जाता है। दिव्या ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मां-बाप डॉक्टर थे, पर सुई देखकर मैं घबराती थी। बड़ी होकर साइकोलॉजी से डिग्री ली। बच्चन साहब की बहुत बड़ी फैन थी। उनकी फिल्में देखती थी। चार साल की थी, तब अपने पड़ोसियों के बच्चों को बुलाकर अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन का गाना खाई के पान बनारस वाला... गाया और उस पर डांस किया। बच्चों की तालियों की गड़गड़ाहट सुनकर बहुत अच्छा लगा। बच्चों को पार्टी दी। उस समय बहुत छोटी थी तो मुझे नहीं पता था कि एक्टर बनना चाहती थी कि नहीं, लेकिन जब डांस और एक्टिंग करती थी, तब खुश हो जाती थी। फिर तो कुदरत ने मेरे लिए एक मौका खोला और टैलेंट हंट में शामिल हुई और एक्टिंग लाइन में आ गई।

अब ज्ञान कौड़ियों के मोल बिकता है। कीमत अंकों की है, प्रमाणपत्र या डिग्री की है, योग्यता को कौन पूछता है। जुगाड़ का युग है। कॉम्पटीशन में जुगाड़ लगाकर लोग डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और न जाने क्या-क्या बन जाते हैं। अब तो सुना है कि प्रोफेसर भी जुगाड़ से बनने लगे हैं। प्राइमरी के सैकड़ों टीचर बीएड की नकली डिग्रियों से बन गए और निडर होकर ही तो बने।

हमें किसी का डर नहीं

वे जमाने चले गए ,जब हम डर-डर कर जीते थे। अब हम पूरी तरह से निडर हो गए हैं। अब हमें न पाप से डर है, न पुण्य की चिंता। जो करते हैं, मन की करते हैं। हमें क्या? कोई जिए या मरे! हम तो अपने और अपनों के लिए ही सब कुछ कर्म करते हैं। क्या सुकर्म, क्या कुकर्म, क्या अकर्म-इसकी चिंता पूरी तरह छोड़ ही दी है। सुना है पहले के मां-बाप अपनी संतान के भविष्य की चिंता में दिन-रात एक किए रहते थे, किन्तु हमारे मम्मी-डैडी कितने अच्छे हैं कि उन्होंने सब कुछ हमारे ऊपर ही छोड़ दिया है। कोई छोटी-सी गलती हो जाने पर देह की खाल तक छील दी जाती थी। बहुत मार पड़ती थी। अब हम कुछ भी करें, न कोई रोकने वाला है, न टोकने वाला। हम पूरी तरह निडर हैं।

अब ज्ञान कौड़ियों के मोल बिकता है। कीमत अंकों की है, प्रमाणपत्र या डिग्री की है, योग्यता को कौन पूछता है। जुगाड़ का युग है। कॉम्पटीशन में जुगाड़ लगाकर लोग डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और न जाने क्या-क्या बन जाते हैं। अब तो सुना है कि प्रोफेसर भी जुगाड़ से बनने लगे हैं। प्राइमरी के सैकड़ों टीचर बीएड की नकली डिग्रियों से बन गए और निडर होकर ही तो बने। लाखों कमाकर कोठियों में ऐश कर रहे हैं। ये अलग बात है कि जांच के डंडे ने सही रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया है। ये सब उनकी निडरता का ही परिणाम तो है। यहां पर तनिक गहराई में उतरने की आवश्यकता है। जिन-जिन निर्माताओं ने स्वयं कुलपति रजिस्ट्रार बनकर डिग्रियां जारी की होंगीं, वे भी तो निडर ही थे। कितने बोर्ड हैं जो शत-प्रतिशत अंक देकर छात्रों का भविष्य उज्ज्वल कराने में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। भले ही उन्हें अपना नाम और पता भी ठीक से लिखना नहीं आता हो। ये निडरता की पराकाष्ठा ही तो है। नियम, कानून, नैतिकता सब कुछ खूंटी पर टांगकर छोड़ दिया गया है। धन्य मेरे महान देश और उसके महान नागरिक!

अब पढ़ाई को ही ले लीजिए। परीक्षा में वे कभी नहीं कहते कि नकल मत करना। बल्कि कुछ मम्मियां और डैडी लोग तो न केवल गुरू जी से यह कहते देखे जाते हैं, सर आज बच्चे की परीक्षा है, ध्यान रखना। इस 'ध्यान रखने' के मतलब बहुत गहरे हैं। आप सब समझते हैं। ज्यादा खोलकर क्या-क्या कहा जाए! कुछ मम्मी-डैडी तो रात-रात भर मेहनत करके हमारी नकल सामग्री उतारते हैं, ताकि हम कक्ष-नरीक्षक की आंख में धूल झोंककर अपना काम शांति से कर सकें। हमारे उन गुरुजनों का तो कहना ही क्या! जो खुद आंख बचाकर परीक्षा हॉल से किसी भी बहाने से पलायन कर जाते हैं। उन्हें भी किसी का डर नहीं। जब उन्हें नहीं, तो हमें ही क्यों हो? वे आखिर हमारे भविष्य निर्माता हैं। वे सीसीटीवी कैमरे के नीचे खड़े होकर बोल-बोल कर पूरी मदद करते हैं। उधर हमारे पूज्य हितैषी मम्मी-डैडी की बात का भी तो ध्यान रखना है, वरना वे राह चलते न तो उन्हें नमस्ते करेंगे और नहीं चाय की दावत पर बुलाएंगे। अब तो हमारा इतना साहस बढ़ गया है कि सीना तानकर, कुर्सी पर कट्टा लेकर ठाठ से बैठते हैं। कभी-कभी तो कुछ ज्यादा आदर्शवादी टीचर ऐसे आ जाते हैं कि गर्दन भी नहीं घुमाने देते। उनकी गर्दन का इंतजाम भी हमें करके घर से ही चलना पड़ता है। परीक्षा की पूरी तैयारी होनी चाहिए न! आखिर परीक्षा तो परीक्षा है न!!

अब जमाना कितना बदल गया है कि हमें या किसी को पुलिस का भी डर नहीं रहा। आप आए दिन टीवी अखबारों, सोशल मीडिया पर देखते हैं कि चालान करने, हेलमेट या मास्क नहीं लगाने पर रोकने पर बिना आवश्यक कागजात रखने पर रोकने-टोकने पर पुलिस को भी पीट दिया जाता है। जब आम आदमी की ये दशा है तो चोर, उच्चके, गिरहकट, राहजन और डाकू सब निडर हो ही जाएंगे। बैंकों में दिन दहाड़े डकैतियां इसी निडरता के कारण ही तो हो रही हैं। कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जहां स्वयं बैंक मैनेजर ही बैंक में डाका डालते हुए पकड़े गए हैं।

आज का युग है कि आदमी केवल कानून की बात तो बड़ी लंबी-चौड़ी करता है, परन्तु उसका पालन कदापि नहीं करना चाहता। हम सब कानून का उल्लंघन करना अपनी शान समझते हैं। विशेष रूप से जो ऊंचे पदों पर आसीन हैं, यदि उन्होंने कानून का पालन भूल से भी कर लिया, तो समझिए उनकी नाक ही कट गई! वे अपने को कानून की परिधि से बाहर का मानकर चलते हैं। निर्भय होकर रिश्वत लेना, गबन करना, अपहरण करना आम हो गया है। आज के युग में डरपोक आदमी सही और सुरक्षित तरीके से जी नहीं सकता।

देश के धर्म के ठेकेदार पूर्णत: निर्भय होकर राजाओं जैसी विलासिता पूर्ण जिंदगी का भोग कर रहे हैं। कुछ कारागारों की शोभा बढ़ा रहे हैं, तो कुछ अभी परदे में क्या कर रहे हैं, ये परमात्मा जानता होगा या वे स्वयं। अकूत धन-दौलत, नव यौवनाओं का अहर्निश साथ, रहस्य पूर्ण महलों का निवास, अंधी जनता का अंधा विश्वास इन्हें निडर बनाने में आग में घृत का काम कर रहा है।

मेरा देश पहले से ही महान था, अब तो हम और भी निडर होकर उसे महान बनाने के लिए कटिबद्ध, वचनबद्ध और दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। पाप पुण्य कुछ भी नहीं होता। इसलिए निडर होकर अपना उल्लू सीधा करना हम सबका मन्तव्य है, और होना भी चाहिए, जो आज सारे वतावरण, दर-दर, घर-घर, गली-गली, गांव-गांव, नगर-नगर और सम्पूर्ण देश में व्याप्त है। किसी न किसी रूप में उसकी महक सबके ही नथुनों में रस-बस गई है। हमारा एक ही नारा है...

निडर रहो, कुछ भी करो।
जरूरत पड़े, तो मारो मरो।।
हर हाल में अपना घर भरो।
कोई तरे या नहीं, तुम तो तरो।

● **डॉ. भगवत स्वरूप 'शुभम'**

PRESENTING

Our new corporate identity

JKCement

A SOLID LEGACY OF TRUST

The trunk spreads wide
The branches reach high
Spurring us on
To reach for the sky.
'Y' for our founding father
Late Shri Yadupati Singhania ji

Energy and sustainability
Define our Abundance Tree.
Green is our vision
Grey, our foundation
Blue is the limitless sky of opportunities
That inspires our transition.

JK Cement Ltd.
Registered Office : Kamla Tower, Kanpur-208001, Uttar Pradesh. Tel : 0512 2371478-81.
Corporate Office : Padam Tower, 19, DDA Community Centre, Okhla, Phase - 1
New Delhi - 110020. Tel.: 011 - 49220000

www.jkcement.com

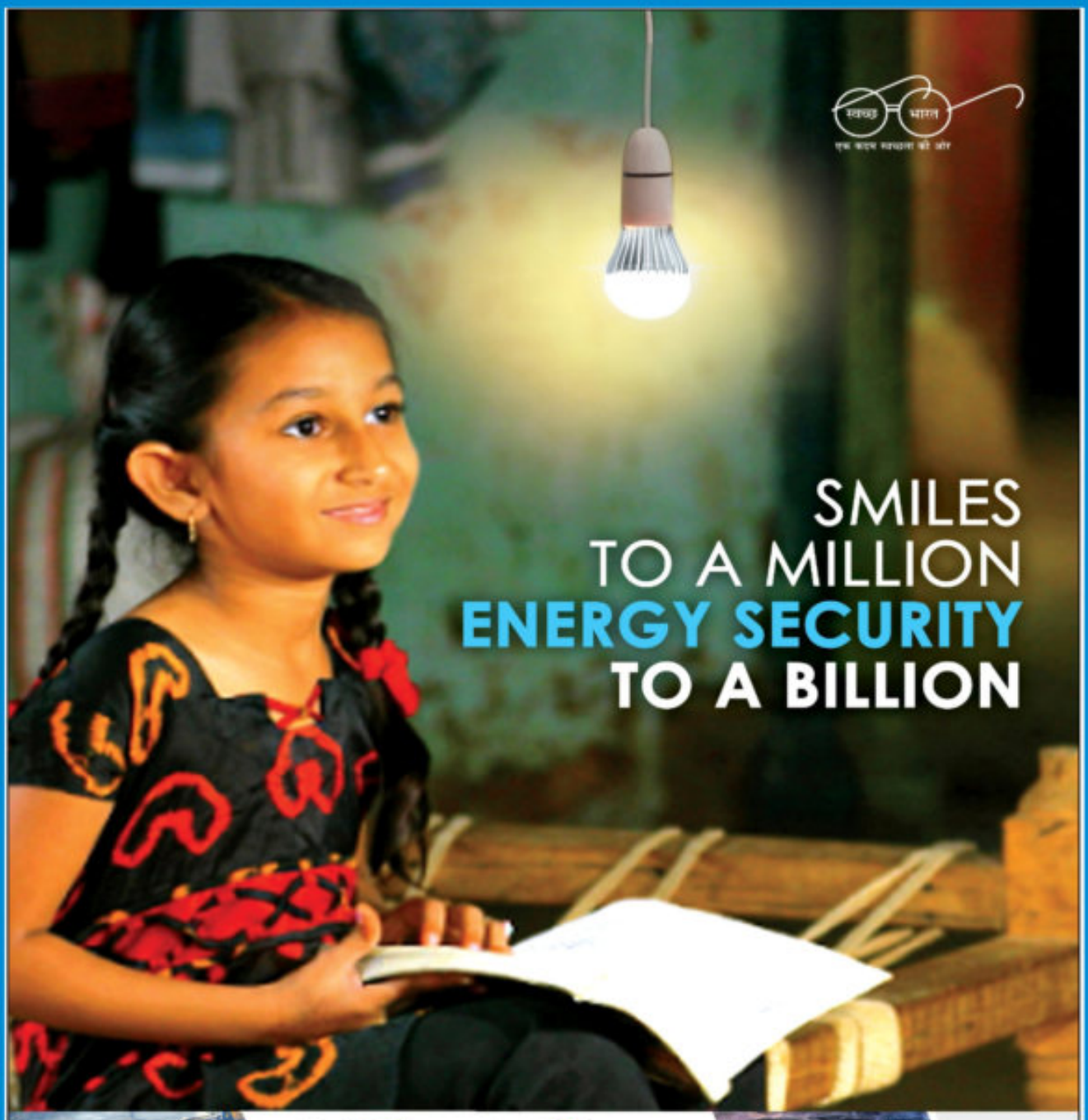

MAHANADI COALFIELDS LIMITED

(A Govt. of India Undertaking & Subsidiary of Coal India Limited)

Corporate Office: At/Po.- Jagruti Vihar, Burla, Sambalpur, Odisha-768 020

www.mahanadicoal.in | mahanadicoal | mahanadicoal